हिन्दुस्तान
1936

आयोगों का महत्व

बिहार में संप्रदाय और जाति के आधार पर गठित आयोगों में नियुक्ति स्वागतयोग्य है। सवर्ण आयोग का नाम बदलकर उच्च जाति आयोग करना और उसमें पूर्व मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता महाचंद्र सिंह की अध्यक्ष के रूप में पदस्थापना सबका ध्यान खींच रही है, तो आश्चर्य नहीं। बिहार में इस वर्ष विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों के मद्देनजर ऐसी सक्रियता स्वाभाविक है। ज्यादातर राज्यों में चुनाव से कुछ पहले ही ऐसे आयोगों को सक्रिय किया जाता है और इससे कुछ हद तक राजनीतिक लाभ की संभावना मानी जाती है। बहरहाल, उच्च जाति आयोग में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा तीन अन्य सदस्य भी बनाए गए हैं। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग में भी पदस्थापना की गई है, जिसमें शैलेंद्र कुमार को अध्यक्ष और सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसमें तीन सदस्य भी नियुक्त हुए हैं। इसके साथ ही, राज्य अल्पसंख्यक आयोग में पूर्व सांसद व जद-यू नेता गुलाम रसूल बलियावी को अध्यक्ष बनाया गया है। इन तीनों आयोगों में हुई नियुक्तियों के निहितार्थ को समझना कठिन नहीं है।

आम तौर पर यही माना जाता है कि ऐसे आयोग वास्तव में निर्धारित वर्ग के बीच संवाद बनाए रखने का काम करते हैं। संवाद से जो अच्छी बातें निकलती हैं, उन्हें सिफारिश के तौर पर ये सरकार तक पहुंचाते हैं, ताकि सरकार उस वर्ग के अनुकूल नीतियां बना सके। वास्तव में, ऐसे आयोग संवाद का विशेष जरिया हैं और अनेक राज्यों में ऐसे आयोगों से लोगों के जीवन में बदलाव आए हैं। इन आयोगों की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यह सुनिश्चित रहना चाहिए कि ऐसे आयोगों में पद खाली न रहें, ताकि इनका सतत लाभ समाज को मिलता रहे। ऐसे राज्य भी हैं, जहां नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे आयोगों में पदस्थ कर दिया जाता है, और उन नेताओं को कुछ सुविधाएं हासिल हो जाती हैं। यह उम्मीद तो करनी ही चाहिए कि ऐसे आयोगों के जरिये राजनीति न हो, बल्कि समाज के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। ऐसे आयोगों में वाकई योग्य या समर्पित नेताओं की आवश्यकता रहती है। देश में ऐसे उदाहरण हैं, जहां योग्य नेतृत्व में आयोगों ने बेहतर काम किए हैं। बेशक, यह समीक्षा या चर्चा होगी कि बिहार सरकार ने चुनाव के मद्देनजर ये नियुक्तियां की हैं और इनका सत्तारूढ़ गठबंधन को कमोबेश लाभ भी होगा।

उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसे आयोगों के जरिये राजनीति न हो, बल्कि समाज के विकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अतः इनमें समर्पित नेतृत्व की जरूरत है।

ध्यान रहे, जब हर जाति में अमीर हैं और गरीब भी, तब आयोगों की प्राथमिकता गरीब होने चाहिए, तभी समाज का ज्यादा भला होगा। जैसे, अनुसूचित जातियों के अंदर भी जो जातियां विकास की दौड़ में पिछड़ गई हैं, उनके विकास को अगर बल मिल सके, तो अनुसूचित जाति आयोग की सार्थकता सिद्ध होगी। ठीक इसी तरह से अल्पसंख्यक आयोग को देखना चाहिए कि अल्पसंख्यकों में भी जो समूह पिछड़ रहे हैं, उन्हें बल मिले। इन आयोगों को राजनीति और चुनावों से परे रहकर देखना चाहिए। सबसे पहले सरकारों का नजरिया बदलना चाहिए। आयोगों का लक्ष्य राजनीतिक लाभ नहीं, बल्कि सामाजिक लाभ होना चाहिए। अनेक राज्यों में यह देखा गया है कि आयोगों के पद खाली रहते हैं, क्या योग्य उम्मीदवारों की कमी है? क्या पदों को स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञों से भरा जा सकता है? बदलते दौर और जागरूक हो रही जातियों के साथ आयोगों में ऐसे विशेषज्ञों की जरूरत बढ़ती जाएगी, जो समाज को केवल सामाजिक चश्मे से देखेंगे, सियासी चश्मे से नहीं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 31 मई, 1950

फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारत

अंग्रेजी सत्ता भारत पर उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक छाई हुई थी, किन्तु उसे भारतीयों की दुर्दमनीय राष्ट्रीय भावना के आगे झुकना पड़ा। उसने आखिर भारत की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया और यहां से विदा ले ली। उसका वह कार्य राजनीतिज्ञतापूर्ण था और उसी का यह परिणाम है कि ब्रिटेन और भारत के बीच आज मित्रता का सम्बन्ध कायम है और इस देश के लोग अंग्रेजों के प्रति अपनी कटुता की पुरानी भावना को प्रायः भूल गये हैं। किन्तु यह कितने खेद की बात है कि फ्रांस और पुर्तगाल भारत की धरती पर अब भी कब्जा जमाये बैठे हैं और उस पर से हटने के कोई लक्षण प्रकट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन के उदाहरण से कोई सबक नहीं सीखा मालूम होता है और उनकी यह भीतरी इच्छा नजर आती है कि अधिक से अधिक समय तक भारत में अपने पांव जमाये रखें। भारत जब स्वयं अंग्रेजों के आधीन था, तब फ्रांस और पुर्तगाल निश्चिन्त होकर यहां जमे रह सकते थे, किन्तु जब प्रायः समस्त भारत स्वतन्त्र हो गया है, तो विदेशी शासन के ये धब्बे फ्रांसीसी और पुर्तगाली बस्तियों के रूप में जीवित नहीं रह सकते।

फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारत में रहने वालों की इच्छा के सम्बन्ध में किसी को कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए। चन्द्रनगर की फ्रांसीसी बस्ती का जनमत पिछले दिनों मालूम किया गया था, और उसने प्रायः एक स्वर से भारत के साथ मिलने का निर्णय किया था। उसके अनुसार चन्द्रनगर का भारत में समावेश हो चुका है। जो तरीका चन्द्रनगर के बारे में अख्तियार किया गया, उसी का दक्षिण भारत की अन्य फ्रांसीसी बस्तियों में भी अनुसरण किया जाये, यह भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच बहुत पहले ही तय हो चुका है। जनमत लेने की एक तिथि निश्चित भी हुई थी, किन्तु उसे अनिश्चित-काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब कोई नहीं कह सकता कि जनमत कब लिया जायेगा और उसके लिए कोई तैयारी की जा रही है अथवा नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विदेश मंत्री डा. राजकुमार इस समय पांडिचेरी गये हुए हैं, जो कि दक्षिण भारत में मुख्य फ्रांसीसी बस्ती है। उन्होंने वहां की मौजूदा स्थिति के बारे में एक मुलाकात में बताया है कि वहां उन्हें राजनीतिक हलचल का बिल्कुल ही अभाव नजर आया।

बांग्लादेश से भारत के संबंध में शुरू से ही उतार-चढ़ाव का सिलसिला रहा है। बांग्लादेश बने पांच दशक से ज्यादा समय बीत गया, पर एक शिकायत लगातार बनी हुई है कि बांग्लादेशियों की भारत में घुसपैठ थमने का नाम नहीं ले रही। इससे भारत की चिंता धीरे-धीरे नाराजगी में बदलती गई है। साल 1977 में 1 दिसंबर को लोकसभा में जो बहस हुई थी, उससे पता चलता है, बांग्लादेश को लेकर हमारे जज्बात कितने बदल गए हैं।

आमने-सामने

बांग्लादेश को सेकुलर बनाए रखना होगा

यहां स्कैन करें

समर गुहा | वरिष्ठ नेता व सांसद

- बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का भाग्य उसकी धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा हुआ है।
- वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 60 लाख है।
- भारतीय सुरक्षा बल ने बलपूर्वक बहुत से लोगों को भारत से निकाल दिया।

मैं आज किसी दल के सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बोल रहा हूं, जिसे देश के कई महान नेताओं के चरणों में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

आज मैं इसे केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं, अपितु हमारे राष्ट्र की अंतरात्मा का ध्यानाकर्षण कहता हूं। बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हमारे ही भाई-बान्धव हैं, यद्यपि हम राजनीतिक सीमाओं से पृथक-पृथक हो गए हैं, फिर भी वे हमारे ही भाई-बहिन हैं और ऐसी स्थिति में उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी है। ऐसी ही बात 15 अगस्त, 1947 की मध्य रात्रि को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कही थी। महात्मा गांधी ने भी यही कहा था कि पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भारत में उचित आश्रय मिलना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी यही कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के प्रति हमारी महान जिम्मेदारी है। अभी हम एक प्राकृतिक तूफान की बात कर रहे थे, किंतु मैं प्रधानमंत्री, इस सभा तथा सारे भारत के लोगों को चेतावनी देता हूं कि इस प्रकार एक राजनीतिक तूफान भी आ सकता है, जो न केवल पूर्वी क्षेत्र के लिए, बल्कि समूचे देश के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है।

हमारे देश में बहुत लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता का हमारा पवित्र उद्देश्य बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता के भविष्य से जुड़ा है। इस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का भाग्य वहां की धर्मनिरपेक्षता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्रीय स्वतंत्रता भारी खतरे में हैं।...

मैंने दस वर्ष पहले एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें मैंने कह दिया था कि बांग्लादेश आजाद होगा। तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। आज उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि वहां जो आज स्थिति है, वह अयूब खां और याह्या खां के शासन से भी खराब है। हजारों देशभक्त, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी, आज कारावास में पड़े हैं। बंग बंधु तथा उनके साथियों की जो हालत हुई, वह हमसे छिपी हुई नहीं है। हमारे देश में 70 लाख शरणार्थी बांग्लादेश से आए हुए हैं तथा और भी आ रहे हैं। वे हमारे भाई हैं। तीस वर्ष का समय सदियों पुराने नाते को नहीं तोड़ सकता। राजनीतिक दृष्टि से चाहे हम पृथक-पृथक हों, परंतु अन्यथा हम एक हैं। इसलिए बांग्लादेश में जो हो रहा है, उस बारे में विचार व्यक्त करना हमारा अधिकार है।

...मुजीब तथा उनके साथियों की हत्या किए जाने के पश्चात हजारों की संख्या में लोग भारत आए थे। ये लोग ऐसे थे, जिनका नेशनल अवामी लीग से संबंध था। जब जनता पार्टी सत्ता में आई, तो उन्होंने यह नीति बनाई कि बांग्लादेश से आने वालों को भारत में न रहने दिया जाए। तब भारतीय सुरक्षा बल के लोगों ने बलपूर्वक बहुत से लोगों को भारत से निकाल दिया। उन लोगों को भारत से निकालते समय बहुत से लोग मारे भी गए थे। मैंने इस बारे में राष्ट्रपति को लिखा। वह इस बात से सहमत हो गए कि भारत से किसी को निकाला न जाए। इस प्रकार उनका भारत से निकाला जाना बंद हो गया। इसके बाद एक और घटना घट गई। जियाउर्रहमान ने प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया कि बांग्लादेश के उन लोगों को, जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है, बांग्लादेश वापस जाने पर कोई दंड नहीं दिया जाएगा। यह आश्वासन प्राप्त करने पर कुछ लोग वापस गए, किंतु जून में 16 व्यक्ति मारे गए। उन प्रत्यर्पित लोगों के बारे में मुझे एक और पत्र भी मिला है। उसमें भारत से अपील की गई है कि हम जियाउर्रहमान के आश्वासन पर बांग्लादेश वापस लौटे थे, किंतु कल को हमें फांसी पर लटका दिया जाएगा। 126 में से 40 को फांसी पर लटकाया जा चुका है, ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि उसकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है? मैं समझता हूं कि सरकार को ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो केवल शक्ति प्राप्त करने के लिए सत्ता को हड़पते हैं। मैं यह तो नहीं कहूंगा कि उन्हें आजाद करने के लिए हमें उन पर कूच कर देना चाहिए, किंतु हमें उन्हें भारत से इस प्रकार से नहीं निकाल देना चाहिए, ताकि वहां जाकर कसाइयों के हाथ उनका वध हो जाए।...

बांग्लादेश सरकार ने हाल में एक बयान में कहा है कि वहां पर अल्पसंख्यकों की संख्या 60 लाख है। ...1971 की जनगणना में गैर-मुसलमान लोगों को गिना नहीं गया था, क्योंकि उनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में था। असुरक्षा की भावना का पहला कारण यह है कि बांग्लादेश को धर्मतंत्रात्मक (इस्लामी) राज्य घोषित किया गया है। वहां धर्मांधता की राजनीति चल रही है। बहुत से बड़े-बड़े राजनीतिक नेता जेल में रखे गए हैं। वहां भारी अत्याचार हो रहा है। बांग्लादेश में एक सम्पत्ति अधिनियम प्रस्थापित किया गया है और एक अधिग्रहण अधिनियम बनाया गया है। हाल में वहां गैर-रिहाइश सम्पत्ति अधिनियम बनाया गया है। यदि किसी परिवार का एक व्यक्ति भी भारत आता है, तो तुरंत उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है।...

असुरक्षा का दूसरा कारण यह है कि वहां गैर-मुस्लिम समुदाय अथवा अल्पसंख्यकों का आईजी या कोई अन्य महत्वपूर्ण पुलिस अधिकारी नहीं है और प्रशासन में भी गैर-मुस्लिम समुदाय का कोई उच्च अधिकारी नहीं है। जो तीन-चार डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी भी पदावनति कर उन्हें क्लर्क बनाकर ढाका लाया गया है। गैर-मुस्लिम लड़कों, हिंदुओं, ईसाइयों तथा बौद्धों को इंजीनियरिंग कॉलेज अथवा मेडिकल कॉलेज या स्नातकोत्तर कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। व्यापार लाइसेंस भी उन्हें नहीं दिए जाते हैं। हाल में ही कई लाइसेंस जब्त किए गए हैं।

बांग्लादेश से जो लोग भारत आ रहे हैं, उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है और सीमा सुरक्षा बल से उन्हें जबर्दस्ती वापस भेजने को कहा जाता है। आज बांग्लादेश से भारी संख्या में लोग भारत में आए हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय व असम में, और उन्हें शरणार्थी नहीं माना जा रहा है। ...बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप किए बिना इस स्थिति से विवेकपूर्ण ढंग से तथा व्यावहारिक कुशलता से निपटा जाए, ताकि वहां फिर से धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कायम हो सके और अल्पसंख्यकों के लिए वहां स्थान सुनिश्चित किया जा सके।

(लोकसभा में दिए गए भाषण के अंश)

सीमा से अधिक दखल देना अच्छी बात नहीं

यहां स्कैन करें

अटल बिहारी वाजपेयी | तत्कालीन विदेश मंत्री

- उसे इस्लामी राज्य घोषित नहीं किया गया, बस एक शब्द बदला गया है।
- बांग्लादेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की कोई गणना नहीं कराई है।
- जो आश्रय के लिए भारत आए हैं, उनको आश्रय देना हमारा नैतिक कर्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर गुहा ने जो भावनाएं प्रकट की हैं, उनकी मैं कद्र करता हूं, लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि बांग्लादेश का मामला केवल प्रधानमंत्री देख रहे हैं और विदेश मंत्रालय से उसका कोई संबंध नहीं है।...

अगर ऐसा होता, तो इस समय उनकी जगह खाली न होती। उत्तर देने के लिए मैं खड़ा हूं, जो भी फैसले होते हैं, वे संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर होते हैं और पूरे सलाह-मशविरे के बाद किए जाते हैं। ...यह कहना ठीक नहीं होगा कि अचानक बांग्लादेश से आने वालों की संख्या में वृद्धि हो गई है।...

भविष्य में क्या छिपा है, यह तो प्रोफेसर गुहा जैसे भविष्यद्रष्टा ही देख सकते हैं, मेरे जैसा मामूली आदमी नहीं देख सकता है।... अगर बांग्लादेश का एक भी नागरिक अपना घर-द्वार छोड़कर भारत में आश्रय लेने के लिए आता है, तो हमारे हृदय में चिंता पैदा होती है। यह मामला लगातार हम बांग्लादेश सरकार के साथ उठा रहे हैं। यह विदेश सचिव के स्तर पर उठाया गया है ढाका से। नई दिल्ली में बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को बुलाकर यह बात उनके ध्यान में लाई गई। बांग्लादेश के विदेश मंत्री मुझे न्यूयॉर्क में मिले, तब मैंने इसकी चर्चा की। हमारे प्रधानमंत्री ने जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर्रहमान से लंदन में मुलाकात की थी, तब भी यह मामला उठा था। प्रोफेसर गुहा ने 1947 के महात्मा गांधी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के और स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वक्तव्यों का उल्लेख किया है। मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुयायी होने का सौभाग्य प्राप्त है। नजरबंदी में उनकी मृत्यु हुई और अल्पसंख्यकों के सवाल को लेकर उन्होंने स्वतंत्र भारत की पहली सरकार से त्यागपत्र दिया। हम भला इस सवाल को कैसे भूल सकते हैं?

लेकिन यह 1977 है। बहुत सा पानी गंगा और पद्मा में बह गया। 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ। बांग्लादेश एक स्वतंत्र सर्वप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरा है ओर उस संघर्ष में प्रोफेसर गुहा ने जो भूमिका निभाई, वह मैं जानता हूं। वह इतिहास में अंकित होगी, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए उनका दुख, उनकी वेदना मैं समझता हूं। लेकिन वह ऐसा न समझें कि सरकार को चिंता नहीं है। अब उन्होंने एक बात कह दी कि अभी वहां जनगणना की गई थी और यह कहा गया कि हिंदुओं की संख्या 60 लाख है। मैं पूछना चाहता हूं, यह 60 लाख की संख्या बांग्लादेश की सरकार की किस घोषणा में कही गई?... हमने इस बारे में पता लगाया है। . मुझे पता है कि बांग्लादेश में क्या संशोधन हुआ है। आखिर विदेश मंत्रालय का भार प्रधानमंत्री ने मेरे ऊपर सौंपा है, तो सारे तथ्यों को जानता हूं। बांग्लादेश को इस्लामी राज्य घोषित नहीं किया गया। 'सेकुलर' शब्द के स्थान पर 'अलमाइटी अल्ला' को रखा गया है। हमने इस बात की ओर भी बांग्लादेश सरकार का ध्यान खींचा।... उसमें एक शब्द यह रखा गया है कि 'अलमाइटी अल्ला के बताए रास्ते पर बांग्लादेश चलेगा। अब आप जरा ठहरें, जो चीज हुई नहीं, उसे कहने से कोई लाभ नहीं है।...

अगर बांग्लादेश से आने वालों की संख्या बढ़ा-चढ़ाकर छापी जाएगी, जो तथ्यों पर आधारित नहीं है, तो उसके दुष्परिणाम होंगे, असुरक्षा की भावना फैलेगी और भारत में भी उसकी अच्छी प्रतिक्रिया नहीं होगी। प्रोफेसर गुहा जिस उद्देश्य की सिद्धि करना चाहते हैं, वह उद्देश्य विफल हो जाएगा। ...मैं इसका खंडन करना चाहता हूं कि बांग्लादेश में सैनिक क्रांति के बाद जो लोग भारत में शरण लेने के लिए आए थे, उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ बांग्लादेश में धकेल दिया गया।... जो लोग गए हैं, वे अपनी इच्छा से गए हैं।... अगर कोई जाना नहीं चाहता था, तो उसके लिए भारत सरकार का विकल्प खुला हुआ था कि वे भारत में राजनीतिक शरण मांगें, मगर उसके साथ हमने दो शर्तें लगाई थीं। एक, उनको सीमा पर नहीं रहने दिया जाएगा और दूसरे भारत के भीतर बांग्लादेश के खिलाफ कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं करने दी जाएगी।... जो नहीं गए, वे भारत में रह रहे हैं। उन्हें किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं भेजा और न हम भेजेंगे। जो आश्रय के लिए भारत में आए हैं, उनको आश्रय देना हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमने उसका पालन किया है।...

प्रोफेसर गुहा ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, जिनका सीधा प्रभाव अल्पसंख्यकों पर हो रहा है और उन्होंने इस संबंध में एक संपत्ति संबंधी कानून का हवाला भी दिया है। मैं उनका ध्यान खींचना चाहूंगा कि जो नया अध्यादेश जारी किया गया है, उसमें कोई बुनियादी अंतर नहीं किया गया है, केवल कार्यवाही जल्दी करने का प्रावधान किया गया है।...

यह भी कहना ठीक नहीं है कि हम बांग्लादेश की स्थिति के बारे में सावधान हैं या पर्याप्त प्रभाव काम में नहीं ला रहे हैं, जिससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यक सुरक्षित रहें। उपाध्यक्ष महोदय, अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ समानता, न्याय और कुछ मात्रा में उदारता का व्यवहार करके हम अपने पड़ोसी देशों के सामने एक आदर्श रख रहे हैं। बंटवारे के समय में यह प्रस्ताव आया था कि धर्म के आधार पर आबादी की अदला-बदली होनी चाहिए, लेकिन उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यह बात मानी गई थी कि अल्पसंख्यक जिस किसी भी देश में होंगे, उस देश की सरकार का सांविधानिक, कानूनी व नैतिक दायित्व होगा कि उनके जीवन की रक्षा करे, उनके सामान की रक्षा करे और उनकी संपत्ति की रक्षा करे और भारत ने इसके अनुसार आचरण का प्रयत्न किया है और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो।...

भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों के बारे में बांग्लादेश सरकार से चिंता व्यक्त की है। अगर फिर भी स्थिति बिगड़ती है, तो उसके अनुसार, कदम उठाए जाएंगे। अगर प्रभावी कदम उठाने के लिए भी विवश होना पड़ा, तो उस पर भी सरकार सोचेगी, लेकिन इस संबंध में बढ़ा-चढ़ाकर बातें करना सही नहीं है। ...हमने बांग्लादेश से चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा रहेगी। चिंता व्यक्त कर दी गई है। वह कहते हैं कि 'डिस्प्लेजर' व्यक्त किया गया है या नहीं। मुझे क्षमा करें, सरकार का काम करने का अपना ढंग होता है।

(लोकसभा में दिए गए भाषण के अंश)

मनसा वाचा कर्मणा

वे सात शब्द

बहुत पहले की बात है, अरब में एक अद्भुत व्यापारी था। उसने अपनी जिंदगी में कभी विफलता नहीं देखी थी, बल्कि आलम यह था कि वह जो कुछ भी छूता, वही सोने में बदल जाता, कहने का तात्पर्य यह कि वह जिस काम में भी हाथ डालता, उसी में कामयाबी के कीर्तिमान रच देता। लोग उसे किसी जादूगर की तरह मानते थे। कारोबारी दुनिया का वह वाकई जादूगर था, क्योंकि जब कभी भी वह यात्रा पर निकलता, तो अपने ऊंटों पर नए-नए खजाने लादकर लौटता। कभी हीरे-मोती लेकर, तो कभी अशर्फियों से भरी बोरियां लादकर।

फिर एक दिन यह अफवाह फैली कि उस व्यापारी ने अपनी सफलता का राज एक किताब में बता दिया है। जाहिर है, जिसने भी सुना, वह उसके घर की तरफ दौड़ पड़ा, ताकि उस किताब को हासिल कर सके। देखते-देखते उसके दरवाजे पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। व्यापारी ने न केवल यह स्वीकार किया कि उसने वाकई अपनी सफलता का राज किताब में लिखा है, बल्कि वहां एकत्र भीड़ को उसने यह भी बताया कि वह खुद पिछले पचास सालों से नियमित रूप से उस जादुई किताब को पढ़ता आ रहा है। अपनी तकरीर के अंत में उसने यह भी कहा कि अगर तुम लोग मेरी सलाह मानोगे, तो तुम सबका जीवन भी मेरे जैसा चमत्कारी हो जाएगा।

भीड़ व्यापारी से उस किताब को दिखाने का इसरार करने लगी। आखिरकार, उसने वह किताब खोलकर लोगों को दिखाई। उस बड़ी किताब के तमाम पन्नों पर सिर्फ सात शब्द बार-बार लिखे थे। मैं भी आपसे वे सात शब्द कहना चाहता हूं और वे शब्द हैं : कुछ हो जाए, एक कोशिश और करो।

ओशो

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

जैसे-जैसे सामाजिक चुनौतियां और प्राथमिकताएं बदली हैं, वैसे-वैसे साहित्य में भी बदलाव देखे गए हैं। मगर साहित्य में कुछ ऐसा भी होता है, जो सदियों बाद भी प्रासंगिक बना रहता है।

अनुलोम-विलोम

स्वदेशी का आह्वान

अमल करने लायक स्वदेशी की यह अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वदेशी का आह्वान हर भारतवासी को आत्मसात करना चाहिए। हमें उन देशों के उत्पाद इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, जो हमारे मित्र-राष्ट्र नहीं हैं या जो शत्रु देश को प्रोत्साहित करते हैं। केंद्र सरकार हमारे देश के उद्यमियों को भी प्रेरित करे। हमारे उद्योगपतियों का फर्ज बनता है कि वे देश की जनता को सही, सस्ता, मजबूत और टिकाऊ उत्पाद उपलब्ध कराएं, ताकि जनता विदेशी वस्तुओं के आकर्षण में न फंसे। अगर देश की जनता ने साथ दिया और सरकारों ने इस मौके का सार्थक उपयोग किया, तो भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ऊपर उठेगी। संभवतः हम शीर्ष तीन में भी जल्द पहुंच सकेंगे। अगर इसका कुछ अंश भी हम पूरा करने में सफल रहे, तो दुनिया का हर व्यक्ति भारत का वीजा पाने का इच्छुक दिखेगा। हमें इस सपने को सच बनाना चाहिए और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए स्वदेशी को अपनाने पर जोर देना चाहिए।

ऋषि पांडे, टिप्पणीकार

लाल बहादुर शास्त्री के बाद संभवतः नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं, जिन्होंने कोई खास देशव्यापी आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने एक तरह से चीन के सामान की खरीदारी बंद करने का आह्वान करते हुए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही। चीन कभी हमारा दोस्त नहीं रहा है। भारत उसके लिए महज एक बाजार है। इसलिए, यदि हम स्वदेशी पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले हमें चीनी माल की तुलना में सस्ता और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करना होगा। इसके साथ ही हमें धीरे-धीरे विदेशी उत्पादों से दूरी बनानी होगी। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात करते हुए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद तैयार करने की भी अपील की है। साफ है, उनका मकसद भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करना है। इतिहास के विद्यार्थी जानते ही होंगे कि इससे पहले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत में खाद्य संकट से निपटने के लिए देशवासियों से हफ्ते में एक बार भोजन न करने की अपील की थी। यह 1965 में भारत-पाक युद्ध और अमेरिका द्वारा अनाज-निर्यात बंद करने की धमकी के दौरान हुआ था। शास्त्रीजी ने खुद भी अपने परिवार के साथ इस अपील का पालन किया और देशवासियों से ऐसा ही करने का अनुरोध किया, जिससे लोगों ने सोमवार शाम के भोजन त्याग दिए थे। क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या हमें प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करना चाहिए?

प्राण चड्ढा, टिप्पणीकार

विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार मुमकिन नहीं

क्या उदारीकरण के युग में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार संभव है? जब हम किसी देश के उत्पाद नहीं खरीदेंगे, तो दूसरे देश भी हमारे उत्पाद क्यों खरीदेंगे? क्या हमारे प्रधानमंत्री यह कहना चाहते हैं कि सिर्फ निर्यात किया जाए, आयात बंद कर दिया जाए? अगर ऐसा है, तो आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दीजिए, खुद बहिष्कार हो जाएगा? जनता के बजाय, सरकार क्यों नहीं बहिष्कार की शुरुआत करती है? जब वह ऐसा नहीं कर सकती, तो जनता से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान क्यों किया जा रहा है? दुनिया लेन-देन के सिद्धांत पर ही चलती है। एकतरफा व्यापार कहीं नहीं होता। भारत भी इस आह्वान में शायद ही सफल हो सकेगा।

सलीम अख्तर सद्दीकी, टिप्पणीकार

अंग्रेजी शासन के समय महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था, जिसमें विदेशी कंपनियों द्वारा तैयार वस्तुओं का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का शासन था और वे भारत से कच्चा माल लेकर ब्रिटेन में उत्पाद तैयार करते थे, और फिर वही सामान हिन्दुस्तान के बाजार में बेच दिया करते थे। मगर इस समय क्या देश में कोई विदेशी शासन है कि आम जनता फिर से स्वदेशी आंदोलन चलाए? क्या हम पर अब भी ब्रिटेन या गोरों का शासन है? जिस तरह भारत सरकार अभी पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ मुखर है, उसी तरह, वह सभी विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाकर अपनी नीति का एलान क्यों नहीं करती? उसे तो सबसे पहले चीन में बने उत्पादों पर इस तरह का प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या देश की आम जनता इस हालत में है कि वह स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं में से किसी एक का चयन कर सके?

वास्तव में, विदेशी वस्तुओं का प्रयोग मुख्यतः कुलीन वर्ग करता है। सबसे महंगी कारें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या ब्रांडेड कपड़े कौन इस्तेमाल करता है? हमारा पूरा बाजार विदेशी वस्तुओं से भरा हुआ है। अगर हम सुपरमार्केट या ऑनलाइन बाजार का सर्वेक्षण करें, तो विदेशी वस्तुएं अमीर घरों की शोभा बढ़ाती पाई जाएंगी। आज इस धनाढ्य वर्ग के हाथों में विदेश का मोबाइल है। ऐसे ज्यादातर घरों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। उनका इलाज भी देश से बाहर ही होता है। इनमें से कई ने तो भारत की नागरिकता छोड़ दी है। फिर, अपने देश में कॉस्मेटिक से लेकर कई चीजें इजरायल से आयात की जाती हैं। तो, सरकार विदेशी वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध की अधिसूचना क्यों नहीं जारी करती? इसके बाद खुद-ब-खुद काम हो जाएगा और स्वदेशी आंदोलन सफल हो जाएगा।

हेसामुद्दीन अंसारी, टिप्पणीकार

CCI NG 3.7 Product: NBTLucknowBS PubDate: 31-05-2025 Zone: Lucknow Edition: 1 Page: NBTLPG8 User: rishi.yadav Time: 05-30-2025 23:33 Color:

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । कानपुर (कानपुर व लखनऊ में एक साथ प्रसारित) । शनिवार, 31 मई 2025

सुरक्षा का प्रश्न

डिफेंस प्रॉजेक्ट्स में हो रही है देरी

रक्षा परियोजनाओं में देरी पर भारतीय वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की चिंता और सवाल वाजिब हैं। दोतरफा मोर्चे पर जूझ रही सेना के आधुनिकीकरण में तेजी लाने की जरूरत है। इसके लिए केवल विदेशी सौदों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, मेक इन इंडिया प्रॉजेक्ट के तहत भी उत्पादन बढ़ाना होगा।

एयरफोर्स की चुनौती

हवाई मजबूती । एयरफोर्स चीफ की टिप्पणी ऐसे वक्त आई है, जब भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को हवाई क्षमता का प्रदर्शन कर ध्वस्त किया था। इसी टकराव ने यह भी दिखाया कि जंग में लड़ाकू विमानों की भूमिका कितनी अहम हो चुकी है।

पाक-चीन दोस्ती । भारत के सामने दो फ्रंट खुले हुए हैं - पाकिस्तान और चीन। और चिंता की बात यह है कि जो चीन के पास है, वह किसी न किसी तरह पाकिस्तान के पास पहुंच ही जाता है। हालिया टकराव में ही उसने तुर्किये के ड्रोन और चीन के लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। भारत के लिए ताजा रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है कि चीन अपने जे-35 स्टेल्थ फाइटर जेट भी पाकिस्तान को देने जा रहा है। सरकार ने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण को मंजूरी तो दी है, पर अगर उम्मीद पूरी हुई तो भी इनको बनने में 10 साल लग जाएंगे।

विमानों की कमी । भारतीय वायु सेना के पास 42.5 स्क्वाड्रन लड़ाकू विमान होने चाहिए, लेकिन हैं केवल 30। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी तक स्वदेशी तेजस मार्क-1A की डिलिवरी नहीं कर पाया है। इसकी वजह से वायु सेना की रक्षा तैयारियों पर असर पड़ रहा है। एयर चीफ पहले भी यह मुद्दा उठा चुके हैं।

मेक इन इंडिया । भारत ने हाल में 'मेक इन इंडिया' पर दम लगाया है। 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ का रक्षा उत्पादन इस प्रॉजेक्ट के तहत हुआ - साथ ही देश ने 21 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का डिफेंस एक्सपोर्ट किया। 100 से अधिक मुल्कों ने भारत से रक्षा उपकरण और हथियार खरीदे हैं। एक दशक में करीब 30 गुना की तेजी आई है।

तेजी की जरूरत । भारत को आने वाले वक्त में अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। साथ ही, जिस तरह से चीन ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है, भारत को भी उस राह पर तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसके लिए डिफेंस प्रॉडक्शन को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है और इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।

खुले मन से

ताकि भविष्य में कोई धाकड़पंती न दिखाए

सुधीर मिश्र

कैस रामपुरी का शेर है-

लुट गए एक ही अंगड़ाई में ऐसा भी हुआ
उम्र-भर फिरते रहे बन के जो होशियार बहुत

कैमरों ने आजकल राजनीति करने वालों की जान ले रखी है। कोई नेता थोड़ा सा धाकड़ बनकर जरा सा भी एडवेंचर करता है तो कैमरा पकड़ लेता है। घर का फंक्शन हो या एक्सप्रेस-वे, पार्टी का दफ्तर हो या होटल के कमरे। बरसों की मेहनत पर एक छोटी सी क्लिप भारी पड़ जाती है।

इसी हफ्ते की बात है। यूपी के एक नेता जी ने अपनी ही पार्टी कार्यालय की सीढ़ियों पर एक कार्यकर्ता के साथ 'भावपूर्ण मुद्रा' में सीसीटीवी कैमरे की गिरफ्त में आ गए। पार्टी पहले से ही एक ताऊ के आइटम डांस से परेशान थी। अब जान-बूझते मक्खी कैसे निगली जाए तो भावनाओं का सार्वजनिक प्रदर्शन करने वाले नेता जी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ। मन में सवाल आया कि आखिर नोटिस की भाषा क्या होगी और नेता जी ने जवाब क्या दिया होगा।

एक वरिष्ठ नेता को फोन किया तो वह शिकायती लहजे में कहने लगे-अब मजा मत लीजिए। मैंने कहा-अरे मजे की क्या बात है, जरा बताइए तो क्या कारण बताया। कहने लगे-जिले वाले नेता जी का कहना है कि कार्यकर्ता की तबीयत खराब हो गई थी तो वह सीढ़ियों पर उसे संभाल रहे थे, पर पार्टी के पास सिर्फ एक फुटेज नहीं था। अलग-अलग एंगल से कई और विडियो भी थे। बहरहाल, बात फिर इस पर शुरू हुई कि राजनीतिज्ञों की इस राष्ट्रीय समस्या का आखिर समाधान क्या है? आमतौर पर नेता जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, वहां इस तरह का भाव प्रदर्शन सामान्य माना जाता है।

वरिष्ठ नेता काफी सुलझे हुए थे। उन्होंने व्यावहारिक बात कही-देखिए इन बिगड़े नेताओं के कुसंस्कार और लक्षण तो बदले नहीं जा सकते, लेकिन ये लोग ऐसे ही करते रहे तो पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। लिहाजा अब कैमरों से कैसे बचें, इसका प्रशिक्षण देना जरूरी है। हर हाथ में मोबाइल कैमरा है, हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जहां नजर नहीं आते, वहां भी हो सकते हैं- स्विच बोर्ड, पर्दों के पीछे, टीवी की साइड में, पंखों, एयरकंडीशनर या दीवार में कहीं भी। खुद अपना मोबाइल और लैपटॉप भी धोखा दे सकता है इसलिए सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि लोग आचरण साफसुथरा रखें, लेकिन आचरण की सफाई का हाल भी स्वच्छ भारत अभियान जैसा है। ऐसे में बचाव और सतर्कता ही उपाय है। नेता जी विचार कर रहे हैं कि साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जाए। कुछ कार्यशालाएं करवाई जाएं और सतर्क व्यवहार का यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सबसे निचली पायदान के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे ताकि भविष्य में कोई धाकड़पंती न दिखाए। बहरहाल, कैमरों की गिरफ्त में आए नेताओं की बेचारगी पर इब्न-ए-इंशा का यह शेर और बात खत्म -

एक से एक जुनूं का मारा इस बस्ती में रहता है
एक हमीं हुशियार थे यारो एक हमीं बद-नाम हुए

ऑफ़ दि ट्रैक

मोटापे पर शिकंजा

दिलीप लाल

मोटापा और डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सेमाग्लूटाइड समूह की दवाओं को लेकर स्वीडन की यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग में हुई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की कुछ खास नर्व सेल्स की पहचान की है। चूहों पर किए गए परीक्षण में जब इन विशेष कोशिकाओं को बिना दवा दिए ही सक्रिय किया गया, तो उन्होंने कम भोजन किया और उनका वजन भी घटा। इसके विपरीत, जब इन्हीं कोशिकाओं को निष्क्रिय कर दिया गया, तो दवा देने के बावजूद उसका प्रभाव कम हो गया और साइड इफेक्ट्स अधिक दिखे। निष्कर्ष निकाला गया है कि इन खास तंत्रिका कोशिकाओं की पहचान से सेमाग्लूटाइड जैसी दवाएं और अधिक असरकारक और सुरक्षित बनाई जा सकती हैं।

ग्लोबल टैलंट की राह रोक US पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है

क्या भारत को महान बनाएंगे ट्रंप

विवेक वाधवा

लंबे समय से अमेरिका की ताकत का राज इस तथ्य में निहित रहा है कि दुनिया की सबसे शानदार प्रतिभाएं उसकी ओर खिंचती चली जाती हैं और वहां उन्हें न केवल आर्थिक संसाधन उपलब्ध होते हैं बल्कि साहसी रिसर्च इंस्टिट्यूशन का साथ भी मिलता है। मगर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कदम-दर-कदम इस व्यवस्था को खत्म किए जा रहे हैं। अमेरिका के लिए यह इनोवेशन के सबसे सशक्त इंजन के धीरे-धीरे बंद पड़ते जाने जैसा है, लेकिन भारत के लिए यह एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।

क्या है संदेश । हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनैशनल स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट पर रोक लगाई गई है। फेडरल रिसर्च फंडिंग के 2.7 बिलियन डॉलर से ऊपर की रकम फ्रीज कर दी गई है। MIT को ग्रेजुएट एडमिशन में कटौती और रिसर्च स्टाफ की छंटनी करनी पड़ी है। कैंसर रिसर्च, क्लामेट साइंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े प्रॉजेक्ट या तो बंद किए जा चुके हैं या बाधित किए जा रहे हैं। हालांकि एक फेडरल जज ने हार्वर्ड के खिलाफ उठाए गए प्रशासन के कदमों पर तात्कालिक रूप से रोक लगाई है, लेकिन इनका जो असर होना था, वह काफी हद तक हो चुका है। इंटरनैशनल स्टूडेंट्स और रिसर्चरों की बिरादरी को साफ संदेश जा चुका है कि अमेरिका में अब उनका स्वागत नहीं होने वाला।

इनोवेशन इकॉनमी की जड़ें । नतीजा यह कि अमेरिका में इंटरनैशनल स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट में भारी गिरावट आई है जो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। ध्यान रहे, यूनिवर्सिटी साइंस में सार्वजनिक निवेश ने वहां न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में जादू किया है और डिजिटल क्रांति को संभव बनाया है बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री ही खड़ी कर दी है। नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) और नैशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) में निवेश ने बायोटेक, क्लीनटेक और नैनोटेक के फलने-फूलने में मदद की। डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट में DARP के अनुदानों ने हमें GPS और शुरुआती इंटरनेट दिया। देखा जाए तो ये अमेरिकी इनोवेशन इकॉनमी की जड़ें हैं। इन पर प्रहार करना वैसा ही है जैसे किसी बहुमंजिला इमारत के निर्माण के बीच में ही उसके नींव को तोड़ने लग जाना।

प्रवासियों का कमाल । सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स में आधे से ज्यादा ऐसे हैं, जिनका कम से कम एक फाउंडर प्रवासी है। इनमें से एक तिहाई फाउंडर भारतीय हैं। ड्यूक, हार्वर्ड और यूसी-बर्कली पर मेरी रिसर्च के मुताबिक भारतीय प्रवासी जितने सिलिकॉन वैली स्टार्टअप के फाउंडर हैं, ब्रिटेन, चीन और ताइवान के प्रवासी मिलकर भी उस संख्या तक नहीं पहुंचते। इन कंपनियों ने सिर्फ धन नहीं पैदा किया है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री खड़ी की है। यह पाइपलाइन बंद हो रही है।

आर्थिक पहलू । इसका आर्थिक बोझ भी बड़ा भारी है। इंटरनैशनल स्टूडेंट्स अमेरिका की इकॉनमी में हर साल 40 बिलियन डॉलर का योगदान करते हैं। ये ट्यूशन फी भरते हैं, घर किराये पर लेते हैं, खाना खरीदते हैं और उनमें से बहुतेरे कंपनी लॉन्च करने की राह पर आगे बढ़ते हैं। रिसर्च फंडिंग से अमेरिका के हर राज्य में सैकड़ों-हजारों नौकरियां बनती हैं और भविष्य की इंडस्ट्री को सहारा मिलता है।

रणनीतिक पहलू । रणनीतिक लागत तो और भी ज्यादा है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, बायोटेक और क्लीन एनर्जी के क्षेत्रों में अमेरिका का दबदबा ग्लोबल टैलंट को आकर्षित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। इस व्यवस्था को कमजोर करने का मतलब सिर्फ यूनिवर्सिटियों की कमजोरी नहीं है। इससे ग्लोबल इकॉनमी में अमेरिका की स्थिति खतरे में पड़ती है।

भारत के लिए अवसर । इसके उलट, भारत ग्लोबल टैलंट को आकर्षित करने और टिकाए रखने के मामले में आगे बढ़ता दिख रहा है। इसके रिसर्च इंस्टिट्यूशंस विश्व स्तरीय क्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं। भारत ने सस्ता वैक्सीन तैयार किया और नासा के बजट के मुकाबले नाम मात्र के खर्च में सफलतापूर्वक स्पेस मिशन संचालित कर रहा है। इसके पास अपना फलता-फूलता स्टार्टअप इकोसिस्टम है, वैश्विक पूंजी तक पहुंच है और एक ऐसी खूबी है जिसका चीन में घोर अभाव है - खुलेपन और बहस को बढ़ावा देने वाली लोकतांत्रिक व्यवस्था।

जरूरी कदम । भारत अभी भी इस स्थिति में नहीं है कि ग्लोबल रिसर्च सुपरपावर के रूप में अमेरिका की जगह ले सके। लेकिन यह इस स्थिति में जरूर है कि अमेरिका से विमुख हो रहे टैलंट और एनर्जी का फायदा उठा सके। यह बात अलग है कि इस अवसर का फायदा उठाने के लिए उसे बहुत कुछ करना होगा। भारत को रिसर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना होगा, रेग्युलेटरी व्यवस्था बेहतर बनानी होगी और सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। यही नहीं विदेशों में बसे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और विदेशी रिसर्चरों के आने की राह भी तैयार करनी होगी। सबसे बड़ी बात यह कि इसे रिसर्च को राष्ट्रीय प्राथमिकता में लाना होगा। ट्रंप भारत को फिर से महान बनने में मददगार हो सकते हैं।

(लेखक वायोनिक्स बायो साइंस के फाउंडर हैं)

भारत के लिए मौक़ा

भारत के सामने लक्ष्य है 2047 तक विकसित बनने का। US और UK से डील पर बात, चीन प्लस वन की पॉलिसी भारत के हक में भी है। यह मौका हिंदुस्तान का हो सकता है, लेकिन उसे इन मोर्चों पर काम करना होगा।

कम निवेश
भारत की जीडीपी ग्रोथ 6% से ऊपर है। फिर भी 2014 में पूंजी निवेश जीडीपी का 25.3% था। 2023 में घटकर 25.1% रह गया। कंपनियों की बात करें, तो 2023 में उनका निवेश जीडीपी का 11.5% रह गया।

सुधार नाकाफी
टैक्स से जुड़ी जटिलताओं को कम करने के लिए सरकार ने 2017 में GST लागू किया। 2019 में कॉरपोरेट टैक्स 35% से घटाकर 25% कर दिया गया। मगर इनका उम्मीद के मुताबिक असर नहीं हुआ।

कम खपत
टैक्स कटौती से कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन निवेश यानी कैपेक्स में बड़ा उछाल नहीं दिखा। निवेश में कमी की वजह है खपत का नहीं बढ़ना। पिछले 10 साल में फैक्ट्रियों की क्षमता का 70-75% ही उपयोग हो पा रहा है। इस कारण कंपनियां नई जगह पैसा नहीं लगा रहीं।

टैक्स राहत
खपत बढ़े, इसके लिए सरकार ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की अपील की है। मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का दायरा भी बढ़ा दिया गया, पर असर सीमित रहा क्योंकि सैलरी पाने वाले लोग वर्कफोर्स का सिर्फ 20% हैं।

कानूनी अड़चन
सरकार चाहती है विदेशी कंपनियां यहां फैक्ट्रियां लगाएं, लेकिन टैरिफ और टैक्स की उलझनें उन्हें डरा रही हैं। Volkswagen और Samsung पर टैक्स केस चल रहे हैं। इससे निवेशकों का भरोसा कमजोर होता है।

प्रस्तुति: शैलेंद्र पांडेय

अधिक लोगों को चाहिए सस्ती क़ानूनी मदद

पिछले दिनों इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 आई है, जिसमें भारत की न्यायपालिका, पुलिसिंग, जेलों और न्यायिक व्यवस्था की विविधता को लेकर कई शोध शामिल हैं। कुछ मामलों में न्यायिक व्यवस्था बेहतर हुई है, कुछ को लेकर अभी काफी काम करना बाकी है। इस रिपोर्ट की प्रधान संपादक माया दारूवाला हैं। रिपोर्ट पर उनसे बात की NBT के राहुल पाण्डेय ने। पेश हैं बातचीत के अहम अंश:

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

माया दारूवाला

■ दुनिया भर में भारत में रूल ऑफ लॉ की रैंकिंग में थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन कुछेक चीजें सुधरी भी हैं...

न्याय व्यवस्था के लिए बजट, वर्कफोर्स और सुविधाओं की भारी कमी है। हमारी आबादी 1.4 अरब से अधिक है। ऐसे में न्याय प्रणाली के संसाधन कम होंगे तो उसके हाल का खयाल किया जा सकता है। इसलिए न्याय मिलने में देरी स्वाभाविक है। जहां तक क्षमता की बात है तो हमने रिपोर्ट में सभी राज्यों की पुलिस, जेलों की क्षमता, न्यायपालिका, कानूनी सहायता और राज्य मानवाधिकार आयोगों को रैंकिंग दी है, ताकि जो जिस क्षेत्र में पीछे हैं, उसमें सुधार ला सकें।

■ न्यायिक व्यवस्था के तहत पुलिस में अभी तक महिलाओं और कई वर्गों के लिए एक तरह का पूर्वाग्रह दिखता है...

सचाई यही है कि जिनके लिए सिस्टम बना है, वे ही उसमें नहीं दिखते। आप आंकड़े देखिए। महिलाओं की संख्या पुलिस में केवल 12% है। प्रावधान है कि हर पुलिस स्टेशन में कम से कम 10 महिला कॉन्स्टेबल और 3 महिला सब-इंस्पेक्टर स्तर की अधिकारी हों। लेकिन ऐसा आपको कहां देखने को मिलता है? 20 लाख की पुलिस फोर्स में 960 महिला IPS अधिकारी हैं। ऐसे ही पुलिस में 11% SC ऑफिसर 14% SC कॉन्स्टेबल, 8% ST ऑफिसर और 9% ST कॉन्स्टेबल, 18% OBC अधिकारी और 26% OBC कॉन्स्टेबल हैं। जब तक प्रशासन में समूचे समाज की न्यायसंगत भागीदारी नहीं होगी, न्याय अधूरा रहेगा।

■ लीगल ऐड (AID) और पैरालीगल वॉलंटियर्स की हालत तो अच्छी नहीं है। इसमें क्या सुधार किए जाएं?

देश के 80% लोग मुफ्त कानूनी सहायता पाने के हकदार हैं। लीगल ऐड की व्यवस्था बनी ही कमजोर तबकों के लिए है। विडंबना है कि या तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या इससे उम्मीद ही नहीं है। इस महत्वपूर्ण सेवा पर मात्र 6 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं। आज एक लीगल ऐड क्लीनिक को 163 गांव कवर करने पड़ते हैं। पांच साल में पैरालीगल वॉलंटियर्स की संख्या 38% कम हो गई है। कानूनी सहायता सेवा को प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह देखने की जरूरत है। स्मार्टफोन से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। पंचायत स्तर पर लीगल ऐड क्लीनिक और पैरालीगल वॉलंटियर्स की बहाली होनी चाहिए।

■ नई आपराधिक संहिता का जुडिशल सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा है?

इन कानूनों को आए 1 साल ही हुआ है। सरकार अभी इन्हें लागू करने पर जोर दे रही है। भारतीय न्याय संहिता में 13 नए अपराध शामिल किए गए हैं। 33 अपराधों में सजा बढ़ाई गई है। 13 अपराधों में सजा दोगुनी या इससे ज्यादा की गई है। 23 अपराधों में न्यूनतम सजा अनिवार्य की गई है। 7 हजार से ज्यादा अपराध ऐसे हैं, जिनमें जेल हो सकती है। इनसे हमारी जेलों में कैदियों की संख्या पर असर पड़ेगा। पुलिस और कोर्ट दोनों के लिए टाइमलाइन तय कर दी गई है, पर पुलिसकर्मियों, जजों, वकीलों, कोर्ट की संख्या उतनी ही है। कार्यभार पहले से ही ज्यादा है। अभी हमारे पास भरपूर क्षमता नहीं है तो कई बार न्याय व्यवस्था में शॉर्टकट का रास्ता भी अपनाया जाता है, इसका भी खतरा है।

■ भारत की जेलों की हालत लगातार खराब होती जा रही है। आपका क्या कहना है?

भारत की जेलों में औसतन 100 की जगह राष्ट्रीय स्तर पर 130 से ज्यादा कैदी हैं। देश में 34 जेल ऐसी हैं, जिनमें कई सालों से 250% ऑक्युपेंसी है। दिल्ली की तिहाड़ की दो जेलें, पश्चिम बंगाल की कांडी जेल, उत्तर प्रदेश की ज्ञानपुर, सहारनपुर, सुल्तानपुर जेलों में 400% कैदी हैं। मुरादाबाद जेल में तो 100 की जगह 500 कैदी भरे हैं। पिछले दशक में विचाराधीन कैदियों की संख्या और जेलों में रहने की अवधि दोनों बढ़ी है। हर 4 में से 3 कैदी विचाराधीन हैं, जिनमें से कई का मुकदमा शुरू नहीं हुआ, कई की जांच चल रही है। आज हमारी जेलों में 4.36 लाख कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन इनमें 5.73 लाख कैदी हैं। हमारा प्रोजेक्शन बताता है कि 2030 तक हमारी जेलों में 5.15 लाख कैदियों को रखने की क्षमता हो जाएगी, लेकिन तब तक कैदियों की संख्या भी बढ़कर 6.88 लाख हो जाएगी।

> **देश के 80% लोग मुफ्त कानूनी सहायता पाने के हकदार हैं। यह व्यवस्था बनी ही कमजोर तबकों के लिए है। विडंबना यह है कि या तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या इससे उन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है। हम इस महत्वपूर्ण सेवा पर मात्र 6 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं। आज एक कानूनी सहायता क्लीनिक को 163 गांव कवर करने पड़ते हैं**

■ कर्नाटक इकलौता राज्य है जिसने न्यायिक व्यवस्था में SC/ST/OBC का कोटा भरा है। एक विविधतापूर्ण न्यायिक व्यवस्था न होने के क्या नुकसान हैं?

प्रतिनिधित्व और भागीदारी लोकतंत्र का जरूरी मूल्य है। इसलिए हमारे संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा गया था। आज जिला अदालत में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व 5% और अनुसूचित जाति का 14% है। विविधता का मतलब है- हर आवाज को बराबरी मिलना। जब न्याय व्यवस्था में सबकी भागीदारी दिखती है तो पता होता है कि लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है। इससे न्याय व्यवस्था और इंसाफ पर लोगों का भरोसा भी बढ़ता है।

www.nbt.in

जो अंत तक साथ रहते हैं

खुद अपनी आंख से

क्षमा शर्मा

पिछले दिनों आगरा में एक करीबी की मृत्यु हो गई। रात को खबर मिली, तो मुंह अंधेरे वहां के लिए निकली। आसमान में अभी सूरज की लालिमा ही थी। एक्सप्रेस-वे पर कैब फर्राटे भर रही थी। उसी रफ्तार से स्मृतियां दिमाग की कुंडियां खड़खड़ा रही थीं। जो चले गए, उनके साथ बचपन के न जाने कितने वर्ष बिताए थे। अतीत कभी लौटता नहीं, पर अक्सर किसी घटना-दुर्घटना के बाद ज्यों का त्यों आंख के आगे आकर खड़ा हो जाता है।

आगरा शहर में जैसे सब कुछ नया-नया नजर आ रहा था। खैर, वहां पहुंची। वातावरण बहुत बोझिल था। घर के बगीचे में लगे पेड़-पौधों पर भी धूल जमी थी। वे मुरझाए थे, जैसे कि वे भी शोक मना रहे हों। सबसे मिलना-मिलाना हुआ, श्रद्धांजलि अर्पित की। तभी आंगन से किसी के जोर से रोने की आवाज आई। ध्यान से सुना, तो वह उनके पालतू कुत्ते की आवाज थी। आंगन में वह जंजीर से बंधा था। खींच-खींचकर उसे तोड़ देना चाहता था। उन परिजन के बेटे ने बताया कि यह रात से परेशान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि पापा, जिन्हें वह भी बच्चों की तरह बाबा नाम से पहचानता था, रात भर से सो क्यों रहे हैं! पूरी रात वह उनके कमरे में जा-जाकर देखता रहा है। उनकी फोटो देखकर भौंकता रहा है। रात भर यहां बैठा था, और बार-बार सूंघकर देखता था। मन और भी दुख से भर गया। ये जानवर कितना मोह पालते हैं। मनुष्य पर कितना भरोसा करते हैं और अक्सर मनुष्य इनके भरोसे को तोड़ता भी रहता है। मनुष्य के लिए कई बार अपनी जान भी गंवा देते हैं। बातों-बातों में लड़के की पत्नी ने बताया कि जब इसे खाना नहीं खाना होता था, तो पापा के कमरे में जाकर छिपा आता था, जिससे कि हम देख न लें और इसे डांट न पड़े। पापा इसे कभी नहीं डांटते थे। उन्हीं के साथ सोता था। जब सवेरे वो गेट पर जाकर बैठते थे, तो उनके साथ ही बैठा रहता था। कोई जानवर या कोई दूसरा कुत्ता उनकी तरफ आता, तो भौंक-भौंककर उनका पीछा करके भगा देता था।

अब अंतिम यात्रा की तैयारियां हो रही थीं, मगर उस कुत्ते का रोना लगातार जारी था। उसका रोना बेचैन कर रहा था। आखिरकार कह ही दिया - सब लोग यहां बैठे हैं। वह वहां बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। उनके बेटे को बात समझ में आई, तो उसने उसे खोल दिया। वह दौड़ा आया। अपनी बड़ी-बड़ी काली आंखों को खोलकर हर एक के सामने खड़ा हो जाता। मानो पूछ रहा हो कि मुझे बताते क्यों नहीं कि क्या हुआ है। फिर वह तेजी से अपने मालिक के पास पहुंचा और पंजे मार-मारकर उठाने की कोशिश करने लगा। जब उसका यह प्रयास भी काम न आया तो उसने गले से इतनी दुख भरी आवाज निकाली कि जितने लोग वहां बैठे थे, सबकी आंखें भर आईं।

चलते-चलते...

प्राचीन चीन में रहने वाले लोगों के 100 से अधिक जीनोम का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिकों को एक रहस्यमय 'भूत वंश' (ghost lineage) का सुराग मिला है। यानी प्राचीन DNA में इसकी आनुवंशिक छाप दिखाई दी है। पेइचिंग के इंस्टिट्यूट ऑफ वर्टिब्रेट पेलियंटोलॉजी एंड पैलियोएंथ्रोपोलॉजी का यह अध्ययन Live Science में प्रकाशित हुआ है।

रीडर्स मेल

बांग्लादेश में बढ़ता तनाव

रोहिंग्या शरणार्थी संकट, म्यांमार के रखाइन प्रांत में जारी हिंसा और प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय मानवीय गलियारा न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में तनाव बढ़ा रहे हैं, बल्कि भारत की सुरक्षा और विदेश नीति पर भी असर डाल रहे हैं। बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच मतभेद, स्थानीय संसाधनों पर दबाव, सीमा पर ड्रग तस्करी और अवैध व्यापार जैसे मुद्दे चिंता बढ़ा रहे हैं। भारत को सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस संकट में चीन और पाकिस्तान की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत होती है। ऐसे में दक्षिण एशियाई सहयोग संगठनों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इन मुद्दों का समाधान केवल सैन्य उपायों से संभव नहीं है। समय रहते जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो यह विवाद पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। वैसे भी भारत को सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव और अशांति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के अंदरूनी हालात चिंताजनक हैं।

मुकेश रावत, लखनऊ

पर्यटकों को प्रोत्साहन

यह लेख 28 मई के संपादकीय 'भरोसा बढ़ेगा' के संदर्भ में है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में बैठक की। उन्होंने साइकल की सवारी कर लोगों को पर्यटन के लिए आमंत्रित किया और वहां के तनावपूर्ण माहौल को बदलने का प्रयास किया। अप्रैल में हुई आतंकवादी घटना के कारण जम्मू कश्मीर में पर्यटन पूरी तरह चरमरा गया। सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि वहां इंडस्ट्री का भी विस्तार किया जाए ताकि पर्यटन के साथ अन्य उद्योग-धंधे भी फलें-फूलें और युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री के प्रयास सबको प्रोत्साहित करने वाले हैं। इस प्रदेश की भलाई के लिए ये सकारात्मक विचार कारगर साबित हो सकते हैं।

योगेन्द्र सारस्वत, मंगोलपुरी

[illegible]

दैनिक जागरण

हर चीज की तरह सुख-दुख की भी अपनी आयु होती है

जंगलराज की झलक

बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव बाद हुई भीषण हिंसा के आरोपितों की जमानत रद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जैसी टिप्पणियां कीं, वे ममता सरकार को कठघरे में खड़ा करने के साथ यह भी बताने वाली हैं कि इस राज्य में किस तरह राजनीतिक हिंसा को प्रश्रय दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए आरोपितों की जमानत रद की कि उन्होंने अपनी हिंसक गतिविधियों से विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश की और यह हिंसा लोकतंत्र पर हमला थी। इस हिंसा की सीबीआइ जांच न्यायपालिका के हस्तक्षेप के चलते हो पाई थी। यह अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट की ओर से इस हिंसा के आरोपितों को जमानत देने का जो विरोध सीबीआइ ने किया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए उचित पाया कि अभियुक्तों पर लगे आरोप उसकी अंतरात्मा को झकझोरने वाले हैं। वास्तव में ऐसा ही है। 2021 में विधानसभा चुनाव बाद जैसे ही नतीजों के रुझान आने लगे और यह साफ हो गया कि तृणमूल कांग्रेस फिर सत्ता में आ रही है, वैसे ही इस दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उन लोगों पर टूट पड़ी जिनके बारे में उन्हें संदेह था कि उन्होंने विरोधी दलों और खासकर भाजपा को वोट दिया है। ऐसे लोगों के घर जलाए गए, दुकानें लूटी गईं, महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। इस आतंक को देखकर भी बंगाल पुलिस मूकदर्शक बनी रही। उसने उन लोगों की भी मदद नहीं की, जो उससे सहायता मांगने गए। पुलिस ने उन्हें सुरक्षित क्षेत्र जाने की सलाह दी। बेबस लोग अपनी जान बचाने के लिए असम तक पलायन कर गए।

चुनाव बाद की भयानक हिंसा पर ममता बनर्जी का कहना था कि उस समय तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ली थी और चुनाव आयोग को हिंसा रोकनी चाहिए थी। इसे बहानेबाजी के अलावा और क्या कहा जाए। वैसे भी उनके शासनकाल में वैसी राजनीतिक हिंसा आम हो गई है, जैसी कभी वाम दलों के समय होती थी। इसका ताजा उदाहरण कुछ दिनों पहले वक्फ कानून के विरोध के बहाने मुर्शिदाबाद के हिंदुओं के खिलाफ भीषण हिंसा है। इस हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से गठित समिति की चंद दिन पहले आई रिपोर्ट यही कह रही है कि यह हिंसा तृणमूल कांग्रेस नेताओं के कहने पर की गई और उस समय भी पुलिस मूकदर्शक बनी रही। इसका अर्थ यही निकलता है कि तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक विरोधियों को आतंकित करने वाले तत्वों को संरक्षण दे रही है और अब ऐसे तत्व बेलगाम हो गए हैं। आखिर मुर्शिदाबाद के हिंदुओं का वक्फ कानून से क्या लेना-देना था? इस हिंसा पर ममता का यह कहना था कि इसकी साजिश भाजपा और बीएसएफ ने रची। अच्छा हो कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में जंगलराज जैसी स्थितियों के निदान पर भी विचार करे।

योग नीति

उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में कैबिनेट के माध्यम से देश की प्रथम योग नीति स्वीकृत की है। यह निश्चित रूप से योग के प्रचार-प्रसार में सहायक साबित होगी। उत्तराखंड को भारत की आध्यात्मिक और योग परंपरा की भूमि माना जाता है। यह प्राचीन समय से ऋषि मुनियों और साधकों की साधना स्थली रही है। उत्तराखंड में वर्तमान में ऋषिकेश, चंपावत और कौसानी में योग साधना के प्रमुख केंद्र हैं, जहां देश-विदेश के साधक योग सीखने और ध्यान लगाने के लिए आते हैं। अब सरकार उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी के रूप में स्थापित करने पर जोर दे रही है। अच्छी बात यह है कि सरकार ने इसमें दूरदृष्टि का परिचय दिया है और अगले पांच वर्ष, यानी 2030 तक यहां पांच योग हब स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये सभी पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। यहां योग और ध्यान केंद्रों की स्थापना के लिए सरकार ने नीति में 20 लाख रुपये तक के अनुदान की व्यवस्था की है। योग केंद्रों का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने होमस्टे, रिसार्ट, स्कूल एवं कालेजों में योग केंद्र बनाने की स्थिति में योग अनुदेशक को प्रति सत्र 250 रुपये की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था भी की है। इससे संचालकों पर योग अनुदेशकों को रखने पर अधिक व्यय भार नहीं पड़ेगा। सरकार योग नीति के जरिये यह उम्मीद कर रही है कि इससे राज्य में 13 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे। इससे निश्चित रूप से जन सामान्य, विशेष रूप से युवा योग की तरफ आकर्षित होंगे। सरकार को चाहिए कि वह नीति को धरातल पर उतारने की व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि इसका लाभ युवाओं से लेकर प्रदेश को भी मिल सके।

> योग नीति उत्तराखंड को योग एवं वेलनेस का वैश्विक हब बनाने में सहायक साबित होगी

विकसित भारत की कुंजी बनता पूर्वोत्तर

ज्योतिरादित्य सिंधिया

हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र 'लैंड लाक्ड' क्षेत्र से 'लैंड लिंक्ड' और तेज गति से विकास के लिए तैयार इलाके में परिवर्तित हो गया है

हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है, जो कभी भारतीय विकास के मानकों पर हाशिये पर था। प्राचीन कामरूप के व्यापार मार्गों से लेकर उभरते सिलिकान क्षेत्र सहित आज के सेमीकंडक्टर फैब तक, यह क्षेत्र अपना भाग्य फिर से लिख रहा है। इसीलिए हाल में राइजिंग नार्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर की विविधता उसकी सबसे बड़ी ताकत है और विकसित भारत के निर्माण के लिए इस क्षेत्र का विकसित होना बहुत जरूरी है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत 30 ट्रिलियन (लाख करोड़) डालर की अर्थव्यवस्था का निर्माण प्रस्तावित है। इसमें पूर्वोत्तर का योगदान महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उदाहरण के रूप में आज त्रिपुरा के लगभग 10,000 टन गोल्डन क्वीन पाइनएपल (अनानास) की आपूर्ति अनेक देशों में की जा रही है।

ग्यारह साल पहले जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली थी, तब से देश की प्रगति में तेजी आई और पूर्वोत्तर क्षेत्र भी उभर कर सामने आया। प्रधानमंत्री ने एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया और पूर्वोत्तर को भारत की "अष्टलक्ष्मी" घोषित किया। पदभार ग्रहण करने के पहले कुछ महीनों में ही उन्होंने पूर्वोत्तर में कार्य करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने एक दशक लंबे मिशन की नींव रखी, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर को एक उपेक्षित क्षेत्र से बदलकर विकास, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय अवसरों के मामले में देशभर में अग्रणी बनाना था। पूर्वोत्तर का परिवर्तन निवेश के ऐतिहासिक स्तरों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा 10 प्रतिशत सकल बजटीय सहायता के माध्यम से इस क्षेत्र में 6.2 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है। केवल इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि का निवेश किया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के टैक्स डेविएशन को कई गुना बढ़कर 5.74 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। सहायता-अनुदान लगभग दोगुना अर्थात 5.66 लाख करोड़ रुपये हो गया है। भूपेन हजारिका सेतु, बोगीबील ब्रिज या सिलचर-शिलांग फोर-लेन एक्सप्रेसवे, पहाड़ी क्षेत्रों में भारत का प्रथम हाई-स्पीड कारिडोर जैसी परियोजनाओं का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है। मिजोरम में हाल में पूरी हुई बैराबी-सैरंगरेल लाइन आइजोल को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ती है, जिससे हम 2027 तक पूर्वोत्तर प्रांतों की आठ राजधानियों- दिसपुर, ईटानगर, ईंफाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, गंगटोक, अगरतला को रेलवे से जोड़ने के अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंच गए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे ने 80,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और हवाई अड्डों की संख्या नौ से बढ़कर 17 हो गई है। इस तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र 'लैंड लाक्ड' क्षेत्र से 'लैंड लिंक्ड' और भविष्य के लिए विकास के लिए तैयार क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। पूर्वोत्तर में हुए इस परिवर्तन के कारण वहां के सभी राज्यों में निवेशकों का भरोसा जगा है। इस आधारभूत परिवर्तन ने ही राइजिंग नार्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट, 2025 के लिए मंच तैयार किया। यह समिट पूर्वोत्तर के 4.5 करोड़ नागरिकों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ और सामूहिक रूप से 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम रहा। देश-दुनिया में इसे लेकर व्यापक और उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखने को मिली। जापान और यूरोपीय संघ जैसे साझेदारों सहित 80 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। विदेशी राजदूतों और वैश्विक निवेशकों ने भारत के शीर्ष उद्योगपतियों और उद्यमियों के साथ शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिससे पूर्वोत्तर को उनके उद्यमों के लिए अवसर के अगले केंद्र के रूप में वैश्विक पहचान मिली। इस अंचल की विविधता के समान ही इसके विविध क्षेत्रों जैसे कि कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, खेल-कूद और सेवाओं में 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस गति को बनाए रखने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सभी आठ राज्यों में निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों की स्थापना की सुविधा प्रदान की है, ताकि सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और निवेशकों को निर्बाध सहायता प्रदान की जा सके। आठ मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व वाली एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स प्रत्येक राज्य की विशिष्टता के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय कार्यनीतियां बना रही हैं। ये नीतियां प्रधानमंत्री के त्रि-आयामी सिद्धांत- एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट और एक्ट फर्स्ट के अनुरूप भी हैं।

अवधेश राजपूत

पूर्वोत्तर अब दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार और भारत-प्रशांत कार्यनीति के लिए एक महत्वपूर्ण सूत्रधार बन गया है। अंतरराष्ट्रीय शहरों से अपनी अनूठी भौगोलिक निकटता के साथ पूर्वोत्तर भारत की आर्थिक कूटनीति और व्यापार एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण गलियारा है। गुवाहाटी और अगरतला जैसे शहर भौगोलिक रूप से भारतीय महानगरों की तुलना में दक्षिण पूर्व एशियाई केंद्रों के करीब हैं, जिससे पूर्व की ओर आर्थिक एकीकरण को बल मिलता है। इस क्षेत्र के विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को समर्थन देने के लिए कनेक्टिविटी को उन्नत एयर कार्गो सुविधाओं जैसे विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा सुदृढ़ किया जा रहा है। भारत-म्यांमार-थाइलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी-माडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट और सित्तवे बंदरगाह जैसी परियोजनाएं इस क्षेत्र को दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे आगे भौतिक, वाणिज्यिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ने के लिए समेकित कार्यनीति बनाती हैं। जैसे-जैसे पूर्वोत्तर राज्यों की आठ राजधानियां वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत होने की तैयारी कर रही हैं और इसके गलियारे प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे यह क्षेत्र उभर रहा है और इसके साथ ही एक नया भारत भी उभर रहा है।

(लेखक केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं)
response@jagran.com

गढ़ी हुई छवियों से मुक्त हों स्त्री-पुरुष

क्षमा शर्मा

ऐसी धारणाओं से यथाशीघ्र मुक्ति पाई जाए कि स्त्रियां घर में रहने के लिए हैं और पुरुष बाहर काम करने के लिए

हाल में उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया। यह कुछ वर्ष पहले की एक मार्ग दुर्घटना से संबंधित है। एक महिला पति और दो बच्चों के साथ बाइक पर जा रही थी। रास्ते में बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पत्नी बुरी तरह से घायल हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां दो दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। पति ने मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में मुआवजे की मांग की। इसके अंतर्गत दुर्घटना के तीन साल के भीतर क्लेम डालना पड़ता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ती है और ट्रिब्यूनल के सामने सारे कागजात पेश करने पड़ते हैं। बाइक चलाने वाले व्यक्ति ने इसी आधार पर क्लेम मांगा, लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि चूंकि वह 40 वर्ष का सक्षम पुरुष है, इसलिए मुआवजे का हकदार नहीं। हां, बच्चे जरूर इसके हकदार हैं। बीमा कंपनी ने भी इसी आधार पर मुआवजा देने का विरोध किया। तब यह मामला हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पति की कमाई का कोई प्रमाण नहीं है और वह पत्नी पर ही आश्रित था तो बच्चों के साथ उसे भी आश्रित मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पति को 17 लाख 84 हजार रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का उक्त निर्णय यही स्पष्ट करता है कि पति को भी पत्नी पर आश्रित माना जा सकता है।

हमारे यहां अभी तक यही माना जाता है कि पति तो कभी पत्नी पर आश्रित हो ही नहीं सकता। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय समाज को भी एक संदेश है। विवाह और तलाक के मामलों में यह कानून पहले से है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और महिलाओं से जुड़े कानूनी मामलों के विशेषज्ञ अरविंद जैन इसे यह कहकर स्पष्ट करते हैं कि तलाक के मामलों में धारा 125 के अंतर्गत यदि पत्नी कमाऊ है और पति उस पर आश्रित है या फिर विकलांग है तो वह गुजारा भत्ता पाने का हकदार है, क्योंकि यह धारा जेंडर न्यूट्रल है। हालांकि तलाक के मामलों में कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी खूब कमाती थी, लेकिन तलाक के बाद वह पति से गुजारा भत्ता मांगने लगी। ऐसे मामलों का एक बड़ा कारण समाज में यह सोच व्याप्त होना भी है कि यदि कोई पुरुष है तो उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा ही इतनी अच्छी होगी कि वह पत्नी के सामने कभी कमजोर नहीं माना जा सकता। हमारे तमाम आख्यान, कहावतें और मुहावरे भी पुरुषों की ऐसी ही छवि बनाने में योगदान देते हैं। जैसे, अरे मर्द होकर रोते हो? क्यों महिलाओं की तरह आंसू बहाते हो? क्या पुरुषों को किसी बात का दुख नहीं होता और क्या वे कभी व्यथित नहीं होते? वे भी हाड़-मांस के मनुष्य हैं, रोबोट नहीं। आखिर उन्हें अपनी भावनाएं क्यों नहीं व्यक्त करनी चाहिए? कई बार तो पुरुषों को कमजोर साबित करने के लिए उन्हें चूड़ियां भेंट की जाने लगती हैं। आज भी जिन नेताओं से लोग नाराज होते हैं, उन्हें चूड़ियां भेंट करने लगते हैं कि लो इन्हें पहनकर घर में बैठ जाओ। क्या जो महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं, वे कमजोर होती हैं। यह एक गर्हित सोच है।

महिलाओं के साथ पुरुषों के प्रति भी सोच बदले। इमेजेज बाजार

क्या जो स्त्रियां घरों में रहती हैं, वे कुछ नहीं करतीं? वे तो 16-18 घंटे तक काम करती हैं। वे खेतों पर मेहनत करती हैं। गांवों में पशु उन्हीं के भरोसे पलते हैं। उन्हें कभी साप्ताहिक अवकाश या और कोई छुट्टी नहीं मिलती। अब तो वे घर संभालने के साथ नौकरी कर पैसे भी कमा रही हैं। इसके बाद भी पुरुषों को लेकर रूढ़िवादी नजरिया नहीं बदला है। पुरुष माने कमाऊ, ताकतवर, कभी न डरने वाला। इसीलिए ऐसे उलाहनों की भी कमी नहीं कि अरे, बीबी के सामने हाथ फैला रहे हो, बीबी के टुकड़ों पर पलोगे, जोरू के गुलाम। ऐसे उलाहने एक गंभीर समस्या के सूचक हैं। इसी तरह सदियों से बनी हुई यह धारणा भी एक बड़ी समस्या है कि स्त्रियां घर में रहने के लिए हैं और पुरुष बाहर काम करने के लिए।

यह अच्छा है कि न्यायालयों का रवैया बदल रहा है और "जाली एलएलबी-2" और "की एंड का" जैसी फिल्में भी बन रही हैं, जिनमें घर में रहने वाले पति भी दिखाए जाते हैं। जाली एलएलबी-2 में अभिनेता अक्षय कुमार वकील हैं, लेकिन घर आकर खाना बनाते हैं। की एंड का में घर संभालने वाला पति है और नौकरी करने वाली पत्नी। पत्नी ही नहीं, पति भी घर संभाल सकता है। खाना बना सकता है। घर पर रहकर उसी तरह बच्चों की देखभाल कर सकता है, जैसे पत्नी करती है। पत्नी भी बाहर निकलकर पैसे कमा सकती है और उसकी कमाई से घर भी चल सकता है। उसके हाथ सिर्फ मेहंदी रचाने और चूड़ियां पहनने भर के लिए नहीं बने। स्त्री कमजोर या मामूली बात से मुरझाने वाली नहीं होती। वह भी कार्यस्थलों पर अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोग महिलाओं और पुरुषों की एकतरफा छवि से परेशान रहे हैं। अब भी हैं। स्त्री और पुरुष, दोनों ने इसका दंड भोगा है। समाज की यह जकड़न जितनी जल्दी टूटेगी, उसका लाभ स्त्रियों और पुरुषों के साथ पूरे समाज एवं देश को मिलेगा। गढ़ी हुई छवियां महिलाओं, पुरुषों के साथ समाज का भी नुकसान करती हैं। भलाई इसी में है कि इन पुरानी छवियों से शीघ्र मुक्ति पाई जाए, क्योंकि यदि स्त्री आर्थिक रूप से कमजोर हो सकती है तो पुरुष भी।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अपेक्षा

अपेक्षा रखना एक सामान्य मानवीय स्वभाव है। दूसरों से अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक बच्चे के मन में भी माता-पिता से अपेक्षा होती है कि उसकी भूख-प्यास का ध्यान रखा जाएगा। जैसे-जैसे उसका जीवन आगे बढ़ता है, परिवार, समाज और सरकार से उसकी अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती हैं। हमारी अपेक्षाओं पर सभी लोग खरे नहीं उतर सकते, और जब ये पूरी नहीं होतीं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव हमारी गुणवत्ता पर पड़ सकता है। यह हमारे जीवन के दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। व्यक्ति हर स्थिति में सबसे अच्छा चाहता है, और ऐसा न होने पर निराशा उत्पन्न होती है।

अपेक्षा के भंग होने की पीड़ा को सहन करना आवश्यक है, और इसे कर्म फल या प्रारब्ध के रूप में देखा जाना चाहिए। यह मान लेना कि जहां अपेक्षाएं हैं, वहां दुख है, सहज है। फिर भी, संसार के प्रति एक खुले दृष्टिकोण को अपनाना कठिन नहीं है। दूसरों से अपेक्षा रखने से पहले हमें अपनी सामर्थ्य, काबिलियत और सीमाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। अपेक्षाओं के पूर्ण न होने पर सहज रहना किसी योग से कम नहीं है।

यह भी सच है कि जहां आपकी अपेक्षाओं का मूल्य नहीं, वहां से दूर हो जाना ही बेहतर होता है। उम्र के साथ अपेक्षाएं भी कम होती जाती हैं, और सब व्यर्थ सा लगने लगता है। अपने को व्यस्त रखना, प्रियजनों के साथ समय बिताना और ध्यान में लीन होना इस दुख का समाधान है। जहां प्रेम होता है, वहां अपेक्षाओं का कोई स्थान नहीं होता। आपका आशावादी सोच धीरे-धीरे आपको परिवार और समाज की एक मजबूत कड़ी बनाने में मदद कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो अपेक्षाओं में लिप्त न होकर सहनशीलता का उदाहरण बने, वह आने वाली पीढ़ी के लिए एक सशक्त मार्ग खोलता है।

छाया श्रीवास्तव

चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र

प्रदीप

परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से चंद्रमा पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोगों और रोबोटिक मिशनों को स्थाई ऊर्जा मिल सकेगी

चीन और रूस मिलकर 2035 तक चंद्रमा पर एक स्वचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हाल में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकास्मोस और चीन के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (सीएनएसए) के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि यह परियोजना न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ेगी, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को भी नई दिशा देगी।

यह प्रस्तावित परमाणु संयंत्र इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन (आइएलआरएस) का एक अभिन्न अंग होगा। आइएलआरएस चीन और रूस की साझेदारी में विकसित की जा रही एक दीर्घकालिक अंतरिक्ष परियोजना है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर निरंतर वैज्ञानिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करना है। चूंकि चंद्र सतह पर सौर ऊर्जा सीमित मात्रा में उपलब्ध होती है- विशेष रूप से ध्रुवीय और अंधेरे क्षेत्रों में, इसलिए वहां परमाणु ऊर्जा को एक अधिक विश्वसनीय और स्थाई ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से चंद्रमा पर विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग, डाटा विश्लेषण, संचार नेटवर्क और रोबोटिक मिशनों को स्थाई ऊर्जा मिल सकेगी। इससे न केवल भविष्य के मानव मिशनों की राह आसान होगी, बल्कि चंद्रमा को दीर्घकालिक वैज्ञानिक केंद्र में परिवर्तित करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाया जा सकेगा। आइएलआरएस परियोजना को अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस प्रोग्राम के प्रत्यक्ष प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा जा रहा है। आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) सहित 55 देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां मिलकर 2027 तक चांद की कक्षा में 'गेटवे' नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना पर काम कर रही हैं। यह स्टेशन चंद्र सतह पर मानव मिशनों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए एक आधार के रूप में कार्य करेगा।

हालांकि चीन और रूस को चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना होगा। चांद की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियां, जैसे अत्यधिक तापमान, विकिरण और निर्वात इस परियोजना को जटिल बनाते हैं। इसके अलावा, परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित उपयोग और अंतरिक्ष में इसके परिवहन की प्रक्रिया भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि चीन और रूस की अंतरिक्ष एजेंसियों ने हाल के वर्षों में अपनी तकनीकी क्षमताओं का लोहा मनवाया है। ऐसे में यह आशा की जा रही है कि यह परियोजना चांद पर स्थाई मानव उपस्थिति और उसके संसाधनों के उपयोग को लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण के अगले चरण को परिभाषित करेगी।

(लेखक विज्ञान संचारक हैं)

मेलबाक्स

न्यायपालिका का साहसिक हस्तक्षेप

'मुर्शिदाबाद हिंसा का डरावना सच' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में अवधेश कुमार ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर हाई कोर्ट समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस-प्रशासन की विफलता का गहन विश्लेषण किया है और इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक और शर्मनाक स्थिति के रूप में प्रस्तुत किया है। जब राज्य मौन हो जाए, प्रशासन बहरा बन जाए, और पुलिस अंधी-तब जनता किसके पास जाए? मुर्शिदाबाद की हिंसा ने एक बार फिर इस प्रश्न को हमारे राष्ट्रीय विवेक के समक्ष रख दिया है, लेकिन इस बार उत्तर आया अदालत से। कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट ने उस चुप्पी को चीरा है, जो राज्य के गलियारों में गूंजती रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस को हिंसा की पूर्व सूचना थी। फिर क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्यों अल्पसंख्यक वोटबैंक की राजनीति के चलते बहुसंख्यकों को असुरक्षित छोड़ा गया? यह एक सामाजिक अन्याय नहीं, बल्कि संवैधानिक अपराध है और इसी अपराध पर न्यायपालिका की दृष्टि पड़ी है। इस रिपोर्ट को पढ़ना केवल तथ्यों को जानना नहीं है-यह एक व्यवस्था का पोस्टमार्टम है। आज आवश्यकता है कि यह रिपोर्ट पूरे देश की विधानसभा और संसद की मेज पर रखी जाए, क्योंकि यह केवल बंगाल की त्रासदी नहीं, भारत के लोकतांत्रिक ताने-बाने पर लिखी एक लाल चेतावनी है। लेखक को राज्य के साथ ही केंद्र सरकार से भी सवाल पूछने चाहिए थे। आखिर सरकारों की तो जिम्मेदारी बनती है। उसने क्यों राज्य के लोगों को अधर में छोड़ दिया। बंगाल सरकार से इसके लिए जवाब तलब करना चाहिए था। उसे राष्ट्रपति शासन का विकल्प आजमाना चाहिए था।

awanishg30@gmail.com

बड़े लक्ष्य की ओर भारत

वैश्विक महाशक्तियां भारत को आर्थिक और सैन्य रूप से सशक्त होते नहीं देखना चाहतीं। पाकिस्तान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह बिना विदेशी उकसावे के भारत को परमाणु धमकी देने का दुस्साहस कर सके। भारत ने हाल के वर्षों में सैन्य मोर्चे पर अपनी मजबूती सिद्ध की है, जो गर्व का विषय है। हालांकि कई नागरिकों और विपक्षी दलों की भावनाएं इस बात पर आहत हो सकती हैं कि भारत ने गुलाम कश्मीर (पीओके) पर निर्णायक कदम उठाने का अवसर क्यों छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी नीति का उद्देश्य केवल तात्कालिक विजय नहीं, बल्कि विकसित भारत का दीर्घकालिक लक्ष्य है। यदि युद्ध लंबा खिंचता, तो विकास की गति बाधित होती। ऐसे में सीमाई संतुलन और आंतरिक विकास में सामंजस्य आवश्यक है। आज का भारत युद्ध में नहीं, बल्कि तकनीक, शिक्षा, आर्थिक प्रगति और वैश्विक नेतृत्व में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की दिशा में अग्रसर है। यदि दुश्मन भारत पर युद्ध थोपने का दुस्साहस करता है, तो भारत पूरी तरह समर्थ है।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार, हरियाणा

दुष्टों की परवाह करने की जरूरत नहीं

भारत को अपनी सैन्य शक्ति और आर्थिक व्यवस्था की मजबूती के साथ-साथ अपने मित्रों की दोहरी नीतियों पर भी ध्यान देना होगा। आपरेशन सिंदूर से दुनिया को यह स्पष्ट हो गया है कि भारत सैन्य शक्ति में कितना मजबूत है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम इसलिए नहीं किया कि ट्रंप ने बिचौलिए की भूमिका निभाई, बल्कि मोदी सरकार जानती है कि युद्ध कितने हानिकारक होते हैं। भारत को अमेरिका, चीन और पाकिस्तान जैसे चोर-चोर मौसेरे भाइयों से सावधान रहना चाहिए। जब हमारी नियत साफ हो, तो हमें अपनी सफलता की मंजिल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली और युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए, पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह विमान आधुनिक तकनीक से तैयार होगा और इसकी रफ्तार लगभग 2500 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यदि यह सफलतापूर्वक कार्य करता है, तो वर्ष 2034 तक यह हमारे बेड़े में शामिल हो सकता है, जिससे देश का धन अन्य देशों में जाने से बचेगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन ... R.N.I. No. DELHIN/2017/74721
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721

271 किलोमीटर है बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा, परंतु भारत के लिए रणनीतिक रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

सतीश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, इग्नू, नई दिल्ली

डा. अमृता बनर्जी
अ. प्रो., केएन विवि, आसनसोल, बंगाल

बांग्लादेश-म्यांमार सीमा

भारत विरोधी साजिश रचने का नया अड्डा

बांग्लादेश की राजनीति पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ी है। बांग्लादेश के भीतर विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है। सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां से कट्टरपंथ की अंधेरी सुरंग शुरू होती है। पाकिस्तान 75 वर्षों से इसी सुरंग में फंसा हुआ है। बांग्लादेश के आंतरिक हालात, पाकिस्तान के साथ उसकी बढ़ती निकटता एवं म्यांमार की कुछ हालिया गतिविधियां यह सब समझने के लिए पर्याप्त है कि बांग्लादेश-म्यांमार सीमा पर किस प्रकार भारत विरोधी षड्यंत्र रचा जा रहा है

बांग्लादेश-म्यांमार सीमा क्षेत्र भारत विरोधी षड्यंत्र रचे जाने के लिए उपयोग में लाए जाने की आशंका गहरा गई है। फाइल

बांग्लादेश की आंतरिक दशा निरंतर कमजोर हो रही है। आर्थिक रूप से भी वह दुर्बल हो रहा है। मोहम्मद यूनुस से वहां की सेना के संबंध ठीक नहीं हैं। छात्र संगठन को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और उसे सत्ता तक ले जाने की चर्चा है। भारत के लिए यह सब चिंता का विषय इसलिए भी है, क्योंकि बांग्लादेश-म्यांमार सीमा पर भारत विरोधी मुहिम की झलक दिखाई दे रही है।

दरअसल यह सब एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है, यदि सामरिक समीकरण के विभिन्न पहलुओं को एक साथ जोड़ कर देखा जाए। बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा महज 271 किलोमीटर की है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर भारत के लिए। भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों की सीमाएं दोनों देशों से मिलती हैं। मिजोरम की सीमा दोनों देशों से मिलती है। म्यांमार के तीन जिले जो अशांत हैं, इसी सीमा पर स्थित हैं। बांग्लादेश का कावस बाजार दूसरी तरफ है। भारत के उत्तरपूर्वी राज्यों के साथ पांच देशों की सीमाएं मिलती हैं: चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार। सबकुछ चीन के इशारे पर करने की तैयारी है।

भारत की ओर निशाना : पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद के समीकरण को देखते हुए चीन के लिए बड़ा आसान था कि विमर्श को पश्चिमी सीमा से हटाकर पूर्वी सीमा तक खींचा जाए। चीन की मंशा भारत को युद्ध जैसी स्थिति में घेरने की रही है। भारत ने अपनी शक्ति और कुशल कूटनीति के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी लिया और पुनः अपनी आर्थिक विकास की गति तेज करने की शुरुआत भी कर दी। युद्ध की सतर्कता और आर्थिक मापदंड एक साथ आगे बढ़ते दिखाई देने लगे। बाहरी ताकतों को यह सब चुभने लगा, खासकर चीन को। इसलिए चीन पाकिस्तान की मदद से भारत के उत्तरपूर्वी सीमा पर भारत विरोधी टीम बनाने में जुटा हुआ है, जिसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहरा बन रही है और स्टूडेंट्स विंग को भारत के विरुद्ध तैयार कर रही है। संसाधन चीन के द्वारा भेजा जा रहा है, ट्रेनिंग पाकिस्तान के द्वारा दी जा रही है और जमीन बांग्लादेश व म्यांमार का प्रयोग किया जा रहा है। चूंकि आज दुनिया की निगाहें भारत की पश्चिमी सीमा पर हैं, चर्चा कश्मीर की हो रही है, लेकिन मंच पूर्वी सीमा पर तैयार किया जा रहा है। इसलिए यह भारत के लिए चिंता का सबब है। राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक असंतोष के बढ़ते प्रभाव ने कई छात्र संगठनों को हिंसक गतिविधियों के लिए प्रेरित किया।

आतंकी गतिविधियों का संचालन : पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने बांग्लादेश में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं, जिससे भारत की पूर्वोत्तर सीमा पर खतरा बढ़ गया है। आइएसआइ बांग्लादेश को आतंकी गतिविधियों के लिए लांचपैड के रूप में उपयोग करने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेश की पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों ने भारत के लिए रणनीतिक चुनौतियां उत्पन्न की हैं। यह त्रिकोणीय गठबंधन भारत की क्षेत्रीय स्थिति को कमजोर कर सकता है। म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के कई विद्रोही समूहों ने म्यांमार में शरण ली है और वहां की सैन्य जुंटा के साथ समझौते किए हैं। इन समूहों को म्यांमार के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में ठिकाने बनाने की अनुमति दी गई है, जिससे वे भारत के खिलाफ गतिविधियां संचालित कर सकते हैं।

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव : म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध के बीच चीन की भूमिका जटिल और बहुआयामी रही है। बीजिंग ने एक ओर म्यांमार की सैन्य सरकार (जुंटा) को समर्थन दिया है, वहीं दूसरी ओर कुछ जातीय विद्रोही समूहों के साथ भी संपर्क बनाए रखा है। इस दोहरी रणनीति का उद्देश्य क्षेत्र में अपने आर्थिक और रणनीतिक हितों की रक्षा करना है। विश्लेषकों का मानना है कि चीन म्यांमार में 'डिवाइड एंड रूल' की नीति अपना रहा है। वह एक ओर सैन्य सरकार को समर्थन देता है, तो दूसरी ओर विद्रोही समूहों के साथ भी संपर्क बनाए रखता है। इस रणनीति का उद्देश्य म्यांमार में स्थिरता कायम रखना और अपने आर्थिक हितों, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता और उग्रवाद की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, जिसमें बाहरी शक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इन शक्तियों ने विभिन्न तरीकों से उग्रवादी समूहों को समर्थन प्रदान किया है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चीन ने ऐतिहासिक रूप से पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी समूहों को समर्थन प्रदान किया है। हाल के वर्षों में, चीन पर म्यांमार स्थित विद्रोही समूहों के माध्यम से भारतीय उग्रवादियों को हथियार और शरण देने का आरोप लगा है। म्यांमार की सीमा से सटे क्षेत्रों में कई उग्रवादी समूहों ने अपने ठिकाने बनाए हैं।

चीन की साजिश : वस्तुतः चीन भारत की सीमाओं पर अस्थिरता क्यों चाहता है? चीन चाहता है कि भारत सीमावर्ती क्षेत्रों- विशेष रूप से लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार सैन्य और राजनीतिक दबाव में रहे। इससे भारत अपने अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए। भारत को दक्षिण चीन सागर, इंडो-पैसिफिक रणनीति, ताइवान मुद्दे या क्वाड जैसी पहलों में मुखर भूमिका से रोकना। चीन का दक्षिण एशिया में खेल एक बहुस्तरीय रणनीति है जो भू-राजनीति, भू-अर्थशास्त्र, सैन्य कूटनीति और रणनीतिक दबावों पर आधारित है। चीन निश्चित रूप से एक बड़ी आर्थिक और सैनिक ताकत है। चीन की मंशा बंगाल की खाड़ी में अपनी शक्ति को मजबूत बनाना है। लेकिन इसी दौर में भारत ने भी अपनी सैन्य शक्ति का परिचय दिया है, जिससे विश्व चकित है। आज भारत के प्रति अमेरिका और पश्चिम का दोहरा सोच भी उजागर हुआ है। परमाणु परीक्षण के बाद भी इन देशों की नियत और दृष्टि ठीक ऐसी ही थी, जैसी आज है। लेकिन कुछ महीनों में संदेह का बादल छंट गया और भारत की महिमा स्थापित हुई। विश्व शांति की भारतीय अवधारणा के लिए यह परीक्षा की घड़ी है, वहीं आर्थिक विकास भी आवश्यक है। ऐसे में चीन भारत को परेशान करता रहेगा, लिहाजा इससे बचाव के उपाय भी करने ही होंगे।

संघर्षरत बलूच समुदाय का सहयोग करे भारत

कर्नल जी. एम. खान
पूर्व सैन्य अधिकारी

पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत आज जिस दौर से गुजर रहा है, वह केवल किसी क्षेत्रीय असंतोष की कहानी नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के गंभीर हनन और राजनीतिक उत्पीड़न का प्रतीक बन चुका है। दशकों से जारी शोषण, सैन्य दमन, जबरन गुमशुदगियां, सांस्कृतिक दमन और सामाजिक बहिष्कार ने बलूच जनमानस में अलगाव की भावना को गहरा कर दिया है। बलूचिस्तान की मांगें अब केवल आर्थिक या प्रशासनिक अधिकारों तक सीमित नहीं रहीं, वे अब स्वायत्तता और स्वतंत्रता की दिशा में संकेत दे रही हैं। बलूच नेताओं और संगठनों ने बार-बार अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई है, और कई बार भारत से भी समर्थन की अपेक्षा जताई है। भारत के लिए यह केवल एक रणनीतिक प्रश्न नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व का विषय बनता जा रहा है।

भारत ने अतीत में तिब्बत के मुद्दे पर साहसिक रुख अपनाया था। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के पश्चात उनकी निर्वासित सरकार को भारत ने शरण दी। फिर 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद भारत ने तिब्बती शरणार्थियों की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स (एसएफएफ) का गठन किया। इस फोर्स ने कारगिल और गलवन जैसी घटनाओं में अपनी ताकत साबित की, और यह भारत की एक कारगर रणनीति का प्रतीक बनी।

सवाल यह है कि क्या भारत अब बलूचिस्तान के लिए ऐसा ही कुछ कर सकता है? इस संदर्भ में दो पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। पहला, क्या भारत बलूच शरणार्थियों और कार्यकर्ताओं को संगठित कर एसएफएफ की तर्ज पर एक विशेष बलूच फोर्स का समर्थन कर सकता है? और दूसरा, क्या भारत में एक निर्वासित बलूच सरकार को स्थान और मान्यता दी जा सकती है, जिससे बलूच आंदोलन को एक राजनीतिक और वैध अंतरराष्ट्रीय स्वरूप मिल सके?

इन दोनों प्रस्तावों के अपने रणनीतिक लाभ हैं। इससे पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव पड़ेगा, भारत की छवि एक न्यायप्रिय लोकतंत्र के रूप में और मजबूत होगी। साथ ही, पाकिस्तान-चीन के साझा आर्थिक हित, विशेषकर सीपीईसी परियोजना पर व्यावहारिक प्रभाव भी पड़ेगा। बेशक, यह मार्ग संवेदनशील और जटिल है। पाकिस्तान और चीन जैसे देश भारत पर 'हस्तक्षेप' का आरोप लगा सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया भी मिश्रित हो सकती है। परंतु यदि भारत इस भूमिका को मानवाधिकारों के समर्थन के रूप में प्रस्तुत करे, तो यह कदम न्यायसंगत सिद्ध हो सकता है। भारत यदि स्वयं को मानवाधिकारों, लोकतंत्र और न्याय का समर्थक मानता है, तो उसे ऐसे संघर्षरत समुदायों के पक्ष में खड़ा होना होगा, विशेषकर तब, जब वह समुदाय स्वयं भारत से समर्थन की अपेक्षा कर रहा हो। बलूचिस्तान केवल एक भूगोल नहीं, वह उन आवाजों का प्रतीक बन चुका है जिन्हें कुचला गया है। भारत यदि इस समय मौन रहा, तो एक बड़ा रणनीतिक अवसर चूक जाएगा।

खरी-खरी

बैलेंस बनाकर चलिए

राजेंद्र कुमार सिंह

जहमतलाल को सरकारी नौकरी मिली, यह सुनकर अनेक लोगों ने अपना सिर धुन लिया। पढ़ने में बिल्कुल नार्मल लड़का था। लेकिन लफंगई में टाप था। कैसे यह परीक्षा पास करके एक महत्वपूर्ण, एक खास नौकरी में चला गया, अभी तक किसी को भनक नहीं लगी।

जहमतलाल से जब कोई पूछता तो यही कहता नौकरी के रेस में प्रतिस्पर्धा फेस करने की टेक्नोलाजी आ गई तो वह जग जीत गया। एक बढ़िया विभाग में उसकी नियुक्ति हुई। उसके विभाग में और कई तरह के उपविभाग थे। उसी में एक छापामारी विभाग था। जहमतलाल उसी विभाग में पोस्टेड था। इस सेक्शन में आने-जाने का सही टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन नौकरी में रिस्क था। दिन हो या रात कभी भी ड्यूटी के लिए बुलाया है जा सकता है। बास कभी आधी रात को भी फोन करके बुला लेता था। बहुत कम समय में तैयार होकर निकलना पड़ता था। इसलिए वह रात में ड्यूटी ड्रेस पहन कर ही सोते।

जब-जब जहमतलाल छापा में जाते हैं, उस दिन भरपूर माल कमाते हैं। सपरिवार स्टार मार्का वाले होटल में छककर मुर्ग मुसल्लम के अलावा और बहुत कुछ उड़ाते हैं। हालांकि ऐसा मौका रोज-रोज नहीं मिलता था। लेकिन रात में ड्यूटी ड्रेस में ही सोना जैसे इनकी आदत सी बन गई थी। क्योंकि अल्प समय में तैयार होकर निकलना होता है। साहब की शान में गुस्ताखी न हो और देर करके साहब से माफी मांगना उनके उसूलों के खिलाफ था। कर्मचारियों को बगैर जवाब-तलब किए बिना सेक्शन से हटा दिया जाता है। वहां से कब आपकी सेवा समाप्त हो जाए, कोई ठीक नहीं।

हालांकि सेवा और मेवा की बात की जाए तो पूरे विभाग में देर-सबेर धनवर्षा होती रहती थी। ऐसे तो पैसे के मामले में सभी स्टाफ समृद्ध थे। यह उस समय पता चलता जब बैंक वाले बाबू जमा होते तो बताते कि इन लोगों से प्राप्त भुगतान की राशि इतनी होती है कि उसे बोरियों में भरकर रखना पड़ता है। बाबू भी ऊपर की कमाई पर अपनी बेहयाई दिखाई कहते- आपलोग बैलेंस रखकर चलिएगा तभी आगे बढ़िएगा। इसलिए आगे निकलने के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है।

पोस्ट

दो टूक...साफ सच... वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह बिना लाग-लपेट सीधी बात करते हैं। वास्तव में रक्षा मामलों में यह बेहद जरूरी भी है।
कादंबिनी शर्मा@SharmaKadambini

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने बड़ी बात कह दी। उनकी बात भारत सरकार के लिए एक अलर्ट भी है। हमारे देश का ब्रेन दूसरे देशों में क्यों जा रहा है? हमारी सरकार उन्हें अच्छा वेतन, इंसेंटिव दे सकती है।
जितेंद्र भारद्वाज@journo_jitendra

चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्किये, हमें आने वाले वर्षों में इन सभी देशों के साथ निपटना होगा। इसके लिए एक दीर्घकालिक रणनीति की आवश्यकता है। हम अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें जापान, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, ताइवान और फिलीपींस के साथ निकट संबंध स्थापित करने चाहिए।
प्रकाश सिंह@singh_prakash

शशि थरूर विदेश में पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन इधर कांग्रेस वाले देश में उन्हें बेनकाब कर रहे हैं।
संजय निरुपम@sanjaynirupam

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए?

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या कांग्रेस नेताओं की ओर से शशि थरूर की आलोचना किया जाना जायज है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चर्चा करना चाहता अब भारत से पाक,
क्योंकि वह ब्रह्मोस की देख चुका है धाक।
देख चुका है धाक राख जा रही सहेजी,
सब कुछ होगा ध्वस्त पुनः यदि हमने भेजी।
कर लो कई करोड़ मिसाइल पर तुम खर्चा,
किंतु पाल आतंक न होगी हमसे चर्चा!!
- ओमप्रकाश तिवारी

अरुण अशेष
राज्य ब्यूरो प्रमुख, बिहार

बिहार डायरी

कानून-व्यवस्था फिर से विमर्श के केंद्र में

राजद इस बार विधानसभा चुनाव में कानून-व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बना सकता है। यही वह मुद्दा है, जिसने 20 साल पहले उसे सत्ता से बेदखल कर दिया था। उस समय राज्य में कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया था। जनभावना को समझ कर जदयू के सांसद के नाते नीतीश कुमार राज्य के दौरे पर निकल गए थे। एनडीए ने राज्य की स्थिति को जंगलराज का नाम दिया था। नीतीश कुमार जब जनता के बीच गए तो उन्होंने अपराध के साथ पिछड़ेपन से मुक्ति का नारा दिया था। चारा घोटाला के कारण सत्तारूढ़ राजद की काफी बदनामी हो चुकी थी। यह मान लिया गया था कि अगर एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। यह हुआ भी। वर्ष 2005 में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सरकार ने अपराध नियंत्रण और समग्र विकास के मुद्दे को प्राथमिकता सूची में रखा।

वर्ष 2005 और उसके पहले के बिहार को जिन लोगों ने देखा है, उन्हें आज का बिहार आश्चर्यचकित कर सकता है। सड़क, बिजली, पुल-पुलिया का जाल हो या ऊंची सरकारी गैर-सरकारी इमारतें, साइकिल से छात्र-छात्राओं को स्कूल आते-जाते देखना, ये सब दृश्य नए बिहार की कहानी कह रहे हैं। सरकारी आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि अपराध इस स्तर पर हो रहा है कि आम लोग घर से निकलने से पहले अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाएं। एनडीए के सभी प्रचारक अभी से लोगों को याद दिला रहे हैं कि 2005 से पहले के बिहार की कल्पना कीजिए, जब लोग शाम ढलने के बाद घर से निकलना उचित नहीं समझते थे। रात में कोई आदमी रेलवे स्टेशन पर उतरता था तो घर नजदीक होने के बावजूद वहीं रह कर भोर होने की प्रतीक्षा करता था।

एनडीए यह सब इसलिए याद दिला रहा है, क्योंकि 20-25 या 30 साल के युवा को 2005 के पहले के बिहार की स्थिति ठीक से याद नहीं है। महागठबंधन और विशेषकर राजद ने इन्हीं आयु वर्ग के वोटरों को प्रभावित करने के लिए बता रहा है कि राजद का शासनकाल यदि जंगलराज था तो अभी का शासन मंगलराज नहीं है। विपक्ष के नेता अपराध की हर छोटी-बड़ी घटना पर प्रतिक्रिया देते हैं। प्रायः हरेक दिन अपराध से जुड़ी प्रकाशित खबरों की सूची जारी करते हैं। तेजस्वी के फेसबुक पर अपराध से जुड़े पोस्ट देखे जा सकते हैं। शुरुआत में तेजस्वी ने सरकारी नौकरी और रोजगार का मुद्दा उठाया था। राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली बहालियों का श्रेय वे स्वयं ले रहे थे। बता रहे थे कि 2022-24 के बीच जब वह राज्य सरकार में उप मुख्यमंत्री की हैसियत से शामिल थे, उन्हीं दिनों में सरकारी रिक्तियों को भरने का निर्णय लिया। लेकिन, जल्द ही राज्य सरकार और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनसे यह मुद्दा छीन लिया। सरकार दावा कर रही है कि विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राज्य में सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या 12 लाख तक पहुंच जाएगी। इसी तरह 38 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

प्रदेश में निरंतर हो रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करते नीतीश कुमार। फाइल

कुल मिलाकर सरकारी नौकरी और रोजगार पाने वालों की संख्या 50 लाख हो जाएगी। सकारात्मक पक्ष यह है कि सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं में विश्वास पैदा हो रहा है। यह चुनाव में एनडीए को लाभ पहुंचा सकता है। जहां तक अपराध का प्रश्न है तो इस पर भी नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हत्या की घटनाओं का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि ये अवश्यंभावी घटनाओं की तरह हो रही हैं, जिन्हें रोकना कठिन है। चार दिन पहले पटना में एक युवक की हत्या हुई। पकड़ में आने के बाद हत्यारे ने कहा कि जिसकी हत्या हुई, उस युवक ने उसकी बहन से प्यार किया था। शादी से इन्कार किया तो बहन ने आत्महत्या कर ली। उसने बदला लिया है। इन छिटपुट व्यक्तिगत कारणों के अलावा शराब, बालू और जमीन के कारोबार की आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण भी हत्याएं हो रही हैं। नीतीश कुमार अपराध की छोटी-बड़ी घटनाओं पर नजर रखते हैं। पुलिस के अधिकारी भी सतर्क रहते हैं। कम से कम एक उपलब्धि तो पुलिस के खाते में दर्ज किया ही जा सकता है कि अपराधियों तक वह देर-सबेर पहुंच ही जा रही है।

असल में यह पूरा मामला धारणा का है। राजद की पूरी कोशिश यह धारणा बनाने की है कि राज्य में शांति नहीं है। राजद के 15 साल के शासनकाल के बारे में यही धारणा बन गई थी। पूरा खेल इसी पर निर्भर करता है कि राजद को धारणा बनाने में किस हद तक सफलता मिलती है। वैसे, एनडीए भी राजद के प्रयास को समझ रहा है। यही कारण है कि एनडीए के आम कार्यकर्ता हों या बड़े नेता, विकास की सौ बात करने के बाद राजद शासनकाल में अपराध की स्थिति की याद दिलाने से नहीं चूकते हैं।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस

प्रो. आर. एन. त्रिपाठी
समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग, बीएचयू, वाराणसी

नशे के विरुद्ध जागरूकता

तंबाकू जनित उत्पादों का सेवन धड़ल्ले से किया जाता है, जिसके व्यापक दुष्प्रभाव दिख रहे हैं। इसके विरुद्ध जागरूकता के प्रसार से ही लोगों को इससे विरक्त किया जा सकता है

प्रतीकात्मक

समूचे विश्व में केवल तंबाकू से प्रतिवर्ष 80 लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है। हमारे देश में समाज के मध्यम तथा निचले वर्ग के लोगों में तंबाकू का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थानों में कई बच्चे आधुनिकता का प्रदर्शन करने में तंबाकू का सेवन करने लगते हैं और आगे चलकर उन्हें इसकी लत लग जाती है। उनके जीवन के लिए यह सबसे बड़ी बाधा हो जाती है। बहुत सारे हास्टलों, संस्थाओं के सर्वेक्षण में ऐसी बातें आ रही हैं कि तंबाकू ने युवा पीढ़ी में भीतर ही भीतर अपना आवरण जमा लिया है।

आज विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर हमें जानना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी का मूल कारण क्या है। वस्तुतः सरकार द्वारा स्वयं तंबाकू को अपनी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत माना गया है और तंबाकू एवं गुटखा के कारखाने लगाने के लिए सरकार द्वारा ऋण की स्वीकृति भी दी जाती है। इससे उन्हें व्यापक प्रचार-प्रसार और उत्पादन का भी मौका मिलता है। प्रचार-प्रसार संसाधनों द्वारा भी अपनी आय बढ़ाने के लिए खूब विज्ञापन किया जाता है। टीवी चैनलों पर इसके आकर्षक विज्ञापन चलाए जाते हैं, जिनके प्रभाव में लोग आसानी से आ जाते हैं। मानसपटल पर इसके छा जाने के कारण अक्सर समाज में इसे स्वीकृति मिल जाती है। वैसे भी गलत कार्यों की स्वमेव स्वीकृति मानव स्वभाव है, परंतु सरकार की इस संबंध में जो गाइडलाइन है, तमाम टीवी चैनल अक्सर उसकी अनदेखी ही करते हैं।

बिहार में शराबबंदी का सुपरिणाम : बिहार सरकार द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में यह सामने आया कि शराबबंदी के बाद पारिवारिक विघटन और आपसी विवाद में होने वाली मारपीट की घटनाओं में आधे से अधिक की कमी आई है। निश्चित रूप से यह सकारात्मक परिणाम है और इससे समाज को एक अच्छा संदेश मिलता है। लेकिन इसके लिए प्रत्येक अभिभावक को जागरूक रहना होगा। बच्चों के मन मस्तिष्क में शुरू से ही यह भाव बनाना होगा कि समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको इस दिशा में ले जा सकते हैं, लिहाजा स्वयं को जीवन भर उनसे बचाव करके आगे बढ़ना होगा।

यह दुखद है कि समूचे विश्व में सिगरेट के सेवन का जितना उपभोग किया जाता है, उसका लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा भारत में होता है। भारत में देसी खाने वाली तंबाकू का खैनी, पान मसाले, गुटका मसाला इत्यादि के रूप में भी बहुत मात्रा में सेवन किया जाता है, जो कैंसर का एक प्रमुख कारण बनकर शरीर को दुष्प्रभावित करता है। ग्रामीण जनमानस और अशिक्षित लोगों में यह धारणा फैला दी गई है कि पेट साफ करने के लिए तंबाकू की आवश्यकता होती है, जबकि यह बिल्कुल निराधार तथ्य है।

मनुष्य के अलावा पर प्रकृति के अन्य जीवों की बात की जाए तो गधा भी हरी चीज ही खाता है। गौर करने वाली बात यह है कि वह हर प्रकार के घास खाता है, लेकिन वह तंबाकू कभी नहीं खाता। यदि घास के बीच में तंबाकू का हरा पौधा हो तो भी वह उसे नहीं खाता है।

बचाव ही उपाय है : हमारे देश में तंबाकू के सेवन की आदत अमीर और गरीब दोनों ही वर्गों में है। गरीब लोगों में जहां सुरती, खैनी, बीड़ी आदि के रूप में तंबाकू का प्रयोग किया जाता है, वहीं संपन्न वर्ग के लोग इसे गुटका, पान और सिगरेट के रूप में लेते हैं। कई संबंधित संस्थाओं के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि भारत के 20 प्रतिशत से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू की चपेट में आ गए हैं और भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक लोगों में कैंसर जनित बीमारियां केवल तंबाकू से हो रही हैं। ऐसे में हमें इससे बचने का उपाय सोचना होगा और 'बचाव ही उपाय है' के सिद्धांत पर कार्य करना होगा।

एक अच्छे नागरिक का दायित्व : श्रमशील व्यक्ति थोड़ा सा मानसिक विश्राम या विराम पाने के लिए तंबाकू का प्रयोग करता है, परंतु वह नहीं जानता कि उसके द्वारा लिया जाने वाला थोड़ा सा तंबाकू कितना घातक है। धीरे-धीरे यही तंबाकू उसके शरीर और मन मस्तिष्क में पैठ बना लेती और वह 'लती' हो जाता है अर्थात उसे उसकी आदत हो जाती है और यही आदत उसके विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि आज के दिन यदि हम तंबाकू सेवन करने वाले कम से कम पांच लोगों को इस बारे में बता सकें और इस व्यसन से मुक्ति दिला सकें, तो शायद एक अच्छे नागरिक का दायित्व निभाएंगे।

भारत को महान बनाने के लिए जहां समूचे देश में व्यापक पैमाने पर स्वास्थ्य सुविधाओं में इतना बड़ा विस्तार किया जा रहा है, नशा मुक्ति अभियान जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी इस दिशा में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। हमारा, आपका, एक शिक्षित समाज का, एक भारत के अच्छे नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह लोगों को तंबाकू के सेवन से बचाए, ताकि स्वस्थ और सशक्त भारत बने।

कल्पमेधा

मनुष्य के सभी कार्य इन सात कारणों में से किसी एक या अधिक वजहों से प्रेरित होते हैं : मौका, स्वभाव, मजबूरी या आवश्यकता, आदत, वजह, जुनून तथा प्रबल इच्छा।
- अरस्तु

वाजिब चिंता

दुनिया फिलहाल जिस संवेदनशील दौर से गुजर रही है और भारत के सामने अपने कुछ पड़ोसी देशों के अस्थिर रुख की चुनौतियां खड़ी रहती हैं, वैसे में सुरक्षा का हर मोर्चा हर वक्त पूरी तरह चौकस और दुरुस्त रहना एक अनिवार्य तकाजा है। निश्चित रूप से देश की सरकार ने इस संबंध में कोताही नहीं बरतती होगी। लेकिन यह ऐसा मसला है, जिसमें हमेशा ज्यादा बेहतर करने की जरूरत होती है, कमियों पर ध्यान देना जरूरी होता है। इस लिहाज से देखें तो देश के वायुसेना प्रमुख एअर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने गुरुवार को महत्त्वपूर्ण रक्षा परियोजनाओं के तहत संसाधनों की खरीद और आपूर्ति को लेकर जो सवाल उठाए हैं, उन पर गौर किया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने रक्षा सौदों में आपूर्ति में देरी पर चिंता जाहिर करते हुए घरेलू रक्षा क्षेत्र पर गंभीरता से विचार करने के लिए जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। वायुसेना प्रमुख ने साफ शब्दों में कहा कि इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं के वादे तो किए गए, लेकिन निर्धारित समय में एक भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी। जबकि बढ़ती चुनौतियों और संवेदनशीलता के मद्देनजर देखें तो समय सीमा सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए।

सवाल है कि जिस मसले पर सरकार को अपनी ओर से चुनौतियों की पहचान और उसका हल निकालने की पहल करनी चाहिए, उसकी फिक्र वायुसेना प्रमुख को जाहिर करने की जरूरत क्यों पड़ी। यह छिपा नहीं है कि समूची दुनिया में अलग-अलग देशों के बीच समीकरण किस तेजी से बदल रहे हैं। कारणों पर बहस हो सकती है, लेकिन यह जगजाहिर है कि अचानक पैदा हुई परिस्थितियों में किसी देश के सामने टकराव से लेकर युद्ध तक के हालात में सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौती खड़ी हो सकती है। ऐसे में अगर सैन्य बलों की ओर से परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने पर चिंता जाहिर की जाती है, तो यह सरकार के लिए तत्काल विचार करने और कमियों पर गौर करने का मामला होना चाहिए। वायुसेना प्रमुख की यह बात बेहद अहम है कि युद्ध का चरित्र बदल रहा है तो हर दिन हम नई तकनीकें देख रहे हैं। जाहिर है, इसी मुताबिक खुद को तैयार रखने की जरूरत है।

भारत ने कई मौकों पर इस तरह की चुनौतियों को बेहद करीब से देखा और इसका सामना किया है, जिसमें पाकिस्तान या चीन जैसे पड़ोसी नाहक ही टकराव जैसे हालात पैदा करते रहते हैं। हालत यह है कि पाकिस्तान को किसी भी समय संघर्ष विराम का उल्लंघन करने में हिचक नहीं होती, तो चीन की गतिविधियां भी भारत के लिए चिंता का कारण रही हैं। ऐसे में सीमा पर कब कैसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं, यह तय कर पाना मुश्किल है। ऐसे में अगर लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा तय हो जाए, लेकिन उसकी आपूर्ति और तैनाती के समय को लेकर सजगता नहीं बरती जाए, तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? पिछले कुछ वर्षों के दौरान युद्ध और तकनीकी के मोर्चे पर दुनिया भर में जिस तरह के बदलाव आए हैं, उसमें जरूरत इस बात की है कि सेना को सभी और नए जरूरी साजो-सामान से लैस किया जाए। रक्षा परियोजनाओं के तहत अगर किसी संदर्भ में वादे किए जाते हैं, तो उन्हें समय पर पूरा करने को लेकर भी उतनी ही सजगता होनी चाहिए। रक्षा क्षेत्र में तकनीकी और संसाधनों के विकास के मामले में आत्मनिर्भरता सबसे बेहतर समाधान है, लेकिन तात्कालिक जरूरतों को तुरंत पूरा करने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

आखिरकार इंसाफ

उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में शुक्रवार को अदालत के फैसले से यह साफ है कि अगर जांच की दिशा सही हो और आरोपियों के प्रति कोई रियायत नहीं बरती जाए, तो इंसाफ मिलना संभव है। दरअसल, एक रिजार्ट में काम करके अपने परिवार का सहारा बनी अंकिता की हत्या के बाद जांच का सिरा जिस दिशा में जा रहा था, उसमें तब यह लगा था कि आरोपी बच निकलेंगे। करीब तीन साल पहले अंकिता की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस हत्याकांड का गंभीर पहलू यह भी था कि एक आरोपी रसूखदार नेता का बेटा था। शायद इसीलिए मामले को दबाने की भी कोशिश की गई। लेकिन अदालत के सजग रुख और जांच की दिशा की वजह से तीन आरोपियों को दोषी साबित किया जा सका और उन्हें कोटद्वार की अदालत ने उम्रकैद की सजा दी। इससे पहले इस मामले में विशेष जांच दल यानी एसआइटी भी बनाई गई थी। हालांकि तब उस पर भी सवाल उठे थे और लोगों ने सीबीआइ जांच की मांग की थी। अब अदालत के फैसले के बाद अगर इसे अंकिता के परिवार को इंसाफ मिलने और सच की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो यह स्वाभाविक ही है।

यह फैसला उन परिवारों के लिए एक उम्मीद और राहत है, जिनकी बेटियां घरों से दूर पढ़ने या नौकरी करने निकलती हैं और अपने सपने साकार करना चाहती हैं। यह दुखद है कि आज जिस विकसित और आधुनिक समाज की बात होती है, वहां आज भी स्त्रियों को कई तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। हमारे समाज में बेटियों के लिए जोखिम का दायरा इतना बड़ा है कि कब धोखा देकर, बहला-फुसला कर या दबाव डाल कर या फिर धमका कर उनको शिकार बनाया जाएगा, इसका उन्हें अनुमान तक नहीं होता। एक रिजार्ट में काम करने वाली अंकिता की हत्या इसका स्पष्ट उदाहरण है। अपना भविष्य संवारने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए संघर्ष कर रही युवतियों पर पर घात लगाए पुरुषों के लिए कोटद्वार की अदालत का फैसला स्वागतयोग्य है और एक चेतावनी है कि कानून सबके लिए बराबर है।

वक्त की जरूरत है वर्षा जल संग्रह

मानसून का स्वागत किए जाने का तात्पर्य यह है कि हम बरसात के पानी के सदुपयोग और संरक्षण के प्रति सचेत हों और अपेक्षित तैयारियां रखें। दरअसल, देश में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़ों को देखें, तो समझ में आता है कि वर्षा जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है।

अतुल कनक

मानसून का आगमन हो गया है। बंगलुरु और मुंबई सहित अनेक शहरों में मानसून पूर्व की बारिश होने लगी है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए मानसून के दिनों में होने वाली बारिश महत्त्वपूर्ण होती है। आज भी भारतीय किसानों का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए बरसाती पानी पर ही निर्भर है। आज जबकि दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा शुद्ध पेयजल की नियमित आपूर्ति से वंचित है, तो बरसात का स्वागत किया जाना चाहिए। मानसून हमें वर्षा जल का संग्रह करने का अवसर देता है ताकि भविष्य की जरूरतों के लिए उस कीमती निधि को बचा सकें जिसके लिए रहीम ने बहुत पहले कह दिया था- 'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।'

मानसून का स्वागत किए जाने का तात्पर्य यह है कि हम बरसात के पानी के सदुपयोग और संरक्षण के प्रति सचेत हों और अपेक्षित तैयारियां रखें। दरअसल, देश में पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के आंकड़ों को देखें, तो समझ में आता है कि वर्षा जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। कुछ समय पहले राज्यसभा में बताया गया था कि एक अध्ययन में वर्ष 2021 के लिए भारत में औसत प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1386 घनमीटर आंकी गई जबकि वर्ष 2031 के लिए प्रतिव्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता 1387 घनमीटर रहने का अनुमान है। यह स्थिति चिंता पैदा करती है, क्योंकि 1700 घनमीटर से कम वार्षिक प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता को जल संकट की स्थिति माना जाता है। यों भी भारत में जल वितरण की स्थिति असमान है। कुछ क्षेत्रों में सामान्य तौर पर हमेशा जल की उपलब्धता बनी रहती है, जबकि कुछ इलाकों में, खासकर गर्मी के दिनों में, जरूरत के पानी के लिए भी हिंसक संघर्ष की नौबत आ जाती है। इसका कारण यह है कि भारत में जल संसाधनों की स्थिति एक समान नहीं है।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में लगभग 71 फीसद जल संसाधन देश के 36 फीसद हिस्से में केंद्रित हैं जबकि देश के शेष 64 फीसद क्षेत्र में केवल 29 फीसद जल संसाधन हैं। यानी देश के एक बड़े हिस्से को अपनी जरूरत के पानी के लिए जल संग्रह की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में बरसात का जो पानी व्यर्थ बह जाता है, उसे यदि सहेज लिया जाए, तो आबादी के एक बड़े हिस्से को जलसंकट के कारण होने वाली परेशानियों से बचाया जा सकता है। भारत में औसत वार्षिक वर्षा करीब 115 इंच होती है। मगर इस वर्षा का वितरण भी भारत के अलग-अलग भूभाग में समान नहीं है। महत्त्वपूर्ण यह है कि करीब 8.6 करोड़ हेक्टेयर में भारत की खेती सिंचाई संबंधी सुविधा के लिए बारिश पर ही निर्भर है।

कुछ समय तक बस्तियों, शहरों और गांवों में बरसात के पानी को सहेजने के लिए तालाब, झील, कुएं, बावड़ी, कुंड और जोहड़ बनाए जाते थे। ये जल संसाधन न केवल बरसात के पानी को सहेज कर लोगों को साल भर जरूरत का पानी मुहैया कराते थे, बल्कि संचित पानी से भूजल का स्तर बनाए रखने में भी मदद करते थे। चूंकि इन संसाधनों की सामाजिक उपयोगिता बहुत थी, इसलिए इनके निर्माण को पुण्य कार्य माना जाता था। सक्षम लोग विशिष्ट अवसरों पर जल संसाधनों का निर्माण करवाते थे। राजस्थान के बूंदी जिले के हिंडौली कस्बे के एक तालाब की कथा तो बहुत ही रोचक है। एक बंजारे की बेटी की शादी इस कस्बे में हुई थी। उन दिनों बंजारे घूम-घूम कर व्यापार करते थे और बहुत संपन्न हुआ करते थे। एक दिन किसी बात से क्षुब्ध उस बंजारे की बेटी को उसकी

> **पुराने जलस्रोतों के मार्ग में नई बसावट या नए निर्माण का एक नुकसान यह भी हुआ कि जरा सी बारिश से बस्तियों में जल-जमाव की स्थितियां बनने लगी हैं। महानगरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण नई बस्तियों का निर्माण फिर भी शहरी प्रबंधन की एक बड़ी आवश्यकता माना जा सकता है, लेकिन देश के छोटे-छोटे शहरों में भी मामूली बारिश जल प्लावन का दृश्य उपस्थित कर देती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि शहरों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जमीन पर बारिश के प्रवाह को सहेजने के लिए पुराने समय में जो जलस्रोत बनाए गए थे, उन्हें या तो उपेक्षा के गर्त में धकेल दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया।**

सास ने ताना मारते हुए कह दिया कि 'यहां कौन से तुम्हारे पिता ने पानी का इतना इंतजाम कर रखा है कि तू खूब पानी बहाए।' यह बात बंजारे को पता चली तो वह अपने लश्कर सहित हिंडौली आया और वहां एक तालाब खुदवाने के बाद ही लौटा।

बावड़ियां और कुंड तो जल संग्रह करने के साथ अपने समय के स्थापत्य की समृद्धि का प्रमाण भी देते थे। गुजरात की रानी की बावड़ी अपने स्थापत्य के कारण ही प्रसिद्ध है और दूर-दूर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। पुराने किलों में तो तालाबों के अंदर भी बावड़ियों और कुओं का निर्माण कराया जाता था, ताकि आपात परिस्थिति में संग्रहीत वर्षा जल के कारण लोगों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़े। मध्यप्रदेश के ग्वालियर के निकट नरवर के किले का इतिहास नल-दमयंती के आख्यान से भी जुड़ा है। इस किले में राजा नल के महल के बाहर ही एक विशाल तालाब है और इस तालाब के अंदर भी आठ कुएं और नौ बावड़ियां हैं।

समय के साथ पुराने जल संसाधन उपेक्षा के शिकार हो गए। अधिकतर प्राचीन जलाशय बरसात के पानी के प्रवाह की राह में होते थे। बरसात का पानी बह कर इनमें एकत्र हो जाता था। पश्चिमी राजस्थान में तो ऐसा तंत्र विकसित था कि एक तालाब के भरने पर पानी दूसरे तालाब की ओर बह निकलता था। वर्षा जल संग्रह के प्रति इस क्षेत्र के लोग कितने जागरूक थे, इसका अनुमान जैसलमेर के गड़सीसर तालाब के उदाहरण से लगाया जा सकता है। बरसात के पहले लोग श्रमदान कर इस तालाब की सफाई करते थे। स्वयं शासक इसमें श्रमदान करते थे। पहली बारिश के बाद इस खूबसूरत तालाब में नहाने आदि पर प्रतिबंध था ताकि तालाब का पानी गंदा नहीं हो। समूचे क्षेत्र में इसी तरह से बरसात के पानी के संग्रह और उसकी शुद्धता को बनाए रखने का चलन था। लेकिन जब से पानी नलों के माध्यम से घर-घर पहुंचने लगा, तो लोग इन प्राचीन संसाधनों के प्रति उदासीन हो गए। देश में अधिकांश तालाबों को रिहाइशी बस्तियों के लिए और कुंडों को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए पाट दिया गया। लोगों ने कचरा फेंक-फेंक कर बावड़ियां और कुएं अनुपयोगी कर दिए।

पुराने जलस्रोतों के मार्ग में नई बसावट या नए निर्माण का एक नुकसान यह भी हुआ कि जरा सी बारिश से बस्तियों में जल-जमाव की स्थितियां बनने लगी हैं। महानगरों में बढ़ती जनसंख्या के कारण नई बस्तियों का निर्माण फिर भी शहरी प्रबंधन की एक बड़ी आवश्यकता माना जा सकता है, लेकिन देश के छोटे-छोटे शहरों में भी मामूली बारिश जल प्लावन का दृश्य उपस्थित कर देती है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि शहरों की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए वर्षा जल के प्रवाह को सहेजने के लिए पुराने समय में जो जलस्रोत बनाए गए थे, उन्हें या तो उपेक्षा के गर्त में धकेल दिया गया या अतिक्रमण का शिकार बना दिया गया।

चंबल नदी के किनारे बसे होने के बावजूद राजस्थान के कोटा शहर की अनेक बस्तियों का भूजल स्तर इसीलिए तेजी से गिरा है। अस्सी के दशक के अंत में बनी एक नीति के तहत हर बस्ती में पानी पहुंचाने की नीयत से खूब नलकूप खोदे गए। हमने धरती के गर्भ का पानी अपने सुख के लिए उपयोग करने की नीति तो बना ली, लेकिन भूजल स्तर को बनाए रखने के उपायों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। परिणाम यह है कि भारत के अधिकांश हिस्सों में भूजल तेजी से कम हो रहा है। जब शुद्ध पानी की उपलब्धता समूची मानव जाति के लिए बड़ी चुनौती बनती प्रतीत होने लगी हो, तो अब आवश्यक है कि हम वर्षा जल के संग्रह और संरक्षण के प्रति सचेत हों।

मशीन बनता इंसान

अनुपमा तिवाड़ी

बढ़ता बाजारीकरण हम सबको धीरे-धीरे वस्तु में तब्दील कर रहा है। साथ ही बदलते दौर में शहरीकरण हमें आहिस्ता-आहिस्ता मशीन बनाता जा रहा है, जिसमें हम अपनी सहजता खोते जा रहे हैं। अब तमीज के नाम पर अत्यधिक नाप-तौल कर बोलना, दूसरों से अलग दिखने की चाह रखना और व्यक्ति-व्यक्ति के बीच की दूरी बनाना ही प्रगति का परिचायक बनता जा रहा है। मगर इस सबमें हम, हमारा अपना होना कितना खोते जा रहे हैं, इसका हमें भान भी नहीं है। अब सोशल मीडिया पर हमारा आधे से ज्यादा समय मित्रों को बधाइयां देने में गुजर रहा है, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच संवाद गायब है।

क्या हम याद कर सकते हैं कि हम खुलकर कब हंसे थे? अब हम हंसना भूलते जा रहे हैं। कई बार देखने में आता है कि लोग इसलिए किसी के दुख में शामिल होते हैं कि औपचारिकता निभानी है। शामिल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए दुख के समय भी बहुत से लोग चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन उनकी आंखें और कान कुछ और ही ढूंढ़ रहे होते हैं। इस औपचारिकता में शब्द अपनी गहराई खो रहे हैं। किसी के सुख और दुख में शामिल होना उसे अंदर तक महसूस करना है। इसलिए सोशल मीडिया पर इतने मित्र होने के बावजूद हम कई बार इतनी रिक्तता महसूस करते हैं कि हमें अपने आसपास एक दोस्त नहीं दिखाई देता, जिससे हम मन की बात साझा कर सकें। कितनी ही बार लगता है कि आत्महत्या करनेवाला व्यक्ति अगर अपने मन की बात कह पाता तो शायद ऐसा नहीं होता।

हम हर दिन देखते हैं कि विभिन्न आयोजनों में मंचों पर या ढोल आदि पर नृत्य बेहद औपचारिक दिखाई देते हैं। उनमें वह तड़प दिखाई नहीं देती है। जो नृत्य हमारी आत्मा से होता हुआ शरीर से फूटकर बाहर आता है, वैसा नृत्य कितना स्वाभाविक होता है। ऐसे नृत्य की किसी धुन पर नर्तक का शरीर ही नहीं, रोम-रोम नृत्य करने लगता है। अब समूहों में होने वाले स्वाभाविक लोकनृत्य अपनी समृद्ध परंपरा खोते जा रहे हैं। एक जैसे बेजान नृत्यों की औपचारिकता वह आनंद नहीं देती।

आज सबसे ज्यादा समय हमारा स्मार्टफोन ले रहा है। एक ही कमरे में बैठे उस परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने फोन के स्क्रीन में गुम होते हैं। बच्चों को भी बड़ों को देखकर फोन की ऐसी लत लगने लगी है कि कई बार माताओं को छोटे बच्चों को खाना खिलाते समय भी सेलफोन हाथ में पकड़ाना पड़ता है। बहुत से परिवारों और परिजनों के बीच में महज औपचारिक बातचीत ही हो पाती है, जिससे उनके बीच एक दूसरे को न समझ पाना, कई प्रकार की भ्रांतियों का जन्म लेना, अविश्वास और दूरियां बढ़ते जाना जैसी स्थितियां बन रही हैं, जिनका सीधा रिश्तों पर असर पड़ता है।

आज बाजार इस कदर हावी है कि हम अपने आपको हर तरह से आत्मनिर्भर मानने लगे हैं और यह अब हमारे व्यवहारों से झलकने लगा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। इससे जीवन मूल्यों का भी ह्रास होने लगा है। भौतिक रूप से बने क्लोन पर तो रोक लगने की बातें भी हुई हैं, लेकिन रोबोट में भावनाएं डालने की बात अब की जा रही है। मगर क्या यह रोबोट हमारे सुख, दुख का साथी हो सकता है? आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता का शोर जोरों पर है, लेकिन क्या यह कल्पना की उड़ान और उसके भाव पकड़ सकता है?

बाजार चमक रहे हैं, प्रचार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब त्योहारों का मतलब मिलना-जुलना कम और दिखना-दिखाना होता जा रहा है, जिसमें 'उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे' की बू आती है। हम वस्तुवादी होते जा रहे हैं। कई मर्तबा हमें त्योहारों पर कपड़ों की जरूरत नहीं होती, तब भी हम खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में नए चलन के कपड़े आ रहे हैं। त्योहारों पर मोबाइल या गाड़ी बदलना एक फैशन बनता जा रहा है। हम वस्तुओं में खुशियों को ढूंढ़ रहे हैं। हमारे पास मोबाइल नहीं है या कोई वाहन नहीं है तो इसे लेने का एक तर्क हो सकता है, लेकिन क्या हर बार नया ब्रांड लेना अनिवार्य है? 'इस्तेमाल करो और फेंको' की संस्कृति फल-फूल रही है। ये चीजों का फेंकना ही नहीं है, बल्कि रिश्तों का भी अपने जीवन से निकालना है। हम जैसे चीजों से व्यवहार करते हैं, वह हमारे व्यवहार करने के तरीके का हिस्सा बनता जाता है और फिर वह मानवीय व्यवहारों से भी अछूता नहीं रहता है।

दुनिया मेरे आगे

> **बाजार चमक रहे हैं, प्रचार हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। अब त्योहारों का मतलब मिलना-जुलना कम और दिखना-दिखाना होता जा रहा है, जिसमें 'उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे' की बू आती है। हम वस्तुवादी होते जा रहे हैं। कई मर्तबा हमें त्योहारों पर कपड़ों की जरूरत नहीं होती, तब भी हम खरीदारी कर रहे हैं।**

तकनीक एक सुविधा है, समाधान नहीं है। हमें सहयोग और ज्ञान साझा करने वाली संस्कृति को बचाए रखने की जरूरत है, जिससे आपसी रिश्ते मजबूत हों। जीवन में मुश्किलें हर एक के साथ अलग-अलग तरह की हो सकती हैं, लेकिन हम कैसे सहजता से उनका सामना करते हैं, यही जीवन जीने की कला है। यह कला हम सबके अंदर है, उसे बचाए रखने की जरूरत है। उसकी चमक को धूप और अंधड़ों से बचाए रखना है।

आज कैलकुलेटर मनुष्य से अधिक सटीक तरीके और तेजी से गणना कर सकता है, लेकिन वह उपज मानव की ही है। मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से अवलोकन, सीखने और खोज के द्वारा विकसित हुआ है। मशीनों में कोई भावनात्मकता नहीं है। भावनाएं मानव मस्तिष्क को विकसित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं। मशीन वही कर सकती है, जिसके लिए उसे बनाया गया है। मशीन नया नहीं रच सकती, लेकिन मनुष्य नया रच सकता है। आज मशीनीकरण के चलते नया रचना कम होता जा रहा है। हमें सहयोग और ज्ञान साझा करने वाली ऐसी संस्कृति बनाने की जरूरत है, जिसमें रिश्ते मजबूत हों, उनमें स्नेह बचा रहे। इंसान सिर्फ दिमाग से ही नहीं, बल्कि अपने दिल से भी नियंत्रित होता है। मानव मस्तिष्क और हृदय निकटता से जुड़ा हुआ होता है। ये दोनों मिलकर उसे एक भावनात्मक रूप से संपूर्ण इंसान बनाते हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं।

कर्ज का जाल

पिछले दिनों व्यापार में नुकसान की वजह से एक परिवार ने आत्महत्या कर ली। सच है कि आज व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई, लाइसेंस फीस में वृद्धि, कर्मचारियों के वेतन और आनलाइन का बढ़ता व्यापार ऐसी कई चुनौतियां हैं जिनका व्यापारी वर्ग को सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों के पास व्यापार करने के लिए अपनी जगह है, वे तो फिर भी किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग किराए की जगह लेकर व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए किराया निकलना भी मुश्किल हो रहा है। सरकारी बैंक और निजी कंपनियां भी आसानी से व्यापारियों को ऋण दे देती हैं, बिना यह जांच किए कि लेने वाला इसे चुका भी पाएगा या नहीं। व्यापारी के पास काम कम होने पर वह एक ऋण चुकाने के फेर में दूसरी जगह से कर्ज ले लेता है। अंत में जब वह कर्ज नहीं चुका पाता, तो आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। एक बार कोई इंसान ऋण ले लेता है, तो उसके पास और ज्यादा ऋण लेने के लिए कंपनियों या बैंकों के फोन आने लगते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। मुश्किल में घिरे लोगों को भी सोच समझ कर ही कर्ज लेना चाहिए।

- चरनजीत, नरेला, दिल्ली

असमान विकास

'टूटती उम्मीदें' (संपादकीय, 29 मई) पढ़ा। इसमें इस विरोधाभास को रेखांकित किया गया है कि जब भारत वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक वृद्धि की गाथा लिख रहा है, तो देश के भीतर आम जनता की जिंदगी बद से बदतर क्यों होती जा रही है? इसका कारण यह है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के निचले तबके तक नहीं पहुंच पा रहा है। तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का मतलब केवल जीडीपी के आंकड़ों में वृद्धि नहीं, बल्कि यह भी है कि देश का हर नागरिक उसका हिस्सा बने। इस स्थिति को बदलने के लिए सरकार को समावेशी नीतियों पर काम करना होगा, ताकि आर्थिक विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। वर्तमान आर्थिक नीतियां बड़े कारोबारियों और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचा रही हैं, जबकि आम लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था का लाभ कुछ लोगों तक सीमित है, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग की स्थिति बदतर हो रही है।

- मो अजहर आलम अंसारी, पूर्णिया

सजगता की जरूरत

देश में कोरोना मामले फिर सामने आए हैं। हालांकि चिकित्सा विशेषज्ञ भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार यह जानलेवा नहीं होगा। फिर भी कोरोना का नाम सुनते ही डर जाना स्वाभाविक है। जब दबे पांव कोरोना दस्तक दे रहा है, तो प्रत्येक नागरिक का दायित्व बन जाता है कि इससे बचाव के लिए फूंक-फूंक कर कदम रखे। कोरोना महामारी के चलते पहले भी हमने बहुत कुछ खोया है। पूर्णबंदी के कारण न केवल देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई थी, अपितु लोगों के काम-धंधे तक चौपट हो गए थे। आज भी वे माली हालत से उबर नहीं पाए हैं। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की जरूरत है। जब कोरोना आया था, तो उसने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल-पट्टी खोल दी थी। समय रहते अब उन कमियों को दूर करने की जरूरत है, ताकि नागरिकों को जान से हाथ धोना नहीं पड़े। चिकित्सा तंत्र के साथ-साथ सभी नागरिकों को भी सतर्कता से रहना होगा ताकि कोरोना को मात दे सकें।

- हेमा हरि उपाध्याय,'अक्षत', उज्जैन

बेहाल किसान

देश की पचास फीसद आबादी कृषि कार्य पर निर्भर है। इसके बावजूद विश्व के कुल कृषि उपज निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मात्र 2.4 फीसद तक सिमटी हुई है। भारतीय किसान आज भी परंपरागत कृषि में विश्वास रखते हैं। हमारे यहां तकनीक का इस्तेमाल विकसित देशों की तुलना में कम है। भारतीय किसान कृषि कार्य में जी-तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उपज के रखरखाव, पैकेजिंग और निर्यात पर अधिक मेहनत नहीं करते हैं, जिसकी वजह से किसानों की आय कम है। उचित रखरखाव और भंडारण के अभाव में देश में प्रतिवर्ष कुल अनाज उत्पादन का लगभग 22 फीसद हिस्सा बर्बाद हो जाता है। यह बर्बादी कुल वैश्विक उत्पादन का आठ फीसद है। आज गेहूं और चावल के मामलों में देश आत्मनिर्भर बन चुका है, लेकिन दलहन और तिलहन में विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है।

- हिमांशु शेखर, गया

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

ट्रंप प्रशासन
छात्रों पर प्रहार

ट्रंप प्रशासन ने अचानक अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नए वीसा साक्षात्कार स्थगित कर उनकी अकादमिक योजनाओं में बाधा डाली है। दुनिया भर के अकादमिक क्षेत्रों में उथलपुथल पैदा करने वाले कदम से ट्रंप प्रशासन ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नए वीसा साक्षात्कारों और उनकी नियुक्तियों तथा अतिथियों के परस्पर आदान-प्रदान को अस्थाई रूप से स्थगित रखने का आदेश दिया है। विदेश सचिव मार्को रूबियो की पहल पर लिया गया यह फैसला एक व्यापक योजना का हिस्सा है जिसके अंतर्गत सभी एफ, एम एवं जे वीसा प्रार्थियों की सोशल मीडिया समीक्षा की जाएगी। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने इस कदम को 'अस्थाई' बताया है, लेकिन इसके प्रभाव दूरगामी होंगे। इसका असर छात्रों, अमेरिकन विश्वविद्यालयों और वैश्विक शिक्षा केन्द्र के रूप में अमेरिका की स्थिति पर पड़ेगा। विदेश विभाग ने दुनिया भर में अमेरिकन दूतावासों को निर्देश दिए हैं कि वे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के नए वीसा साक्षात्कार और आदान-प्रदान अतिथियों के वीसा साक्षात्कार रोक दें। इनमें सामान्य रूप से स्नातक कार्यक्रमों के लिए एफ-1, आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए जे-1 तथा पेशेवर प्रशिक्षण के लिए एम-1 वीसा शामिल हैं। साक्षात्कार पुन: शुरू करने की कोई समयसीमा नहीं बताई गई है। विभाग ने एक नियोजित समीक्षा एवं पुष्टि कार्यक्रम की घोषणा की है जिसके अंतर्गत प्रार्थियों के सोशल मीडिया की व्यापक जांच को केन्द्र में रखा गया है। इसका तत्काल प्रभाव 2025 के अंत में अमेरिका में अपना अध्ययन शुरू करने की योजना बनाने वाले छात्रों पर होगा। वैसे भी वीसा प्रक्रिया में हफ्तों या महीनों का समय लगता है, ऐसे में इस स्थगन का अर्थ ऐसे हजारों छात्रों की योजनाओं में विलंब या उनकी समाप्ति होगा जिन्होंने प्रवेश ले लिया है, पर अभी उनके वीसा साक्षात्कार नहीं पूरे हुए हैं।

अकादमिक वर्ष 2023-24 में अमेकिन संस्थानों में 1.13 मिलियन अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने प्रवेश लिया था जो अब तक सर्वाधिक है। इनमें से 71.5 प्रतिशत एशिया से थे जिनमें भारत और चीन के छात्रों की प्रमुखता थी। इनमें से अनेक छात्रों के लिए अचानक स्थगन अनिश्चितता तथा जीवन में परिवर्तन लाने वाली कॅरियर और अकादमिक योजनाओं को पटरी से उतारने वाला होगा। अमेरिकन विश्वविद्यालयों पर भी इसके काफी प्रभाव पड़ेंगे। न्यूयार्क, नार्थईस्टर्न एवं कोलम्बिया जैसे विश्वविद्यालय अपने राजस्व तथा शोध योगदानों के लिए अंतरराष्ट्रीय छात्रों की फीस से प्राप्त राजस्व पर अत्यधिक निर्भर थे। हार्वर्ड, येल और नार्थईस्टर्न विश्वविद्यालयों के छात्रों में पांचवां हिस्सा अंतरराष्ट्रीय छात्रों का है। प्रशासन से वर्तमान तनावों को देखते हुए हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने पिछले सप्ताह अंतरराष्ट्रीय छात्रों का प्रवेश बंद कर दिया है। अंतरराष्ट्रीय छात्रों की अनुपस्थिति से न केवल इन संस्थानों की वित्तीय स्थिति, बल्कि विविधता, खोज एवं वैश्विक सम्मान भी प्रभावित होगा। इससे शोध प्रयोगशालायें, स्नातक कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान प्रयास बुरी तरह प्रभावित होंगे। इस स्थगन के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सुधारों की समीक्षा को कारण बताया गया है, पर संभवत: इसके पीछे राजनीति है। यह कदम प्रशासन और विश्वविद्यालय परिसरों के बीच बढ़ते तनावों के कारण उठाया गया है जिसके केन्द्र में फिलिस्तीन-समर्थक विरोध प्रदर्शन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि, प्रशासन सुरक्षा और कठोर जांच की बात करता है, पर ऐसी घटनाओं से वैध सुरक्षा सरोकारों तथा राजनीतिक दमन के बीच की विभाजक रेखा धुंधली होती जा रही है। ट्रंप प्रशासन द्वारा अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर लगाई इस लगाम के पीछे अमेरिका में एक जटिल संतुलन बनाने का प्रयास है। एक ओर जांच और पुष्टि की इन प्रक्रियाओं को अमेरिका के वैध राष्ट्रीय हितों के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस स्थगन की व्यापक एवं अपरिभाषित प्रकृति से वैश्विक प्रतिभा के आकर्षण केन्द्र के रूप में अमेरिका के कद को धक्का लगा है। ट्रंप प्रशासन के इस कदम से अंतरराष्ट्रीय छात्र, अमेरिकन विश्वविद्यालय और उनके वैश्विक अकादमिक साझीदार अनिश्चय की स्थिति में हैं।

चीन की सैन्य रणनीति

असाधारण सैन्य क्षमताओं के दावे और आक्रामक बयानबाजी के बावजूद चीन लगातार सीधे सैनिक टकरावों से बचता रहा है। इसके बजाय वह धोखाधड़ी, राजनय और सूदखोरी के रास्ते पर चलता है।

भोपिंदर सिंह
(लेखक, सेवानिवृत्त ले. जनरल हैं)

असाधारण सैन्य क्षमताओं के दावे और आक्रामक बयानबाजी के बावजूद चीन लगातार सीधे सैनिक टकरावों से बचता रहा है। इसके बजाय वह धोखाधड़ी, राजनय और सूदखोरी के रास्ते पर चलता है। चीनी दार्शनिक सुन जू ने अपने ग्रंथ 'आर्ट आफ वार' में इन सैन्य रणनीतियों का विस्तृत वर्णन किया है जो सैकड़ों सालों से चीनी नेतृत्व की सोच और नीतियों को प्रभावित करता रहा है। उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय निबंध में असमान युद्ध का सैनिक सिद्धान्त पेश किया गया है जो आज के 'यूका'-परिवर्तनशील, अस्थिर, जटिल एवं विरोधाभासी विश्व में लगातार प्रासंगिक होता जा रहा है। वर्तमान दुनिया लगातार उथलपुथल तथा विसंगतियों की शिकार है। चीन ने अपनी सैन्य व राजनयिक रणनीति सुन जू जैसे प्राचीन चीनी सिद्धान्तकारों के विचारों के आधार पर बनाई है। विस्तारवादी चीन की रणनीति का एक प्रमुख तत्व सुन जू के लागत-प्रभावी सिद्धान्त का पालन है जिसका आधार 'बिना लड़े दुश्मन को पराजित करना' है।

चीन की सैन्य शक्तियों, आक्रामक दृष्टिकोण, छठी पीढ़ी की तकनीक और हथियारों तथा 'वुल्फ वैरियर' राजनय के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन सभी हालिया वैश्विक टकरावों व युद्धों पर सरसरी नजर डालने से स्पष्ट होता है कि टकराव में चीन की स्थिति के बारे में मचे भारी शोर-शराबे के बावजूद चीनी सैनिक जमीन पर विचित्र रूप से अनुपस्थित रहे हैं।

अमेरिकी-नाटो सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद, इस्राइल-गाजा युद्ध तथा रूस-यूक्रेन युद्ध से चीन अनुपस्थित रहा। यहां तक कि अभी हाल ही में चार दिन चले भारत-पाक टकराव में पाकिस्तान के 'इस्पाती भाई' यानी चीन के हस्तक्षेप के बारे में बहुत चर्चा हुई, लेकिन चीन ने केवल राजनयिक रूप से पाकिस्तान -समर्थक दृष्टिकोण अपनाने तक स्वयं को सीमित रखा।

भारत में खासकर 'दो मोर्चों पर युद्ध' जैसे काल्पनिक परिदृश्यों पर काफी चर्चा होती रहती है और चीन तथा पाकिस्तान सीमा पर एकसाथ टकराव से बचने के लिए समुचित प्रतिरोधक विकसित करने पर विचार होता है। पहले से ही सैनिक दबाव का सामना कर रहे भारत के समक्ष दो मोर्चों पर युद्ध गंभीर खतरा पैदा कर सकता है क्योंकि इससे संसाधनों की कमी हो सकती है तथा सैनिकों की अधिक तैनाती करनी पड़ सकती है। इसके कारण दो शक्तियों से एकसाथ युद्ध करने की भारत की क्षमता प्रभावित होगी जिनमें से एक चीन होगा।

लेकिन एक बार फिर यह भय निरर्थक सिद्ध हुआ है क्योंकि चइन के सहयोगी पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान को चीन से केवल मौखिक समर्थन मिला और उसके सैनिक कहीं पर मैदान में नहीं उतरे, जबकि इसकी आशंका बनी हुई थी। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या संपूर्ण युद्ध की चीन की इच्छा कमजोर हो गई है अथवा वह थोड़ी आक्रामक बयानबाजी के साथ अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है और अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपकरणों का प्रयोग कर रहा है।

तीन साल से अधिक समय से जारी रूस-यूक्रेन युद्ध में पुतिन के साथ खड़े होने के बावजूद चीन ने अपनी सैन्य उपस्थिति नहीं प्रदर्शित की, जबकि उत्तर कोरिया और नाटो जैसे देशों की स्थिति अलग थी जिन्होंने इस युद्ध में हथियारों और कर्मियों के रूप में अपनी सहभागिता प्रदर्शित की। इसी प्रकार उसने अफगान तालिबान के साथ मिल कर पश्चिम-विरोधी दृष्टिकोण नहीं अपनाया, जबकि अमेरिकी-नाटो सैनिकों के चले जाने के बाद वहां खाली स्थान पैदा हुआ था। हिंसा से ग्रस्त मध्य-पूर्व में भी चीन ने सभी पक्षों को खुश रखने का प्रयास किया, उसने किसी को किसी प्रकार नाराज करने का प्रयास नहीं किया।

इस प्रकार चीन के बारे में कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं उभरी कि वह इस्राइल-समर्थक, ईरान-समर्थक या यहां तक कि फिलिस्तीन-समर्थक है। उसने अच्छी-अच्छी बातें की तथा जमीनी स्तर पर नियंत्रण करने वाले पक्ष को चीनी आर्थिक सहायता का प्रस्ताव किया। इन सबसे यह तस्वीर सामने आना सुनिश्चित हुआ कि चीन सभी कट्टरपंथी, स्वेच्छाचारी और विकल्प-हीन शक्तियों के साथ है या उसने सभी दरवाजे बंद होने वाले देशों को विकलांग बना दिया।

इसके ठीक विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यपूर्व और अफगानिस्तान के बहुत खर्चीले युद्धों में भारी मात्रा में डालर खर्च किए तथा उसके अनेक सैनिक मारे गए जिनकी लाशें अमेरिका पहुंचती रहीं। उसने रूस-यूक्रेन युद्ध में भी सीधी सहभागिता नहीं की और केवल समर्थन का वादा करता रहा। इसके बजाय चीन खामोश रहा और उसने अपने संसाधनों का प्रयोग आर्थिक राजनयिक व तकनीकी प्रभाव से क्षेत्रों पर विजय के प्रयास करता रहा। लेकिन चीन ने अपने आर्थिक हित प्रभावित होने की स्थिति में कई देशों की बाहें मरोड़ने में कोई संकोच नहीं किया।

उसने श्रीलंका से कर्ज अदायगी में विलंब या विफल होने पर हंबनटोटा बंदरगाह को 99 साल के पट्टे पर ले लिया। इसके साथ ही उसने आर्थिक व साइबर दबाव डालने के लिए आस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण ढांचागत संरचनाओं पर 'वोल्ट टाइफून' हमला किया। उसने मानचित्रों के माध्यम से अपना विस्तारवाद प्रदर्शित किया तथा दक्षिण चीन सागर में कृत्रिम द्वीप बनाए। लेकिन ऐसा करने में उसने पूर्ण परंपरागत युद्ध नहीं भड़कने दिए। उसने शुन जू के सिद्धान्तों का पालन किया, 'सभी युद्ध धोखाधड़ी पर आधारित होते हैं। इसलिए सक्षम होने पर अक्षमता और सक्रिय होने पर निष्क्रियता प्रदर्शित करो। जब पास हो तब ऐसा लगे कि बहुत दूर हो, बहुत दूर होने पर उसे ललचाओ और अव्यवस्था पैदा कर उस पर हमला करो। जब वह संकेन्द्रित हो तो उसके खिलाफ तैयारी करो और जब वह मजबूत हो तो उससे बचो।

उसके जनरलों में गुस्सा पैदा कर उसे भ्रमित करो। स्वयं को कमजोर प्रदर्शित कर उसे घमंडी बनने दो।' इस रास्ते पर चलते हुए चीनी भू-राजनीतिक 'माइंड गेम' खेलने में माहिर हो गए हैं।

इससे काफी संकेत मिलते हैं, पर अंतत: भौतिक कार्रवाई बहुत कम होती है। इस प्रकार चीन अमेरिका-विरोधी दृष्टिकोण अपना कर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है, पर वह साहसी और सैनिक हस्तक्षेप से बचता है तथा ज्यादा से ज्यादा आक्रामक बयानबाजी करता है। चार दिन के भारत-पाक टकराव का नतीजा तुर्की और अजरबैजान के साथ चीन-समर्थक दृष्टिकोण बनाने में सफल हुआ, पर पाकिस्तान को सैनिक हस्तक्षेप या भारत के साथ लगी सीमा पर आक्रामक कार्रवाइयों के रूप में उसे अपने 'इस्पाती भाई' का समर्थन नहीं मिला। हालांकि, यह दिल्ली के लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

चीनी अपने सैनिक लक्ष्य चयनित रूप से देखते हैं, वे समुद्र में फिलीपीन के साथ टकराव करते हैं, भूटानी क्षेत्र में 'सलामी रणनीति' से घुसपैठ करते हैं तथा ताइवान के निकट लगातार सैनिक अभ्यास करते हैं, लेकिन वे सावधानी से अपनी आक्रामकता की सीमा नहीं तोड़ते हैं। चीन समझता है कि सैनिक हस्तक्षेप से उसका व्यापारिक, वाणिज्यिक और आर्थिक स्थायित्व प्रभावित हो सकता है जो पहले ही अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध का सामना कर रहा है। इसके अलावा देश में मांग की कमी, बेरोजगारी तथा जनसंख्या संरचना बिगड़ने के कारण वह संकटग्रस्त देशों को अपने 'कर्ज जाल' में फंसा रहा है जो उसके विस्तारवादी व वर्चस्ववादी सपने पूरा करने का सर्वाधिक प्रभावी हथियार है।

इसके अलावा चीन की एक और रणनीति तकनीकी-साइबरसुरक्षा को आक्रामक रूप देना है। इसके लिए वह हुवावेई जैसी कंपनियों का प्रयोग करता है जिनके बारे में दुनिया भर में अनेक आशंकायें पैदा हुई हैं। इस प्रकार चीन वर्तमान परिस्थितियों में सुनियोजित ढंग से 'मारो और भागो' की रणनीति पर काम कर रहा है और संभवत: वह सैनिक रूप से इसके आगे जाने का इच्छुक नहीं है। आखिरकार उसके प्राचीन सैन्य रणनीतिकार सुन जू ने यह भी कहा था कि 'सबसे अच्छी विजय वही होती है जिसके लिए कोई लड़ाई न लड़नी पड़े।' इसे देखते हुए भारत को 'दो मोर्चों पर युद्ध' जैसे विमर्श पर सावधानी से गौर करना चाहिए।

आमजन की ईश्वर व आत्मनियंत्रण की यात्रा

> "जीवन में कुछ खास नहीं होता, जीवन भटक जाता है। अधेड़ उम्र आती है, और यह एहसास होता है कि जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई।"

अजित कुमार बिश्नोई
(लेखक, आध्यात्मिक उपदेशक हैं)

यह एक आम आदमी के लिए एक सामान्य भावना है। व्यक्ति बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू करता है: मैं अलग हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, जिसका बुद्धिमत्ता से कोई लेना-देना नहीं है। मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं श्रेष्ठ हूं। अहंकार व्यक्ति के जीवन में बहुत पहले से ही प्रमुख होने लगता है। जीवन में कुछ खास नहीं होता, जीवन भटक जाता है। अधेड़ उम्र आती है, और यह एहसास होता है कि जो उम्मीद थी वह पूरी नहीं हुई।

इसका शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, झुर्रियां और धारियां अधिक स्पष्ट होने लगती हैं, और हां, बाल सफेद होने लगते हैं। मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, कुछ लोगों को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है। बुढ़ापे में याददाश्त खोने के साथ अपने हानिकारक प्रभाव दिखाने लगते हैं, जब तक कि व्यक्ति मानसिक रूप से सक्रिय न हो, बिना सोचे-समझे टीवी से चिपका न रहे। यदि बदलाव नहीं किए जाते हैं, तो यह एहसास होता है कि व्यक्ति ने खो दिया है। अनमोल मानव जीवन बर्बाद हो गया है।

लेकिन हमें हारना नहीं है, मैं उन दृढ़ निश्चयी लोगों में से एक हूं जो हार मानने से इनकार करते हैं। न ही मैं अपने करीबियों को सामान्य जीवन जीने दूंगा। मैंने क्या किया? धीरे-धीरे मेरे अंदर पूरा बदलाव आया। मैं बहुत ही सरल, स्वादहीन भोजन का आदी हो गया, जिसमें उच्च पोषण मूल्य होते हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता।

मेरे मामले में, यह लगभग तीन महीने का समय था। साथ ही, मैंने टहलने और योग अभ्यास का एक नियम शुरू किया। शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। मैंने मनोरंजन से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह और हां, हानिकारक सामग्री होती थी। धीरे-धीरे, मैं स्वस्थ मनोरंजन का आदी हो गया। और मैंने जप, दर्शन, नमन, प्रार्थना और ईश्वर को किए गए उपकारों के लिए धन्यवाद देने जैसे आध्यात्मिक अभ्यास करना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि ईश्वर मेरे जीवन में शामिल हो रहे हैं। मुझे बहुत सारे अंतर्ज्ञान मिलने लगे, जिनके जरिए ईश्वर मुझे सूक्ष्म संकेत दे रहे थे।

मैं ग्रहणशील था और समझ गया। जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों के समाधान स्पष्ट होने लगे और जीवन सहज होने लगा। मैं अब अपने प्रियजनों की मदद करने के लिए तैयार था। वे पहले से ही मेरे व्यवहार से सीख रहे थे। क्या लोग हमारे कामों से नहीं सीखते, हमारे कहने से नहीं? अगर हम जो कहते हैं वह इतना अच्छा है, तो हम खुद उसका पालन क्यों नहीं करते? यह तथ्य लगभग सभी को याद नहीं है। मैं सारा दिन झूठ बोल सकता हूं और अपने बच्चों को सच बोलने के लिए कह सकता हूं। निश्चित रूप से, जब बच्चे बेईमान हो जाते हैं तो हम निराश होते हैं। हम शिकायत करते हैं, लेकिन कौन सुन रहा है? सवाल यह है- अधिक लोग वह क्यों नहीं करते जो मैंने किया? कई बहाने हैं। मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करता है एक है। जब तक हम ईश्वर द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक यह काम नहीं करेगा। यह व्यक्तिगत अनुभव की बात है। कोई और चीज मुझे प्रेरित नहीं कर सकती। ज्ञान महान है, लेकिन इसे लागू किया जाना चाहिए। एक और समस्या दोषपूर्ण स्वभाव है, जिससे हम सभी पीड़ित हैं। हमारा स्वभाव तीन गुणों (मोड) से बना है, जो अच्छाई, जुनून और अंधकार हैं। वे हम सभी में विभिन्न अनुपातों में मौजूद हैं।

(भगवद-गीता 18.40) हमारे पास जितना अधिक जुनून होगा, भगवान की शरण में जाने के लिए खुद को राजी करना उतना ही कठिन होगा। और अगर हमारे पास बहुत अधिक अंधकार है, तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। वासना, लालच, घृणा, आदि अपने भयानक सिर उठाते रहेंगे, और हम असहाय होकर हार मान लेंगे। भगवान मदद कर सकते थे क्योंकि उनकी मदद व्यक्ति के स्वभाव को सुधारने में महत्वपूर्ण है। लेकिन भगवान की मदद करने के लिए, व्यक्ति को उनकी शरण में जाना चाहिए। मैंने जो महसूस किया है वह यह है कि न केवल मेरा स्वभाव बेहतर हो रहा है बल्कि मेरे पिछले जन्मों के अधर्मी %कर्म% मुझे अपंग नहीं कर पा रहे हैं; भगवान हर बार मेरी मदद करते हैं। (18.58) मुझे उन लोगों के लिए बुरा लगता है जो बुढ़ापे में भी अपने प्रियजनों के लिए कमाने में व्यस्त हैं। जब बुरे %कर्मफल% प्रकट होते हैं तो क्या होता है? बच्चे अपने माता-पिता को बिना किसी सहानुभूति के आईसीयू में डाल देते हैं। दुनिया इसी तरह है, हम वाल्मीकिजी के उदाहरण से नहीं सीखते हैं, जो तब बदल गए जब नारदजी ने उन्हें वास्तविकता का एहसास कराया।

उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से जाकर पूछने के लिए कहा गया कि क्या वे उनके बुरे कर्मों के कारण उनके दंड में भागीदार होंगे। वाल्मीकिजी हम सभी के लिए आदर्श होने चाहिए। तब, सब कुछ बदल जाएगा। जीवन का संतुलन बेहतर होने लगेगा क्योंकि भगवान ही सब कुछ हैं। (7.19) वे हमारे जीवन के सभी पहलुओं में मदद कर सकते हैं। भगवान हमें सुधारना शुरू करते हैं, जैसा कि केवल वे ही कर सकते हैं। भगवान जानते हैं कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, और वे हमें कैसे नुकसान पहुँचाती हैं। मेरे मामले में, यह हर दूसरे दिन किया गया और एक गलती को दूर किया गया। भगवान ने मुझे एहसास दिलाया कि अगर मुझे बेहतर जीवन चाहिए, तो मुझे इससे छुटकारा पाना होगा। और भगवान ने इसे साबित करने के लिए अगले दिन को आनंदमय बना दिया। फिर, भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम आदतन वही गलतियां न करते रहें।

भगवान अंतर्ज्ञान के माध्यम से हमें सचेत करते हैं, जैसा कि केवल वे ही कर सकते हैं। इस प्रकार हम अपने वर्तमान को बेहतर और भविष्य को और भी बेहतर बनाना शुरू करते हैं। लेकिन चूँकि हम अपने दम पर जो हासिल कर सकते हैं, उसमें सीमित हैं, इसलिए भगवान सक्रिय रूप से मदद करते हैं।

आप की बात

रक्षा क्षेत्र में प्रगति

भारतीय रक्षा क्षेत्र में पिछले दस वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र सरकार ने न केवल रक्षा बजट में वृद्धि की है, बल्कि स्वदेशी उत्पादन को भी प्राथमिकता दी है। मिसाइलों, पनडुब्बियों, जलपोतों, विमानों और ड्रोन जैसे आधुनिक हथियारों का निर्माण देश के भीतर शुरू हो चुका है। यही नहीं भारत अब रक्षा सामग्री का निर्यात भी कर रहा है जो रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि, इस प्रगति में कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने हाल ही में रक्षा परियोजनाओं की समयसीमा में हो रही देरी पर चिंता जताई। उनका यह कहना कि हथियारों और रक्षा उपकरणों की लगभग कोई भी परियोजना समय पर पूरी नहीं होतीए एक कड़वी सच्चाई है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विदेशों से की गई खरीद की आपूर्ति में देरी भी आम बात है। लेकिन इस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा रक्षा मंत्रालय और उच्च सैन्य अधिकारियों के बीच गुप्त रूप से ही की जानी चाहिए। इससे जहां एक ओर समस्याओं का समाधान आंतरिक स्तर पर हो सकेगा वहीं देश के दुश्मनों तथा हर बात पर सरकार की आलोचना करने आदी कुछ विपक्षी नेताओं को भी मौका नहीं मिलेगा। वायुसेना प्रमुख के इस कथन को रक्षा बलों की आवश्यकता के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए।

-**सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

वीरांगनाओं का स्वागत

नेशनल डिफेंस एकेडमी- एनडीए को भारतीय सशस्त्र बलों का सबसे प्रतिष्ठित त्रि-सेवा प्रशिक्षण संस्थान माना जाता है। वर्ष 2025 में जब एनडीए से पहली बार महिला कैडेट्स का बैच पासआउट हुआ तो यह केवल एक समारोह नहीं, बल्कि भारतीय सैन्य इतिहास में एक क्रांतिकारी अध्याय की शुरुआत थी। इन महिला योद्धाओं की परेड न केवल परंपराओं को तोड़ने वाली, बल्कि यह उन लाखों बेटियों के सपनों को भी नई उड़ान देने वाली बनी जो अब तक केवल पुरुषों का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र की ओर देख भी नहीं पाती थीं। वर्ष 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय ने महिलाओं को भी एनडीए प्रवेश परीक्षा में बैठने का अधिकार प्रदान किया। इसके बाद 2022 में पहली बार महिला कैडेट्स ने एनडीए में प्रवेश किया और तीन वर्षों की कठिन सैन्य, शारीरिक और शैक्षणिक यात्रा के बाद वे आज गर्व के साथ पासआउट हुई हैं। इस बैच में एक किसान की बेटी है जिसने आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा। इस बैच में 16 वीरांगनाओं को सैन्य अधिकारी बनने का अवसर मिला है। उम्मीद करनी चाहिए कि आने वाले वर्षों में सेना के तीनों अंगों के साथ ही अर्धसैनिक बलों व पुलिस में भी वीरांगनाओं की संख्या और बढ़ेगी।

- **परमवीर केसरी**, मेरठ

पाकिस्तान की असलियत

पाकिस्तान इस्लाम की छवि लगातार धूमिल करने पर लगा है। आतंकवाद के जनक पाकिस्तान ने कट्टरपंथी सोच के सहारे निर्दोष लोगों को जिहाद के नाम पर बार-बार मार कर इस्लाम को बदनाम किया है। ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने सीधे तौर पर भारत के नागरिकों के साथ ही स्वर्ण मंदिर पर निशाना लगाने का प्रयास किया ताकि भारत में सिखों को मुख्यधारा से अलग किया जा सके। पहलगाम में आतंकियों द्वारा धर्म पूछकर किए नरसंहार का उद्देश्य भी भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे भड़काना था। लेकिन भारतीय मुसलमानों ने आगे बढ़ कर उसका यह षडयंत्र विफल कर दिया है। जहां आपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकल रही तिरंगा यात्राओं में बड़ी संख्या में मुसलमान स्वत: शामिल हो रहे हैं, वहीं सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडलों में शामिल मुस्लिम नेता खासकर मुस्लिम देशों में पाकिस्तान की असलियत उजागर कर रहे हैं। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका पाकिस्तानी असलियत को उजागर करने में बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आई है। स्पष्ट है कि अब भारतीय मुसलमान पाकिस्तान के जाल में फंसने वाले नहीं हैं।

- **ललित शंकर**, गाजियाबाद

कोरोना से चिन्ता

इन दिनों देश में कोरोना संक्रमण के मामले पुन: बढ़ने लगे हैं। खबरों के मुताबिक कोरोना के केसों की संख्या 1400 के आसपास पहुंच गई है और कई मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि, विशेषज्ञ भरोसा दिला रहे हैं कि पहले जो रौद्र रूप कोरोना ने दिखाया था, इस बार यह इतना खतरनाक या जानलेवा नहीं होगा। फिर भी कोरोना का नाम सुनते ही रूह कांपना स्वाभाविक है। जब दबे पांव कोरोना दस्तक दे रहा है तो प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बन जाता है कि इस जानलेवा बीमारी से बचाव हेतु फूंक-फूंक कर कदम रखना ही उचित होगा। स्वयं की सुरक्षा ही सर्वश्रेष्ठ बचाव है। कोरोना महामारी के चलते पहले भी हमने बहुत कुछ खोया है। सरकार व चिकित्सा तंत्र को स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने तथा कोरोना संक्रमण के खतरनाक होने की संभावना से निपटने की जरूरत है। समय रहते अब पिछले सबक पर ध्यान देते हुए कमियां दूर करने की जरूरत है ताकि देश के नागरिकों को जान से हाथ न धोना पड़े और ना ही लॉकडाउन जैसी स्थितियों का सामना करना पड़े। सरकार को कोरोना के बारे में आम लोगों को सभी सूचनायें देनी चाहिए।

- **हेमा हरि उपाध्याय**, उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से **responsemail.hindipioneer@gmail.com** पर भी भेज सकते है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 89

सकारात्मक माहौल

वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 2000 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियों के परिणाम संकेत देते हैं कि राजस्व और मुनाफा वृद्धि में सुधार हुआ है। वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही की तुलना में सालाना आधार पर राजस्व में 7.6 फीसदी की वृद्धि हुई। कर पश्चात लाभ में सालाना आधार पर 12.7 फीसदी और तिमाही आधार पर 15.7 फीसदी की वृद्धि हुई। एकबारगी समायोजित कर पश्चात लाभ सालाना आधार पर 9 फीसदी और तिमाही आधार पर 13 फीसदी बढ़ा। हालांकि वृद्धि दर बहुत अधिक नहीं है लेकिन यह रुझान (जहां कर पश्चात लाभ में वृद्धि तिमाही आधार पर वार्षिक आधार की तुलना में अधिक रही) कारोबारी चक्र में बदलाव का संकेत दे सकता है।

पेट्रोलियम और बैंकिंग एवं वित्त जैसे अस्थिर क्षेत्र, जिनका प्रदर्शन औसत रहा, उन्हें बाहर कर दिया जाए तो अन्य क्षेत्रों के लिए राजस्व में वृद्धि कुल मिलाकर सालाना आधार पर 9.5 फीसदी और तिमाही आधार पर 7.1 फीसदी रही, जबकि परिचालन लाभ में सालाना 18 फीसदी की वृद्धि हुई और कर पश्चात लाभ में सालाना आधार पर 21.4 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। समायोजन के बाद कर पश्चात लाभ सालाना आधार पर 15.4 फीसदी और तिमाही आधार पर 17.6 फीसदी बढ़ा। वहीं करों का भुगतान सालाना और तिमाही आधार पर 13.9 फीसदी बढ़ा।

तेल क्षेत्र पर कच्चे तेल और गैस की कम कीमतों का असर हुआ और राजस्व में सालाना आधार पर 0.9 फीसदी का इजाफा हुआ जबकि परिचालन लाभ में सालाना आधार पर 1.5 फीसदी का इजाफा हुआ। कर पश्चात लाभ में 2 फीसदी की गिरावट आई। हालांकि, तिमाही आधार पर कर पश्चात लाभ 19 फीसदी बढ़ा। यह इस बात का संकेत है कि रिफाइनरों को बेहतर रिफाइनिंग मार्जिन से मुनाफा हुआ और वित्त वर्ष25 की चौथी तिमाही में तेल एवं गैस कीमतों में गिरावट ने भी उनकी मदद की। बैंकों की आय में सालाना आधार पर 8.8 फीसदी की वृद्धि हुई और करों में 28 फीसदी का भारी इजाफा सहन करने के बाद सालाना आधार पर उनका कर पश्चात लाभ 3.3 फीसदी बढ़ा। गिरते ब्याज दर के दौर का सकारात्मक प्रभाव अभी तक सामने नहीं आया है। वाहन कलपुर्जा, पूंजीगत वस्तु, लॉजिस्टिक्स और औषधि क्षेत्र की राजस्व वृद्धि ने सालाना आधार पर 10 फीसदी की वृद्धि का आंकड़ा पार कर लिया। अधोसंरचना और सीमेंट क्षेत्र आपस में करीब से जुड़े हुए हैं क्योंकि सीमेंट की बिक्री विनिर्माण पर निर्भर है, ऐसे में दोनों के राजस्व में तिमाही आधार पर 15 फीसदी का इजाफा हुआ और दोनों ने सालाना आधार पर एक अंक में लेकिन ऊंची वृद्धि दर्ज की।

पूंजीगत वस्तुओं के मुनाफे में सालाना आधार पर 11 फीसदी और तिमाही आधार पर 22 फीसदी का इजाफा हुआ। वहीं समायोजित कर पश्चात लाभ की बात करें तो अधोसंरचना क्षेत्र में इसमें 95 फीसदी और लॉजिस्टिक्स में 32 फीसदी का इजाफा हुआ। बिजली क्षेत्र का राजस्व 7 फीसदी बढ़ा जबकि समायोजित मुनाफा 19.7 फीसदी बढ़ा। औषधि और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र देश के व्यापार के अग्रदूत हैं। औषधि क्षेत्र का राजस्व सालाना आधार पर 13 फीसदी बढ़ा जबकि एकबारगी कर पश्चात समायोजन के बाद लाभ 61 फीसदी बढ़ा। यहां अधिकांश चिंताएं शुल्क को लेकर छिड़ी जंग से जुड़ी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र ने 8.5 फीसदी की राजस्व वृद्धि दर्ज की और कर पश्चात लाभ केवल 4.6 फीसदी रहा। मार्जिन में कमी एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि यह उद्योग बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, वीजा संबंधी चिंताएं और बदलते कारोबारी माहौल के कारण परिस्थितियां बदल रही हैं।

दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) के उद्योग में सालाना आधार पर 7.7 फीसदी की राजस्व वृद्धि देखने को मिली जबकि समायोजित कर पश्चात लाभ 5 फीसदी बढ़ा। यहां भी मार्जिन में कमी आई। वाहन उद्योग में अगर टाटा मोटर्स को बाहर कर दें (जेएलआर के कारण उसके नतीजे बहुत अस्थिर रहे) तो मुनाफे में मामूली वृद्धि देखने को मिली। जेएलआर को शमिल करें तो सालाना आधार पर कर पश्चात लाभ 24 फीसदी घट गया। दोपहिया वाहन कंपनियों का प्रदर्शन चार पहिया वाहनों से अधिक बेहतर रहा। व्यापक दृष्टि डालें तो तिमाही आधार पर तेजी मतलब हो सकता है कारोबारी चक्र में तेजी। एफएमसीजी और वाहन जैसे क्षेत्रों के परिणाम संकेत देते हैं कि खपत बहुत मजबूत नहीं थी। वैश्विक मोर्चे पर भी चिंताएं बरकरार हैं, लेकिन उम्मीद की कुछ किरणें भी हैं।

भारत को चाहिए नई पीढ़ी की उद्यमिता

हमारी नई पीढ़ी के उद्यमियों को जोखिम लेने वाला होना चाहिए। उन्हें नवाचारी भी होना चाहिए और वैश्विक स्तर पर महत्त्वपूर्ण कारोबारी भी। बता रहे हैं नितिन देसाई

देश में उद्यमिता के क्षेत्र में दो विशेषताओं का होना आवश्यक है। पहला, उसे इस कदर नवाचारी होना चाहिए कि वह अपनी कारोबारी योजना के अंतर्गत नए उत्पाद सामने लाए और नई प्रक्रियाओं को प्रस्तुत करे। दूसरा, उसकी मार्केटिंग भी वैश्विक होनी चाहिए ताकि वह भारत में विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से निपट सके और वैश्विक बाजारों में भी उनका सामना कर सके।

अतीत में ऐसा होता रहा है। लक्ष्मी सुब्रमण्यन की एक अत्यंत पठनीय किताब आजादी के पहले के दौर में उद्यमिता को लेकर उपयोगी सूचनाएं मुहैया कराती है। मुगलों के दौर में नवाचार को प्रमुखता नहीं दी जाती थी क्योंकि वह औद्योगिक क्रांति के पहले का युग था। उस समय वित्त का महत्त्व था जिस पर शासकों का बहुत अधिक नियंत्रण नहीं था। वित्तीय और कारोबारी नेटवर्क पर उद्यमियों का दबदबा था। इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं बंगाल के बैंकर जगत सेठ और सूरत के कारोबारी मुल्ला अब्दुल गफ्फूर जिनके पास जहाजों का बेड़ा था और जिनका पश्चिम एशिया के कारोबार पर दबदबा था।

भारत पश्चिम एशिया के लिए प्रमुख निर्यातक देश था, जहां दो बड़े साम्राज्य यानी सफ़वी और ओटोमन बहुत बड़े बाजार थे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मुगल काल में निजी उद्यमिता के अधीन काफी आर्थिक तेजी देखने को मिली। उस समय वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 24 फीसदी थी जो 1820 तक घटकर 16 फीसदी रह गई। पश्चिम में औद्योगिक क्रांति के विस्तार के बाद यह गिरावट बढ़ी।

उपनिवेशकाल में हालात बदले। भारतीय अर्थव्यवस्था में कारोबार, सैकड़ों की तादाद में मौजूद अनौपचारिक, असंगठित बाजारों की मदद से आकार लेता था जो उत्पाद के स्रोत और खपत के क्षेत्रों को जोड़ते थे। इन पर भारतीय बैंकरों और फाइनैंशर्स का दबदबा था और वे लेनदेन के रिकॉर्ड और फंड के लेनदेन के लिए हुंडी पर निर्भर रहते थे। औपनिवेशिक शासक इससे संतुष्ट नहीं थे लेकिन शासन के आरंभिक दिनों में वे भारतीय बैंकरों पर निर्भर थे। हालांकि, जब वैश्विक व्यापार की बात आती तो भारतीय कारोबारी ब्रिटिश कारोबारी समूहों द्वारा स्थापित एजेंसियों के बढ़ते दबदबे के कारण हाशिए पर पहुंच जाते। सुब्रमण्यन ने दो लोगों का उल्लेख किया- जमशेदजी जीजीभॉय और द्वारकानाथ टैगोर। उनके मुताबिक ये दो भारतीय कारोबारी थे जिन्होंने औपनिवेशिक दबदबे को चुनौती दी और अफीम और नील के वैश्विक व्यापार में प्रमुखता से उभरे।

औपनिवेशिक काल की एक और प्रमुख बात है औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों का उभार। सुब्रमण्यन स्टील और जलविद्युत के उत्पादन में जमशेद टाटा के नवाचारों और उनकी सक्रियता का खास उल्लेख करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने तालों, टाइपराइटर और आत्मविकास के अन्य उत्पाद तैयार करने में गोदरेज की भूमिका और बाद में किर्लोस्कर, बजाज और टीवीएस सुंदरम की भूमिकाओं को रेखांकित किया। यह उस समय हुआ जब औपनिवेशिक शासकों ने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद भारतीय कंपनियों के लिए हालात आसान बना दिए थे। मैं वालचंद हीराचंद के काम को इसमें जोड़ना चाहूंगा जिन्होंने नवाचारी इकाइयों की स्थापना की। उदाहरण के लिए आज की हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट, नौवहन कंपनी सिंधिया, विशाखापत्तनम में पोत निर्माण उपक्रम और प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स। आजादी के पहले के दौर में कई भारतीय उद्यमियों ने नई परियोजनाओं की शुरुआत की और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। मुगल काल में सरकार उद्यमों पर अधिक निर्भर थी न कि उद्यम सरकार पर। बाद में औपनिवेशिक काल में स्वदेशी उपक्रमों को सरकार से शायद ही मदद मिली। प्रथम विश्व युद्ध के समय अल्पकाल के लिए जरूर उनको जरूरी सहायता मिली।

स्वतंत्रता ने अतीत का सिलसिला पलट दिया और सरकार और निजी उपक्रमों के बीच मजबूत रिश्ता कायम हुआ। लाइसेंस राज के दौरान और उसके बाद भी ऐसा हुआ। हालांकि, सरकार ने विकास प्रक्रिया पर अपना नजरिया आरोपित करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए उत्पादन संबद्ध पहल और निजी क्षेत्र को अधोसंरचना विकास योजनाओं में शामिल करने का निर्णय, चूंकि इस क्षेत्र में सरकार का एकाधिकार है इसलिए सरकार द्वारा निवेशकों का विशिष्ट चयन आवश्यक होता है।

नवाचार की बात करें तो लाइसेंस वाले दौर में इसका उभार हुआ लेकिन मुख्य रूप से वह नए सरकारी उपक्रमों के माध्यम से सामने आया। बहरहाल, इसमें अक्सर वह गति नहीं थी जो प्रबंधन स्वामित्व के माध्यम से आती है और इनमें से कई सरकारी पहलों का अंत हो गया। निजी कारोबारी क्षेत्र पर निर्भरता में 1980 के दशक में इजाफा हुआ और निजी क्षेत्र पर वास्तविक निर्भरता की शुरुआत 1991 में लाइसेंस राज समाप्त होने के बाद हुई। इसमें वित्तीय तंत्र के जबरदस्त उदारीकरण का भी योगदान था।

हाल के दशकों में उद्यमिता के क्षेत्र में प्रमुख उन्नति सॉफ्टवेयर, कारोबारी सेवाओं और डिजिटल इकनॉमी से संबंधित कारोबारी कंपनियों की तेज वृद्धि के रूप में सामने आई। भारत में कुशल श्रमिकों की किफायती उपलब्धता ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई है। इसका एक सटीक उदाहरण है भारत में विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों की स्थापना जो वैश्विक चिप डिजाइन में 20 फीसदी की हिस्सेदार हैं। ये कंपनियां भारतीय श्रमिकों पर निर्भर हैं लेकिन भारतीय उद्यमियों पर नहीं। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि चिप निर्माण या असेंबली में स्वदेशी उद्यमों की भागीदारी का स्तर बहुत कम है। इसके कारण सरकार को औद्योगिक विकास के लिए भारी सब्सिडी आधारित नजरिया अपनाना पड़ता है। इस क्षेत्र में सरकार की संबद्धता का पैमाना 70 फीसदी पूंजीगत लागत सब्सिडी से पता चलता है जो गुजरात में बनाए जा रहे एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को दी गई। यह राशि तकरीबन दो अरब डॉलर है। इन प्रयासों के बावजूद भारत में नवाचार का पैमाना चीन, दक्षिण कोरिया और ताईवान जैसे देशों से पीछे है। कई प्रमुख उद्यमी जो अधिक नवाचारी और वैश्विक रुझान रखने वाले हैं उन्होंने रिटेल फाइनैंस जैसे अपेक्षाकृत कम प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र में विविधता लाने का निर्णय लिया है। इससे भी अधिक परेशान करने वाला रुझान है बीते कुछ दशकों में विनिर्माण निवेश में धीमी वृद्धि।

हमें भारतीय उपक्रमों को नवाचार पर केंद्रित करना होगा और वैश्विक व्यापार के साथ संबद्धता बढ़ानी होगी। उद्यमिता पर एक सरकारी नीति की स्थापना करनी होगी और ऐसी प्रतिस्पर्धा की व्यवस्था करनी होगी जो बाजार की शक्तियों की ताकत को चिह्नित करे और बाजारोन्मुखी माहौल को बढ़ावा दे बजाय कि चुनिंदा कारोबारों या क्षेत्रों को बढ़ावा देने के।

पारिवारिक स्वामित्व वाली कंपनियों में प्रवर्तकों की शक्ति पर नियंत्रण और पेशेवर तरीके से कॉर्पोरेट प्रबंधन में घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों के प्रभाव में इजाफा करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। स्टार्टअप्स को विस्तार देना होगा ताकि नए उत्पाद और प्रक्रियाएं सामने आ सकें। काफी कुछ वैसे ही करना होगा जैसा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में हो रहा है। छोटे उपक्रमों के लिए संगठित वित्तीय मदद बढ़ानी होगी। 2017 के व्यापक अध्ययन के मुताबिक अपनी वित्तीय जरूरतों के 85 फीसदी हिस्से के लिए इन्हें अनौपचारिक माध्यमों पर निर्भर रहना पड़ता है। एक ऐसी व्यापार नीति बनानी होगी जो मजबूत कारोबारी प्रोत्साहन की मदद से निर्यात का तेजी से विस्तार करे। यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विदेशी निवेश स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे और तकनीकी ज्ञान का प्रभावी प्रसार हो।

अब जबकि भारत वैश्विक विकास के मोर्चों की ओर बढ़ रहा है, इसके उपक्रमों को कम लागत वाले कुशल श्रमिक मुहैया कराने की अपनी मौजूदा भूमिका से परे जाना होगा। उन्हें महत्त्वपूर्ण नवाचार करना होगा और वैश्विक व्यापार में नेतृत्व करने वाला बनना होगा। सरकार और शेयर बाजार को जोखिम लेने वाले उद्यमियों, नवाचार करने वालों और प्रमुख वैश्विक व्यापारिक गतिविधियों की मदद करनी होगी जो भारत द्वारा प्रबंधित कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तकनीक में उन्नत बना सकें। वैसे ही जैसे पूर्वी एशिया के देशों ने सैमसंग जैसी कंपनियों या ताइवान ने सेमीकंडक्टर विनिर्माण कंपनी के साथ किया है।

बहुपक्षीय संस्थानों में बढ़े भारत की भूमिका

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मिली 2.4 अरब डॉलर ऋण पर भारत में चिंता एवं निराशा जताई गई है। यह रकम पाकिस्तान को ऐसे नाजुक समय में मिली जब भारत के साथ उसकी सैन्य झड़प हो रही थी। बाद में आईएमएफ ने एक पूरक टिप्पणी में यह जरूर माना कि इस रकम का बेजा इस्तेमाल होने या ऐसा प्रतीत होने पर उसकी छवि को झटका लग सकता है। हालांकि, आईएमएफ की तरफ से यह भी कहा गया कि 'हाल के घटनाक्रम स्थिति की समीक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं।'

आईएमएफ के कदम से कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल तो यह है कि तटस्थ रहने के लिए प्रतिबद्ध कोई बहुपक्षीय संस्था अपने दो सदस्य देशों के बीच युद्ध के दौरान ऐसा कदम क्यों उठाएगा? इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि भारत भविष्य में ऐसे कदमों की पुनरावृत्ति कैसे रोक सकता है?

असहज वास्तविकता

एक असहज करने वाली वास्तविकता यह है कि बहुपक्षीय संस्थान हमेशा तटस्थ नहीं रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान ये बहुपक्षीय संस्थान प्रायः दबदबा रखने वाले खासकर पश्चिमी देशों के हितों को अधिक तवज्जो दे रहे थे। बहुपक्षीय प्रणाली में सबसे बड़े दाता देश अमेरिका ने अक्सर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वित्तीय सहायता की दिशा अपने मित्र एवं सहयोगी देशों की तरफ मोड़ दी जबकि प्रतिद्वंद्वी देशों को इससे महरूम रखा।

शीत युद्ध के बाद भी यह रुझान बरकरार रहा। वर्ष 1994 में आईएमएफ ने मेक्सिको को 18 अरब डॉलर ऋण दिए जिनका इस्तेमाल अमेरिकी निवेशकों की रक्षा के लिए किया गया। वर्ष 2013 में आईएमएफ ने ग्रीस को आर्थिक संकट से उबारने में सक्रिय भूमिका निभाई। आईएमएफ को यूरोपीय ताकतों का भी पूरा समर्थन था। ये देश अपने पड़ोस में आर्थिक हालात बिगड़ता नहीं देखना चाहते थे। रूस और यूक्रेन के जारी मौजूदा संघर्ष में बहुपक्षीय एजेंसियों ने यूक्रेन को भारी भरकम सहायता दी है मगर रूस में उन्होंने अपना परिचालन निलंबित रखा है।

मगर, पाकिस्तान को हाल में दिया गया ऋण पुराने ढर्रे से अलग है। शीत युद्ध काल से इतर इस बार बड़े अंशधारक तटस्थ रहे हैं। दूसरी बात यह दिखी है कि आईएमएफ की तरफ से ऋण की स्वीकृति सक्रिय सैन्य टकराव के बीच आई है जो अपने आप में एक अभूतपूर्व स्थिति है।

दीपक मिश्रा

कर्ज पर टिका पाकिस्तान

पाकिस्तान लंबे समय से आईएमएफ से कर्ज लेता रहा है जो कौतूहल का विषय लग रहा है। यह आईएमएफ से कर्ज लेने वाला चौथा सबसे बड़ा देश है और पिछले 25 वर्षों में इसे 25 से 30 अरब डॉलर रकम मिली है। आईएमएफ से मिलने वाली रकम के साथ चीन और सऊदी अरब से मिलने वाली आर्थिक सहायता से पाकिस्तान कई बार आर्थिक पतन से बच गया है। आखिर आईएमएफ एक ऐसे देश को इतनी रकम कर्ज क्यों दे रहा है जिसे अर्थशास्त्रियों ने बार-बार 'खतरनाक रूप से अस्थिर' और 'एक विफल होता राज्य' करार दिया है? इसका एक कारण आईएमएफ की ढांचागत कमजोरी में दिखता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि एक प्रभावी निगरानीकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने की इसकी इच्छा इसके निर्णय को विकृत कर देती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बार-बार उधार लेने वाले देश के साथ इसका रवैया ढीला-ढाला रहा है जिससे उधारी, फिर विफल कार्यक्रम और फिर अधिक उधारी देने का चक्र शुरू हो जाता है। इस चक्र को तोड़ने के लिए एक बाहरी हस्तक्षेप की जरूरत है और भारत इसमें एक भूमिका निभा सकता है।

भारत के समक्ष विकल्प

जी-20 समूह देशों की अध्यक्षता के दौरान भारत ने वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार के लिए सार्थक कदम उठाए हैं। भारत ने एन के सिंह और लैरी समर्स की सह-अध्यक्षता में एक अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया। समूह ने बहुपक्षीय बैंकों की क्षमता बढ़ाने एवं उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए दूरगामी सुझाव दिए। ये सुझाव अब आगे बढ़ाए जा रहे हैं, खासकर विश्व बैंक इन्हें आगे ले जाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। अफसोस की बात है कि आईएमएफ इस सुधार कार्यक्रम से पीछे छूट गया था। अब एक और प्रश्न यह है कि भारत आईएमएफ जैसे संस्थानों में अपना प्रभाव कैसे बढ़ा सकता है और अपना रणनीतिक हित प्रभावी ढंग से कैसे सुनिश्चित कर सकता है? भारत इस दिशा में निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

पेशेवराना अंदाज

बहुपक्षीय संगठनों में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को प्रतिभाओं का एक बड़ा समूह खड़ा करना होगा। फिलहाल हमारे श्रेष्ठ एवं प्रतिभावान लोग इन संस्थानों में नहीं जाते हैं। इन बहुपक्षीय संगठनों में उपस्थिति एवं वहां होने वाले कार्यों को भारत रणनीतिक प्राथमिकताओं के नजरिये से नहीं देखता है। अकादमिक या निजी क्षेत्र से नियुक्तियां यदा-कदा ही होती हैं। विदेश में रहने वाले योग्य भारतीय भी कई अन्य कारणों से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। यह स्थिति अवश्य बदलनी चाहिए। हमारे प्रतिनिधियों में कूटनीतिक चतुराई के साथ तकनीकी विशेषज्ञता भी होनी चाहिए।

मतदान रणनीति पर पुनर्विचार

भारत अब काफी बदल चुका है मगर हमारे मतदान का तरीका और सहयोगी नहीं बदले हैं। हम परंपरागत रूप से दूसरे विकासशील देशों के साथ जुड़े हैं- इस पर हमारे औपनिवेशिक अतीत और गुट-निरपेक्ष नीतियों की छाप दिखती है। मगर एक वैश्विक शक्ति बनने की चाह रखने वाले भारत को अपनी नीतियों पर अवश्य पुनर्विचार करना चाहिए। ब्राजील और चीन जैसे देशों ने विकासशील एवं पिछड़े देशों (ग्लोबल साउथ) से अलग अपने तरीके से मतदान कर व्यावहारिक सोच का परिचय दिया है जो उनके राष्ट्रीय हित को परिलक्षित करते हैं। भारत को भी ऐसा ही मुद्दा आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए तभी यह वैश्विक शक्तियों के बीच विश्वास एवं आदर हासिल कर पाएगा।

वैश्विक साझेदारी मजबूत करना

भारत को ग्लोबल नॉर्थ यानी विकसित देशों के बीच अपनी बौद्धिक उपस्थिति मजबूत करनी होगी। यह ठीक है कि हम ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ा रहे हैं मगर हमारी नीतिगत बुनियाद हमारी बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं के साथ कदम नहीं मिला पा रही है। विदेश में भारत पर केंद्रित कुछ गिने-चुने केंद्र ही हैं और भारतीय विचारक संस्थाओं की देश के बाहर काफी कम उपस्थिति देखी जाती है। रणनीतिक निवेश और जी-20 के दौरान दूसरे देशों के साथ आपसी समझ बढ़ने का फायदा उठाते हुए भारत को शोधकर्ताओं और अपनी नीतियों के हिमायती लोगों का एक वैश्विक तंत्र तैयार करना चाहिए ताकि बहुपक्षीय मंचों में हमारे हितों को बढ़ावा मिले। सीमा पर गोलीबारी तो थम गई है मगर वैश्विक स्तर पर प्रभाव कायम करने की कूटनीतिक जंग जारी है। अब समय आ गया है जब भारत को न केवल सैन्य शक्ति के माध्यम से अपनी ताकत का परिचय देना चाहिए बल्कि पेशेवराना अंदाज, सिद्धांत आधारित मतदान और साझेदारियों के जरिये भी अपनी धाक जमानी चाहिए।

(लेखक इक्रियर के निदेशक एवं सीईओ हैं)

आपका पक्ष

रक्षा क्षेत्र में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय

आज का भारत अपनी सामरिक नीति में एक क्रांतिकारी परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के निर्माण और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी का निर्णय केवल नीति नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान, सुरक्षा और वैश्विक महाशक्ति बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग है। यह कदम न केवल रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता के जंजाल को तोड़ता है, बल्कि भारत को आत्मनिर्भरता के नए युग में ले जाता है। दशकों से भारत रक्षा उपकरणों के लिए विदेश पर निर्भर रहा, जिसके चलते आपूर्ति में देरी, तकनीकी बाधाएं और राजनीतिक दबावों ने हमारी सैन्य ताकत को बार-बार चुनौती दी। लेकिन अब जब युद्ध के मैदान में आधुनिक तकनीक और स्वदेशी क्षमता निर्णायक भूमिका निभा रही है, यह निर्णय समय की मांग है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम जैसे गौरवमयी उदाहरण सिद्ध करते हैं कि भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता विश्व में किसी से कम नहीं। यह निर्णय केवल रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह निवेश को आकर्षित करेगा, लाखों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेगा और तकनीकी नवाचार को नई उड़ान देगा। रक्षा मंत्रालय के इस ऐलान के बाद संबंधित कंपनियों के शेयरों में आए उछाल ने साफ कर दिया है कि देश और निवेशक दोनों इस दिशा में अटूट विश्वास रखते हैं। यह केवल एक नीति नहीं, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर एक अजेय शक्ति के रूप में स्थापित करने का संकल्प है। आत्मनिर्भर रक्षा का यह मार्ग भारत को न केवल सुरक्षित, बल्कि समृद्ध और सशक्त बनाएगा।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान और स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम गौरवमयी उदाहरण पेश कर रहे हैं

तंबाकू का नशा भी है हानिकारक

विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की थी। इस दिन दुनियाभर में तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। शिक्षा संस्थानों में भी इस पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस का मकसद तभी पूरा होगा जब लोग खुद तंबाकू से दूर रहेंगे। यह हर साल दुनियाभर में लाखों लोगों की जिंदगियों को तबाह कर देता है। भारत में भी यह आंकड़ा कम नहीं है। आज यह नशा नासूर बन रहा। नशा कोई भी क्यों न हो हमेशा बर्बाद ही करता है। तंबाकू का नशा इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तंबाकू सेवन करने वाले का स्वास्थ्य तो बरबाद होता ही है साथ ही वह दूसरों के लिए भी खतरनाक सिद्ध होता है। तंबाकू सेवन करने वाला जब खांसता है या थूकता है तो यह कई खतरनाक कीटाणुओं के दूसरों तक पहुंचने के कारण बनते हैं। इसका सेवन करने वालों को अपने परिवार की खातिर इसे छोड़ देना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को गोवा के तट पर विमानवाहक पोत 'आईएनएस विक्रांत' पर नौसेना के योद्धाओं के साथ बातचीत में कहा कि यदि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच वार्ता के लिए गंभीर है तो उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंप देना चाहिए।

चिंतन

जीडीपी की सुस्ती चिंताजनक विनिर्माण क्षेत्र में करें सुधार

राजकोषीय घाटा का लक्ष्य हसिल करना उल्लेखनीय प्रगति है, पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दर में जारी सुस्ती चिंताजनक है। पिछले कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था स्टैगनेशन सिंड्रोम की तरफ बढ़ रही है। शेयर बाजार के मजबूत प्रदर्शन करने के बावजूद भारत नए निवेश अपेक्षित मात्रा में आकर्षित नहीं कर पा रहा है। सार्वजनिक निवेश में कमी दर्ज की जा रही है, जीडीपी पर इसका असर दिख रहा है। देश में बेरोजगारी दर भी तीन से चार प्रतिशत के बीच है, जो विकसित देशों के आंकड़े के दायरे में ही है, इससे साफ है कि कामकाज के माहौल हैं, इसके बावजूद जीडीपी की नरमी चुनौती पेश कर रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी के 4.8 प्रतिशत के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.63 प्रतिशत था। राजकोषीय घाटे को काबू में रखना सरकार के लिए हमेशा बड़ी चुनौती होती है। विनिर्माण क्षेत्र के कमजोर प्रदर्शन से देश की आर्थिक वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 की जनवरी-मार्च तिमाही में धीमी होकर 7.4 प्रतिशत रही। अब पूरे वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी वृद्धि दर घटकर चार साल के निचले स्तर 6.5 प्रतिशत पर आ गई। इससे पिछले वित्त वर्ष 2023-24 की जनवरी-मार्च तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8.4 प्रतिशत रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च तिमाही में वृद्धि दर के सुस्त पड़ने से समूचे वित्त वर्ष (2024-25) में जीडीपी वृद्धि दर घटकर 6.5 प्रतिशत पर आ गई। वित्त वर्ष 2023-24 में देश की जीडीपी 9.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में वृद्धि दर 5.4 प्रतिशत रही है। जीडीपी के मामले में भारत बेशक चीन से आगे हो, लेकिन इसकी लगातार सुस्ती से भारत अपने विकसित भारत के लक्ष्य को लक्षित समय तक नहीं हासिल कर सकेगा। अभी महंगाई दर भी नियंत्रण में है और रिजर्व बैंक ने लगातार दो बाद रेपो दरों में कटौती की, ऐसे में सरकार के पास आर्थिक सुधार के अगले चरण में जाने का मौका है। उद्योग जगत से इस आशय की मांग लगातार की जा रही है। फिक्की, एसोचैम जैसे उद्योग संगठनों ने भी नए आर्थिक सुधार की वकालत की है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जल्द ही पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता है, अभी आंकड़ों में भारत ने जर्मनी को पछाड़ा है और विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का तमगा हासिल किया है, लेकिन विनिर्माण के क्षेत्र में देश उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर पा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, देश की अर्थव्यवस्था इसके पहले अक्टूबर-दिसंबर 2024 तिमाही में 6.4 प्रतिशत, जुलाई-सितंबर तिमाही में 5.6 प्रतिशत और अप्रैल-जून तिमाही में 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी। वार्षिक आधार पर वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि दर घटकर 4.5 प्रतिशत रही, जबकि 2023-24 में 12.3 प्रतिशत थी। हालांकि, कृषि क्षेत्र में 2024-25 के दौरान उत्पादन बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह 2.7 प्रतिशत था। चौथी तिमाही के दौरान विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन घटकर 4.8 प्रतिशत रह गया जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह 11.3 प्रतिशत था। भारत को विनिर्माण क्षेत्र की दिक्कतों को दूर करने की जरूरत है। वैश्विक मैनुफैक्चरिंग का हब बनने के लिए बहुत जरूरी है कि भारत विनिर्माण क्षेत्र में लगातार बेहतर प्रदर्शन करे।

जयंती विशेष
शिवप्रकाश

लोक कल्याण की प्रणेता अहिल्याबाई होल्कर

किसी भी देश का विकास शासन तंत्र की लोककल्याणकारी नीतियों और उसकी सुशासन व्यवस्था पर निर्भर करता है। भारत का इतिहास ऐसे शासकों की गाथाओं से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने देश और अपनी प्रजा के विकास व उत्थान के लिए बहुत कुछ किया। होल्कर राज-परिवार में ऐसा ही एक नाम रहा है पुण्यश्लोक महारानी अहिल्याबाई होल्कर का। उनकी कल्याणकारी नीतियां आज भी सरकारों को प्रेरित करती हैं। यह वर्ष उनके जन्म का त्रिशताब्दी वर्ष है। उनके सुशासन, लोक कल्याणकारी नीतियों एवं सांस्कृतिक उत्थान के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उनका 300 वाँ जयंती वर्ष संपूर्ण देश मना रहा है।
अहिल्याबाई होल्कर का जन्म 31 मई 1725 को अहमदनगर (अहिल्या नगर) जनपद के चौंडी गांव में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में 21 मई से 31 मई तक 10 दिवसीय अभियान लोकमाता अहिल्याबाई की स्मृति को समर्पित किया है। महारानी अहिल्याबाई होलकर के बहुआयामी व्यक्तित्व एवं उनके प्रेरणा प्रद जीवन से प्रेरित माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ग़रीब कल्याण की योजनाओं एवं "विकास से विरासत" के उनके संकल्प को जन-जन तक पहुँचाने का काम भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं। बौद्धिक संवाद, प्रदर्शनी, छात्र-छात्राओं के बीच प्रतियोगिताएँ, मंदिरों व घाटों की स्वच्छता, आरती एवं शोभायात्राओं के माध्यम से यह कार्य संपन्न हो रहा है। राज्यों की सरकारें एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा भी अनेक योजनाओं एवं संस्थाओं का नाम महारानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर किया गया है। पश्चिमी विद्वानों ने भारत के संबंध में दुष्प्रचार करते हुए कहा कि "हिन्दू शासन व्यवस्था अराजक थी।" जेम्स मिल ने लिखा था कि "भारत नैतिक रूप से खोखला और स्वार्थी समाज था जो शासन योग्य नहीं था", जबकि पश्चिमी देशों में धर्म के नाम पर भीषण अत्याचार हो रहे थे। तब भारत में महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने लोक कल्याणकारी धर्मराज्य की स्थापना की थी।

भारत में धर्म एक व्यापक कल्पना है, जो आर्थिक एवं नैतिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसी को ऋषि कणाद द्वारा वैशेषिक सूत्र में कहा गया है कि : "यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः"अर्थात जो समाज में अभ्युदय (भौतिक उन्नति), निश्रेय (आध्यात्मिक उन्नति) सिखाता है वही धर्म है। भारत में धर्म के आधार पर चलने वाले शासन को ही आदर्श शासन माना गया है, जिसमें सभी सुखी एवं निरोगी हो। ऐसा योग्य शासन प्रभु श्री राम ने दिया, रामराज्य के इसी आदर्श का पालन करने का प्रयास सम्राट विक्रमादित्य, राजा भोज, सम्राट हर्षवर्धन जैसे अनेक राजाओं ने किया। विदेशी आक्रमणों के समय इन्हीं मूल्यों की रक्षा करने के लिए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज सरीखे शासनकर्ताओं ने अपने प्राण को न्योछावर कर दिया। 300 वर्ष पूर्व महारानी अहिल्याबाई भी इन्हीं शाश्वत मूल्यों का पालन करने वाली महारानी थी। अहिल्याबाई ने अपने ससुर की मृत्यु के पश्चात 1767 में मालवा राज्य का शासन संभाला। नर्मदा के प्रति भक्ति, व्यावसायिक एवं सामरिकता से उन्होंने अपनी राजधानी नर्मदा के तट पर महेश्वर को बनाया। 28 वर्ष उन्होंने अपनी मृत्यु पर्यन्त यह शासन सत्ता संभाली। किसानों के विकास की योजनाएं, भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना, जनजातीय विकास, अपने शासन को अपराध मुक्त करना, रोजगारपरक अर्थनीति, महिला सशक्तिकरण उसके लिए महेश्वरी साड़ी का निर्माण एवं सैनिक कल्याण उनके शासन की विशेषताएँ थीं। 500 महिलाओं की सैनिक टुकड़ी का निर्माण कर एक महिला फौज भी उन्होंने तैयार की थी। महेश्वर साड़ी आज भी उनकी महिला केंद्रित उद्योग नीति को दर्शाती है। प्रजा के प्रति वात्सल्य भाव के कारण उन्हें जनता ने लोकमाता की उपाधि प्रदान की थी। अपने राज्य की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ भारत के सांस्कृतिक उत्थान में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सभी धाम, सभी ज्योतिर्लिंग, समस्त शक्ति पीठ सहित असंख्य मंदिरों का निर्माण, नदियों के घाटों का निर्माण, यात्रियों के रुकने के लिए धर्मशालाओं की व्यवस्था यह उनके द्वारा होने वाले अतुलनीय कार्यों की श्रृंखला है। हिमालय में स्थित बद्रीनाथ, केदारनाथ, काशी स्थित भगवान श्री विश्वनाथ, सोमनाथ,द्वारिका, पुरी जगन्नाथ, रामेश्वरम, सभी के पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका है। देशभर में उनके द्वारा कराए गए इन कार्यों की संख्या लगभग 12500 से अधिक है। इसका भी वैशिष्ट्य है कि यह कार्य उनको प्राप्त स्वयं की सम्पत्ति से कराया, राजकोष से नहीं।

(लेखक भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

अहिल्याबाई होल्कर
डॉ. योगिता यशवीर राघव

भारत की युगप्रवर्तक महारानी

> रानी अहिल्याबाई होल्कर ने अपने अदम्य साहस, दूरदर्शिता और परोपकारी सोच से समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी। आज हम उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं। अहिल्याबाई का शासनकाल न्याय, पारदर्शिता और प्रजा-हित के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अहिल्याबाई का नाम सबसे पहले आना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। आज जब हम बेहतर शासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण की बात करते हैं, तब अहिल्याबाई का जीवन हमें एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह कहती हैं कि सच्चे नेतृत्व में सत्ता नहीं, सेवा होती है।

भारतीय इतिहास की कालजयी गाथाओं में जो एक नाम नारी नेतृत्व, न्यायप्रिय शासन और लोककल्याण की अद्वितीय मिसाल बनकर चमकता है, वो है रानी अहिल्याबाई होल्कर जिन्होंने अपने अदम्य साहस, दूरदर्शिता और परोपकारी सोच से समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी। वे केवल एक शासिका नहीं, बल्कि एक युगप्रवर्तक थीं, जिनकी दृष्टि, सेवा भावना और निर्णय क्षमता आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। आज हम उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं, जिन्होंने न केवल मालवा राज्य को समृद्ध और सुदृढ़ बनाया, बल्कि समूचे भारत में धर्म, संस्कृति और जनकल्याण की अमिट छाप छोड़ी। महान युगप्रवर्तक रानी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती उनके अदम्य साहस, जीवन, मूल्यों, अद्वितीय नेतृत्व, न्यायप्रिय शासन, जनकल्याणकारी कार्यों और समाज कल्याण के प्रति उनके योगदान को आत्मसात व श्रद्धांजलि देने का एक ऐतिहासिक अवसर है।

एक साधारण जन्म, असाधारण यात्रा

एक साधारण बालिका से महान शासिका तक का सफर 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंडी गांव में जन्मी अहिल्याबाई का जीवन संघर्षों से प्रारंभ हुआ, लेकिन उनका धैर्य, विवेक और करुणा उन्हें अपराजेय बना गए। विवाह के बाद जब पति मालवा के शासक खंडेराव होल्कर और ससुर मल्हारराव होल्कर दोनों का निधन हो गया, तब उन्होंने 1767 में मालवा राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली। पति और ससुर के निधन के बाद, जब राज्य संकट में था, अहिल्याबाई ने न केवल मालवा राज्य की बागडोर संभाली, बल्कि अपने पराक्रम व कुशलता से उसे एक उन्नत, सुरक्षित और खुशहाल राज्य में परिवर्तित कर दिया। कठिन परिस्थितियों में नेतृत्व संभालते हुए उन्होंने शासन को सुशासन में बदल दिया। 'अहिल्याबाई होल्कर का जीवन केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानी नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए एक अमूल्य प्रेरणा है।'

सुशासन का स्वर्णिम युग

अहिल्याबाई का शासनकाल न्याय, पारदर्शिता और प्रजा-हित के लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। वे प्रजा को परिवार की तरह मानती थीं। उनके शासन मेंः कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, कृषि, व्यापार और शिक्षा को प्रोत्साहन मिला, और सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई। उनका विश्वास थाः 'राजा को अपनी प्रजा के सुख-दुख को समझकर निर्णय लेना चाहिए।' यही कारण था कि प्रजा उन्हें 'माँ अहिल्या' कहकर पुकारती थी। उनके निर्णयों में न केवल राजनैतिक बुद्धिमत्ता दिखती थी, बल्कि मानवीय संवेदना भी स्पष्ट रूप से झलकती थी।
धार्मिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण कला, संस्कृति और धर्म के पुनरुद्धार की वाहिका अहिल्याबाई का भारत के निर्माण में अनेक योगदान हैं। वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर, नासिक का त्र्यंबकेश्वर मंदिर, सभी का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने ही करवाया। देशभर में धर्मशालाएं, कुएं, घाट, और विश्राम

स्थल बनवाए जो आज भी तीर्थयात्रियों और समाज के लिए उपयोगी हैं।

महिला सशक्तिकरण की अग्रदूत

आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो अहिल्याबाई का नाम सबसे पहले आना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। अहिल्याबाई ने समाज में महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के महत्व को समझा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किया। एक विधवा होकर भी उन्होंने राजकाज को न केवल संभाला, बल्कि उसे उन्नति के पथ पर अग्रसर किया। वे उन विरली शासकों में थीं जिन्होंने स्त्रियों के हित में ठोस नीति बनाई और उसे लागू भी किया।
लोककल्याण और सुशासन का आदर्श : आज के भारत के लिए प्रेरणा अहिल्याबाई का शासन आज के 'सुशासन' (Good Governance) का एक आदर्श मॉडल है। उनकी नीतियाँ और प्रशासनिक दृष्टिकोण आज भी भारत के लिए प्रेरणादायक हैंः उन्होंने जनसुनवाई, न्यायपालिका और सार्वजनिक निर्माण को प्राथमिकता दी। उनका शासन काल सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक कुशलता का उत्कृष्ट उदाहरण रहा।

आज की पीढ़ी के लिए संदेश

अहिल्याबाई होल्कर का जीवन केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि एक प्रकाशस्तंभ है, जो हमें न्याय, करुणा और नेतृत्व के गुण सिखाता है। अहिल्याबाई का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय, करुणा, और नेतृत्व के बल पर न केवल एक राज्य, बल्कि पूरे समाज को बदलने की क्षमता होती है। उनकी दूरदर्शिता और कार्य हमें यह संदेश देते हैं कि एक व्यक्ति का संकल्प और कर्तव्यनिष्ठा पूरे समाज और राष्ट्र को बदल सकती है।
उनकी 300वीं जयंती पर हम सभी को उनके मूल्यों को आत्मसात कर, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लेना चाहिए। अहिल्याबाई का जीवन केवल इतिहास की एक कहानी नहीं, बल्कि आज के समय की आवश्यकता है। जब नेतृत्व में नैतिकता और जनहित की भावना खोती जा रही है, तब अहिल्याबाई की कार्यशैली हमें याद दिलाती है कि सच्चे नेता वे होते हैं जो सेवा को धर्म मानते हैं। उनकी 300वीं जयंती पर हमारा कर्तव्य है कि हम उनके जीवन-मूल्यों को अपनाएं—सत्य, सेवा, न्याय और करुणा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी

भविष्य के लिए प्रेरणा

आज जब हम बेहतर शासन, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक संरक्षण की बात करते हैं, तब रानी अहिल्याबाई होल्कर का जीवन हमें एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। वह कहती हैं कि सच्चे नेतृत्व में सत्ता नहीं, सेवा होती है। उनकी 300वीं जयंती पर हमें उनके आदर्शों को अपनाकर समाज और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अहिल्याबाई होल्कर की विरासत आज भी जीवंत है, और उनकी शिक्षाएँ भारत को एक न्यायपूर्ण और सशक्त राष्ट्र बनाने की प्रेरणा देती रहेंगी। 'न्याय, करुणा और सुशासन की प्रतीक रानी अहिल्याबाई भारत के लिए केवल एक शासिका नहीं, बल्कि एक आदर्श हैं, जिनकी नीतियां आज भी प्रकाशपुंज बनकर मार्गदर्शन करती हैं।'

(लेखिका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, गुरुग्राम की सहसंयोजक अध्यक्ष व के.आर. मंगलम विश्वविद्यालय, सोहना में सहायक प्रोफेसर हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

स्वयं को भगवान के चरणों में अर्पित करना ही ज्ञान है

संकलित
दर्शन

सर्व सामर्थ्य होते हुए भी अहंशून्य होकर स्वयं को भगवान के चरणों अर्पित कर देना ही ज्ञान, भक्ति और कर्म की परिपूर्णता है। भगवान के परम भक्त बालिपुत्र अंगद ने रावण की सभा में अपना एक पैर रोपकर अपने मुष्टिप्रहार से रावण के दसों मुकुटों को सिर से गिरा दिया था, वहीं चार मुकुटों को बीच में उछालकर भगवान के पास भेज दिया था। लंका से लौटकर आए अंगद से जब भगवान श्रीराम ने पूछा कि तुमने ये मुकुट कहां और कैसे प्राप्त किए, तब अंगद ने धर्म और ईश्वर से विमुख व्यक्ति की तात्विक व्याख्या की है। अंगद विनम्र भाव से कहते हैं, प्रभु! ये चार मुकुट नहीं, राजनीति के चार पद हैं, जिन पर चलकर व्यक्ति व्यवहार करते हुए भी परमार्थ को प्राप्त कर लेता है। रावण आपसे और धर्म से विमुख हो चुका है, इसलिए राजनीति के चारों चरणों (साम, दाम, दंड और भेद) का दुरुपयोग कर रहा था, इस कारण मुकुट के रूप में ये चारों उसको छोड़कर आपकी शरण में आ गए हैं। रावण ने शेष छह मुकुट जो सिर पर धारण कर रखे हैं, वे साधक के जीवन में रहने वाली षड्संपत्ति (शम, दम, उपरति, तितीक्षा, श्रद्धा और समाधान) हैं। चूंकि रावण उनका भी दुरुपयोग कर रहा था, इसलिए ये षड्संपत्ति न रहकर विकार बनकर रावण के सिर पर शासन कर रहे हैं, जो उसके विनाश के कारण बनेंगे। मेरे प्रभु! गुण तो केवल वे ही हैं, जिन्हें आपने स्वीकारा है। शेष सब अवगुण ही हैं।

सेवा का समर्पण भाव

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक राजा भोजन कर रहा था, अचानक खाना परोस रहे सेवक के हाथ से थोड़ी सी सब्जी राजा के कपड़ों पर छलक गई। राजा की त्यौरियां चढ़ गयीं। जब सेवक ने यह देखा तो वह थोड़ा घबराया, लेकिन कुछ सोचकर उसने प्याले की बची सारी सब्जी भी राजा के कपड़ों पर उड़ेल दी। अब तो राजा के क्रोध की सीमा न रही। उसने सेवक से पूछा, तुमने ऐसा करने का दुस्साहस कैसे किया? सेवक ने अत्यंत शांत भाव से उत्तर दिया, महाराज! पहले आपका गुस्सा देखकर मैनें समझ लिया था कि अब जान नहीं बचेगी। लेकिन फिर सोचा कि लोग कहेंगे की राजा ने छोटी सी गलती पर एक बेगुनाह को मौत की सजा दी। ऐसे में आपकी बदनामी होती। तब मैनें सोचा कि सारी सब्जी ही उड़ेल दूं। ताकि दुनिया आपको बदनाम न करे। और मुझे ही अपराधी समझे। राजा को उसके जबाव में एक गंभीर संदेश के दर्शन हुए और पता चला कि सेवक भाव कितना कठिन है। जो समर्पित भाव से सेवा करता है उससे कभी गलती भी हो सकती है फिर चाहे वह सेवक हो, मित्र हो, या परिवार का कोई सदस्य, ऐसे समर्पित लोगों की गलतियों पर नाराज न होकर उनके प्रेम व समर्पण का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि ये ही लोग हमारे सच्चे हितैषी और सेवक होते हैं।

अंतर्मन

आज की पाती

पांचवें गुरु अर्जुन देव को नमन

गुरु परंपरा की महिमा अपार है और भारतीय सनातन संस्कृति में गुरु का स्थान अत्यंत पूज्य माना गया है। इसी गौरवशाली परंपरा में सिख धर्म के पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का स्थान विशिष्ट है, जिन्होंने अपने जीवन और विचारों के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को सत्य, सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया। गुरु अर्जुन देव न केवल धार्मिक संत थे, बल्कि एक महान समाज सुधारक, कुशल संगठक और ज्ञान के अद्वितीय स्रोत भी थे। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मानवता की सर्वोच्चता को महत्व दिया। गुरु अर्जुन देव का जीवन शांति, सेवा और ज्ञान के आदर्शों से ओतप्रोत था। - प्रतीक सिंह, राजनांदगांव

जयंती : इतिहास की विलक्षण दीपशिखा थी अहिल्याबाई

राजनीति को सेवा, धर्म को लोक कल्याण और न्याय को करुणा का स्वरूप देने वाली तथा नारी होकर भी दक्ष प्रशासन देने वाली महारानी अहिल्याबाई होल्कर एक ऐतिहासिक महिला थी। समाज में धर्म, संस्कृति, शिक्षा, सेवा और मानवीयता के लिए उनका योगदान अतुलनीय हैं। अहिल्याबाई होल्कर एक आध्यात्मिक और नैतिक क्रांति की अद्भुत मिसाल है। यू तो भारत का इतिहास नारी शक्ति के शौर्य, वीरता एवं त्याग से भरा पड़ा है, महारानी लक्ष्मीबाई से लेकर रानी दुर्गावती तक की वीर गाथायें प्रेरणादायी हैं। भारत की नारी को जब जब प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला तब तब उसने उम्मीद से दुगुना परिणाम दिया है। वास्तव में पुरुष प्रधान इस देश में नारी सदैव सबल, प्रबल एवं कुशल रही हैं।

अशोक बजाज
(पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर)

महारानी अहिल्याबाई ने प्रतिकूलता के बावजूद समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई थी। उसका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंडी नामक छोटे से गाँव में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता मनकोजी शिंदे गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई का व्यक्तित्व ऐसा था कि जब इंदौर के महाराजा मल्हारराव होल्कर ने उन्हें देखा तो उनकी सरलता बुद्धिमत्ता और व्यवहार कुशलता से प्रभावित होकर उनके पिता मनकोजी शिंदे से अपने इकलौते पुत्र खंडेराव से शादी का प्रस्ताव रखा। दोनों परिवारों की सहमति से राजकुमार खंडेराव की शादी अहिल्याबाई से हो गई। विवाह के बाद उन्होंने जीवन के कठिन संघर्षों को सहन करते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। दुर्भाग्य से शादी के कुछ वर्षों बाद ही खंडेराव की मृत्यु हो गई और फिर ससुर महाराज मल्हारराव भी चल बसे, इसके बाद राज्य की बागडोर संभालने का दायित्व अहिल्याबाई पर आ पड़ा एक महिला वह भी विधवा का उस कालखंड में शासन करना न केवल कठिन बल्कि समाज की दृष्टि से अस्वीकार्य भी था परंतु अहिल्याबाई ने अपने अदम्य साहस और विवेक से यह साबित कर दिया कि भारत की नारी भी पुरुषों की तरह सक्षम नेतृत्व प्रदान कर सकती है। युद्ध हो या अन्य कोई चुनौती पूरे हिम्मत के साथ वह कर्तव्य पथ पर डटी रही उन्होंने जितने युद्ध लड़े सभी में दुश्मनों के छक्के छुड़ाए। महारानी अहिल्याबाई ने मालवा की राजधानी महेश्वर को एक सांस्कृतिक, व्यापारिक और न्यायप्रिय नगरी बना दिया, उनके शासन में प्रजा की आवाज सीधे रानी तक पहुंचती थी तथा वह प्रतिदिन जनता के बीच बैठकर न्याय करती थीं। उनके दरबार में विद्वानों, कलाकारों और साधुओं को सदैव उचित सम्मान और संरक्षण मिलता था।उन्होंने कृषि, व्यापार और उद्योग को प्रोत्साहित किया। साथ ही साथ शासन की कर-प्रणाली को पारदर्शी और सरल बनाया, उन्होंने स्त्री सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उनकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि वह अपने निकट संबंधियों को भी दोषी पाए जाने पर दंडित करने में नहीं हिचकती थी, वह अपनी प्रजा के लिए ममतामयी माँ थी तथा उनकी देखभाल शासिका के तौर पर नहीं बल्कि माता के समान करती थी इसीलिए लोग उन्हें "लोकमाता" शब्द से संबोधित करते थे।

करंट अफेयर

भारत शांति रक्षा का बेहद महत्वपूर्ण समर्थक : संरा

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष शांति रक्षक अधिकारी ने कहा है कि भारत शांति रक्षा का एक महत्वपूर्ण समर्थक है, जिसमें शांति रक्षकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के प्रयासों में उसकी अग्रणी भूमिका भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अवर महासचिव ज्यां-पियरे लैक्रोइक्स की यह टिप्पणी बृहस्पतिवार को संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक मीडिया सत्र के दौरान आई। वह 24-25 फरवरी को भारत द्वारा आयोजित महिला शांति सैनिकों के पहले सम्मेलन में भाग लेने के लिए नयी दिल्ली आए थे। लैक्रोइक्स ने सम्मेलन और उसके बारे में उनके आकलन के बारे में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा, "हां, मैं वास्तव में नयी दिल्ली और उस सम्मेलन में जाना चाहता था।" लैक्रोइक्स ने कहा, "सबसे पहले, क्योंकि भारत सेना और पुलिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान देने वाला देश है। यह शांति रक्षा का भी एक बहुत महत्वपूर्ण समर्थक है, भारत के पुरुषों और महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के अलावा, विभिन्न प्रयासों का समर्थन करने के मामले में भी। मैं विशेष रूप से इस बारे में सोच रहा हूं, लेकिन शांति सैनिकों के खिलाफ अपराध की जवाबदेही पर भारत की ओर से दिए गए नेतृत्व के कई अन्य उदाहरण भी हैं।"

ऑफ बीट

जेनेटिक कोड में एक ही चीज के लिए है बहुत सारे शब्द

आनुवंशिक कोड की सार्वभौमिकता सभी जीवित जीवों के बीच एक सामान्य वंशावली को इंगित करती है और यह कोड जैविक कोशिकाओं की संरचना, कार्य और विनियमन में आवश्यक भूमिका निभाता है। यह समझना कि जेनेटिक कोड कैसे काम करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और सिंथेटिक जीव विज्ञान की नींव है। लेकिन अभी भी कई अनसुलझे रहस्य हैं, जैसे प्रोटीन फोल्डिंग जैसी विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के लिए कोड क्यों महत्वपूर्ण है। आनुवंशिक कोडबुक चार अक्षरों से बने 'शब्दों' से बनी है : ए, सी, जी और यू। इनमें से प्रत्येक अक्षर एक अलग रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक के लिए है जिसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है : एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरैसिल।राइबोसोम नामक एक आणविक मशीन जीन को प्रोटीन में अनुवाद करने के लिए कोडबुक को पढ़ती है। राइबोसोम तीन अक्षर वाले शब्दों को पढ़ते हैं जिन्हें कोडोन कहा जाता है, और चार अक्षरों के 64 अलग-अलग संभावित संयोजन होते हैं जो अलग-अलग कोडोन बनाते हैं। 64 शब्दों की इस सूची में, 61 अमीनो एसिड को एनकोड करते हैं, और तीन कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को रोकने के लिए राइबोसोम को संकेत देते हैं।